राष्ट्रीय संस्करण

CopyRight - Jagran.com

सिद्धू ने दिया इस्तीफा, 34 दिन बाद खोला राज >> 4

वर्ष 3 अंक 35

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, सोमवार, 15 जुलाई 2019

दैनिक जागरण

www.jagran.com

पृष्ठ 14

सरोकार

परी के कद पर नहीं, उनके मकसद पर जाइए

बठिंडा : शारीरिक रूप से सौ फीसद दिव्यांग 22 वर्षीय परी की प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर समाज के लिए नजीर बनी हुई है। अपनी पढ़ाई के साथ दूसरे बच्चों को पढ़ाकर बुजुर्ग माता-पिता का न केवल सहारा बनी है, बल्कि भविष्य में कुछ बड़ा करने का इरादा भी रखती है। (पेज-7)

जागरण विशेष

हॉकी खिलाड़ियों को तराश रहे ओलंपियन सैयद अली

लखनऊ : लखनऊ के चंद्रभानु गुप्त मैदान में पूर्व ओलंपियन सैयद अली अपनी नर्सरी में खिलाड़ियों को इस मकसद से तराशते और निखारते हैं कि वे किसी दिन देश के लिए खेल सकें और हॉकी के फिर से सुनहरे दिन ला सकें। (पेज-13)

बाहुबली पर सवार, चांद के पार

20 घंटे के काउंटडाउन के बाद 54 दिन के सफर में रचा जाएगा इतिहास

जेएनएन, नई दिल्ली

- 6 बजकर 51 मिनट पर रविवार सुबह शुरू हुआ काउंटडाउन
- 2 बजकर 51 मिनट पर सोमवार की सुबह लांचिंग का निर्धारित समय
- 6 सितंबर को चांद की सतह पर लैंडर के उतरने का अनुमान

कागजों पर चांद के पार जाने की कल्पनाओं के बीच भारतीय वैज्ञानिकों ने असल में चांद के पार जाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इसरो के बाहुबली रॉकेट के कंधे पर सवार चंद्रयान-2 चांद के दक्षिणी ध्रुव के उस हिस्से पर कदम रखेगा, जहां अब तक किसी देश का यान नहीं पहुंचा है। छह सितंबर को रचे जाने वाले उस इतिहास का गवाह बनने के रास्ते पर कदम रख दिया गया है। रविवार सुबह छह बजकर 51 मिनट पर चंद्रयान-2 की लांचिंग की उलटी गिनती शुरू हुई। 20 घंटे के काउंटडाउन के बाद सोमवार की अलसुबह दो बजकर 51 मिनट पर इसकी लांचिंग का समय निर्धारित किया गया।

लांचिंग के बाद 54वें दिन चंद्रयान-2 चांद की सतह पर कदम रखेगा। ऐसा करते ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा, जिसने चांद की सतह पर यान उतारा है। 2008 में भारत ने चंद्रयान-1 को लांच किया था। यह एक ऑर्बिटर अभियान था। ऑर्बिटर ने 10 महीने तक चांद का चक्कर लगाया था। चांद पर पानी का पता लगाने का श्रेय भारत के इसी अभियान को जाता है।

इसरो की स्थापना के बाद से यह उसका अब तक का सबसे मुश्किल अभियान है। सफर के आखिरी दिन जिस वक्त रोवर समेत यान का लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा, वह वक्त भारतीय वैज्ञानिकों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा। खुद इसरो के चेयरमैन के. सिवन ने इसे सबसे मुश्किल 15 मिनट कहा है। इसकी सफलता के साथ ही भारत इस क्षेत्र में एक नई छलांग लगा लेगा। इस अभियान की महत्ता को इससे भी समझा जा सकता है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी अपना एक पेलोड इसके साथ लगाया है।

दक्षिणी ध्रुव है कुछ विशेष : इस अभियान के लिए चांद के दक्षिणी ध्रुव को चुनना भी सोचा-समझा फैसला है। इसरो का कहना है कि उत्तरी ध्रुव के मुकाबले यह हिस्सा छाया में रहता है। यहां पर्याप्त पानी होने की उम्मीद है। इस हिस्से में हमारी सौर व्यवस्था के शुरुआती दिनों के प्रमाण मिलने का भी अनुमान है। लैंडर विक्रम यहां दो क्रेटरों (अंतरिक्षीय पिंडों के टकराने से बने विशाल गड्ढे) के बीच के ऊंचे मैदान पर उतरेगा। उतरने की सुरक्षित और सटीक जगह लैंडर पर लगे कैमरे से मिलने वाली तस्वीरों के आधार पर चुनी जाएगी।

शुभ हो 54 दिन की चांद यात्रा पेज>>5

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो का सबसे भारी रॉकेट जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हीकल-मार्क 3 (जीएसएलवी-एमके3) चंद्रयान-2 को लेकर रवाना होगा। इसके लांचिंग की उलटी गिनती शुरू हो गई है। प्रेट्र

दुनिया की टिकी निगाहें

चंद्रयान-2 की सफलता पर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। चंद्रयान-1 ने दुनिया को बताया था कि चांद पर पानी है। अब उसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान-2 चांद पर पानी की मौजूदगी से जुड़े कई ठोस नतीजे देगा। यह अभियान चांद पर विभिन्न अणुओं में पानी की उपस्थिति का अध्ययन करेगा। इससे चांद की सतह का नक्शा तैयार करने में मदद मिलेगी, जो भविष्य में अन्य अभियानों के लिए सहायक होगा। चांद की मिट्टी में कौन-कौन से खनिज हैं और किस मात्रा में हैं, चंद्रयान-2 इससे जुड़े कई राज खोलेगा। उम्मीद यह भी है कि चांद के जिस हिस्से की पड़ताल का जिम्मा चंद्रयान-2 को मिला है, वह हमारी सौर व्यवस्था को समझने और पृथ्वी के विकासक्रम को जानने में भी मददगार हो सकता है।

करतारपुर कॉरिडोर पर झुका पाकिस्तान

बड़ा मसला ▸ भारत की ज्यादातर मांगें मानीं, बिना वीजा रोज जा सकेंगे पांच हजार श्रद्धालु

दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक में 80 फीसद मुद्दों पर सहमति

विपिन कुमार राणा, अटारी (अमृतसर)

करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर रविवार को वाघा सीमा पर हुई संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक में पाकिस्तान ने भारत की ज्यादातर मांगें मान लीं। कॉरिडोर का भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देने के साथ ही पाकिस्तान इसके लिए भी राजी हुआ कि बिना वीजा भारतीय पासपोर्ट धारक पांच हजार श्रद्धालु रोजाना करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन के लिए जा सकेंगे। ओसीआइ (ओवरसिज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्ड धारक भी बिना वीजा के जा सकेंगे। रावी नदी पर पक्का पुल बनाने पर भी वह तैयार हो गया है।

उल्लेखनीय है कि श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव के मद्देनजर दोनों देश इस कॉरिडोर को श्रद्धालुओं के लिए खोलने पर काम रहे हैं। दोनों देशों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एससीएल दास ने की। उन्होंने अटारी स्थित ज्वाइंट चेक पोस्ट पर बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु अकेले या समूह में जा सकेंगे। महत्वपूर्ण दिनों में दस हजार श्रद्धालु कॉरिडोर से पाकिस्तान जा सकें, इसके लिए भी पाक अधिकारियों से आग्रह किया गया है। इस पर किसी भी प्रकार की फीस या परमिट लगाने की चल रही चर्चाओं पर भी वहां की सरकार को दोबारा विचार करने को कहा गया है। रावी नदी पर भारत की तरफ से बनाए जा रहे पुल की आगे की एक्सटेंशन बनाने पर पाकिस्तान ने सहमति दी है। समय कम होने के कारण अगर पुल बनाने में पाकिस्तान को सहयोग की जरूरत पड़ती तो भारत करेगा। पहले पाक अपनी तरफ दरिया में तटबंध या पक्की सड़क बनाने के पक्ष में था, लेकिन इससे डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर) में बाढ़ की आशंका के दृष्टिगत भारत ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए, भारत ने पुल बनाने का आग्रह किया, जिस पर पाक अधिकारियों ने सहमति दे दी है।

- भारत के खिलाफ कॉरिडोर का इस्तेमाल नहीं होने देने का भरोसा
- पाकिस्तान रावी नदी पर पुल बनाने को हुआ सहमत, भारत करेगा सहयोग

कॉरिडोर एक नजर में

- कुल लागत : 500 करोड़।
- पैसेंजर टर्मिनल : 15 एकड़ जगह।
- पांच हजार श्रद्धालुओं के लिए 54 इमीग्रेशन काउंटर।
- दो हजार श्रद्धालुओं के बैठने की क्षमता।
- 10 बसों, 250 कारों, 250 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग।
- सुंदर लैंड स्केपिंग और आर्ट वर्क।

अटारी (अमृतसर) : करतारपुर साहिब कॉरिडोर मामले पर रविवार को वाघा सीमा (पाकिस्तान) पर भारत और पाकिस्तान के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक हुई। प्रेट्र

31 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट

दास ने बताया कि भारत द्वारा करतारपुर कॉरिडोर का काम आगामी 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। डेरा बाबा नानक-करतारपुर कॉरिडोर हाइवे पर फोरलेन का काम 50 फीसद पूरा हो चुका है। उसे भी 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। 4.19 किलोमीटर के फोरलेन पर 120 करोड़ रुपये खर्च आएगा। अभी तक इस बाबत भारत-पाक टेक्निकल कमेटी की तीन बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें कॉरिडोर के रास्ते की रुकावटों को दूर किया जा चुका है।

आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात भारत ने दोहराई, सौंपा डोजियर : दास ने बताया कि पाकिस्तान के अधिकारियों को डोजियर भी सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि कॉरिडोर के जरिये बनने वाला श्रद्धा का वातावरण किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा इस मौके का गलत उपयोग न हो। आतंकवाद पर भारत के जीरो टॉलरेंस के बारे में बताते हुए खालिस्तान समर्थित संगठन सिख फॉर जस्टिस पर लगे प्रतिबंध के नोटिफिकेशन की कॉपी भी पाक को सौंपी गई है।

खालिस्तान समर्थक अमीर नहीं था एजेंडे में : पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी विश्वास दिलवाया कि कॉरिडोर का इस्तेमाल किसी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। भारत की आपत्ति के बाद पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (पीएसजीपीसी) से गोपाल चावला को हटाने के बाद खालिस्तान समर्थक अमीर सिंह को शामिल करने पर उन्होंने कहा कि यह मामला इस बैठक के एजेंडे में नहीं था।

भारत ने अतिक्रमण का मामला भी उठाया : करतारपुर साहिब गुरुद्वारा से संबंधित जगह पर हुए अतिक्रमणों को हटाने और श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए जमीन अधिग्रहण का मामला भी भारत ने उठाया। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव दीपक मित्तल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीजीएम मुनीष रस्तोगी, गृह मंत्रालय के एडीजी मीडिया भारत भूषण बाबू, पीडब्ल्यूडी पंजाब के सचिव हुसन लाल मौजूद थे। ज्ञात हो, इस पवित्र गुरुद्वारे तक भारतीय सिखों के पहुंचने की मांग लंबे समय के बाद पूरी होने जा रही है। इसे लेकर मोदी सरकार की जमकर सराहना हो रही है।

कर्नाटक के बागी विधायक मानने को तैयार नहीं

बेंगलुरु : कर्नाटक में सियासी ड्रामे के बीच पल-पल घटनाक्रम बदल रहा है। एक दिन पहले इस्तीफा वापस लेने की बात कहने वाले कांग्रेस के बागी विधायक एमटीबी नागराज पलट गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस्तीफा वापस लेने का सवाल ही नहीं। कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि उसके विधायक लौट आएंगे और गठबंधन सरकार को बचा लेंगे। वहीं, कांग्रेस और जदएस के 15 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। अदालत ने स्पीकर से तब यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। कांग्रेस के संकटमोचक माने जाने वाले डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी से शनिवार को मुलाकात के बाद नागराज ने पार्टी के साथ बने रहने की इच्छा जताई थी। (पेज-3)

बिहार में लगातार बारिश से टूटे कई तटबंध, 19 डूबे

पटना : बिहार में उफनाई नदियों का पानी उत्तर बिहार, कोसी और सीमांचल के जिलों के गांव और शहर में घुसकर कहर ढा रहा है। रविवार सुबह मधुबनी में सात और दरभंगा में चार जगहों पर तटबंध टूट गए। इससे दर्जनों गांवों में पानी घुस गया है। विभिन्न जगहों पर 19 लोग डूब गए। एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश रविवार को थोड़ी थमी, लेकिन कोसी-सीमांचल के लोगों की मुसीबत शुरू हो गई है। सुपौल से कोसी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। शनिवार रात को कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोले जाने के कारण सुपौल-सहरसा के लगभग 12 दर्जन गांव जलमग्न हो गए थे। (पेज-7)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 4

आजम खां पर 23 और मुकदमे दर्ज करने की तैयारी

रामपुर : सपा सांसद आजम खां और जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आले हसन खां के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में किसान की जमीन जबरन जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल किए जाने का आरोप है। इसी आरोप में 23 अन्य किसानों ने भी तहरीर दी है, जिसमें अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 6

हिमाचल में बहुमंजिला इमारत ढही, जवान समेत दो की मौत

सोलन : हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कुमारहट्टी में रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुमंजिला इमारत ढह गई। इससे उसमें सेना के जवानों समेत 37 लोग दब गए। अब तक 25 को मलबे से निकाला जा चुका है। दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें सेना का एक जवान भी शामिल है।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 10

सोशल मीडिया पोस्ट्स नहीं खंगालता टैक्स विभाग

नई दिल्ली : टैक्स विभाग ने इस धारणा को गलत बताया है कि अघोषित आय का पता लगाने के लिए वह सोशल मीडिया पोस्ट्स से विदेश भ्रमण तथा महंगी खरीदारी से जुड़ी सूचना इकट्ठा करता है। सीबीडीटी के चेयरमैन पीसी मोदी ने कहा है कि विभाग को ऐसे कदम उठाने की जरूरत नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 11

हांगकांग के प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप से मांगी मदद

हांगकांग : हांगकांग में प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने लगातार दूसरे दिन चीन की सीमा से सटे शहर शा टिन में बड़ी रैली निकाली। रैली के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी लहराए गए। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर लहराकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हांगकांग को आजाद कराने और संविधान बचाने की गुहार भी लगाई।

नीट और पीजी को खत्म करने की सिफारिश

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, एमएस और एमडी में दाखिले के लिए एमबीबीएस के नतीजे ही पर्याप्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : एमडी और एमएस पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए एक बड़ी राहत पहुंचाने वाली खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने प्रस्तावित विधेयक में पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट (एनईईटी) प्रवेश परीक्षा को खत्म करने की सिफारिश की है। मंत्रालय का कहना है कि एमबीबीएस के फाइनल नतीजे ही पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पर्याप्त होंगे।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस संशोधन को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) विधेयक के संशोधित मसौदे में शामिल कर लिया गया है, जिसे मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों पर विधेयक में इन संशोधनों को शामिल किया गया है।

सूत्रों ने कहा, 'ताजा एनएमसी विधेयक में किए गए बदलावों के मुताबिक पूरे देश में साझा परीक्षा के रूप में आयोजित नेशनल एग्जिट टेस्ट (एनईएक्सटी) के आधार पर पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिले होंगे। इस तरह एमबीबीएस की फाइनल परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों को पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कोई दूसरी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी।'

इसके साथ ही छात्रों को एमबीबीएस की परीक्षा पास करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए भी किसी अन्य परीक्षा में बैठने जरूरत नहीं होगी। परंतु, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए छात्रों को अलग से प्रवेश परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा डीएम/एमसीएच कोर्स में दाखिले के लिए भी नीट सुपर स्पेशियलिटी प्रवेश परीक्षा होती रहेगी।

देश के 480 मेडिकल कॉलेजों में हर साल 80,000 छात्र एमबीबीएस पाठ्यक्रमों दाखिला लेते हैं। पीजी की 50,000 सीटें हैं, जिसके लिए हर साल लगभग 1.5 लाख छात्र प्रवेश परीक्षा देते हैं। एनएमसी विधेयक को 2017 में संसद में पेश किया गया था। लेकिन 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही यह विधेयक भी खत्म हो गया था।

इस विधेयक को लोकसभा में पेश करने किए जाने पर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भारी विरोध किया था, जिसके बाद इसे संबंधित विभाग की संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। इस विधेयक के जरिए भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) अधिनियम, 1956 के स्थान पर एनएमसी की स्थापना का प्रस्ताव है। इस अधिनियम में वैकल्पिक चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए 'ब्रिज कोर्स' का प्रस्ताव किया गया है, जिसके करने के बाद वो एलोपैथी चिकित्सा में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। संसद की समिति की सिफारिश पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'ब्रिज कोर्स' को विधेयक से हटा दिया था और कुछ अन्य बदलाव भी किए थे।

लंदन में दो खिताबी मुकाबले और दोनों में पार हुई रोमांच की हद

टाई...फिर टाई और इंग्लैंड बना चैंपियन

विश्व कप में दैनिक जागरण

अभिषेक त्रिपाठी • लंदन

दिल थाम देने और दिमाग को सुन्न कर देने वाला सुपर संडे। विश्वकप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मैच टाई हो गया। विजेता चुनने के लिए सुपर ओवर का सहारा लिया गया लेकिन वह भी टाई हो गया। इसके बाद फैसला हुआ इस नियम के आधार पर कि जिस टीम ने सबसे ज्यादा चौके- छक्के लगाए होंगे उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इसके आधार पर इंग्लैंड को विजेता (पारी और सुपरओवर को मिलाकर इंग्लैंड के 26 चौके छक्के और न्यूजीलैंड के 17) घोषित कर दिया गया। हालांकि क्रिकेट के नए बादशाह का फैसला तो हो गया, लेकिन अब चौके छक्के से विजेता चुनने वाले नियम पर बहस शुरू हो सकती है।

न्यूजीलैंड ने लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में पहले खेलते हुए आठ विकेट पर 241 रनों का स्कोर बनाया। इंग्लैंड की टीम 50 ओवर में इसी स्कोर पर ऑलआउट हो गई। इस कारण पहली बार वनडे विश्व कप का फाइनल सुपर ओवर तक गया। मैच में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के कारण इंग्लैंड को सुपर ओवर में पहले खेलने का मिला। इंग्लैंड के लिए जोस बटलर और बेन स्टोक्स ने छह गेंदों पर 15 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने सुपर ओवर की पांच गेंदों पर 14 रन बना लिए थे और उसे जीत के लिए आखिरी गेंद पर दो रन की जरूरत थी। जोफ्रा आर्चर की आखिरी गेंद पर गुप्टिल ने गेंद को डीप स्क्वॉयर लेग की तरफ खेला। जेम्स नीशाम और गुप्टिल एक रन पूरा करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़े। जेसन ने बल्लेबाजी छोर पर थ्रो फेंका और बटलर ने गुप्टिल को आउट कर दिया।

सुपर ओवर का रोमांच

इंग्लैंड : 3, 1, 4, 1, 2, 4

न्यूजीलैंड : वाइड, 2, 6, 2, 2, 1, 1 विकेट

विजेता ट्रॉफी को उठाकर खुशी जाहिर करते इंग्लैंड के कप्तान इयॉन मोर्गन। एपी

विश्व कप जीतने वाली छठी टीम : वेस्टइंडीज (02), भारत (02), ऑस्ट्रेलिया (05), पाकिस्तान (01) और श्रीलंका (01) के बाद इंग्लैंड विश्व कप जीतने वाली छठी टीम बन गई। उसे यह सम्मान 44 साल के इंतजार के बाद हासिल हुआ है। दुनिया के सबसे पुराने लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम की बालकनी में विश्व कप ट्रॉफी उठाने का सपना लिए यहां पहुंची न्यूजीलैंड की टीम को लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचकर निराश होना पड़ा। (पेज-12 देखें)

फेडरर का सपना टूटा, जोकोविक विंबलडन के बादशाह

नई दिल्ली, जेएनएन

विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने लंदन में रविवार को हुए विंबलडन के रोमांचक और चार घंटे 55 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में स्विट्जरलैंड के दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर को मात देकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

सर्बिया के गत विजेता जोकोविक ने विंबलडन का सबसे ज्यादा (08) बार खिताब जीतने वाले फेडरर को पांच सेट तक चले मुकाबले में 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12 से हराकर यह खिताब जीत लिया। मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा। कभी फेडरर आगे रहे तो कभी जोकोविक भारी पड़ते नजर आए। पहला सेट टाई-ब्रेक तक गया और नोवाक ने यह सेट 7-6 से जीता। अनुभवी फेडरर ने दूसरे सेट में एकतरफा अंदाज में 6-1 से यह सेट 26 मिनट में जीत लिया। जोकोविक ने फिर से फेडरर की राह मुश्किल की और यह सेट टाई-ब्रेक में 7-6 से जीतने में सफल हुए। इस सेट को भी फेडरर ने जोकोविक को आसानी से जीतने नहीं दिया और सेट को टाई-ब्रेक तक ले गए। यह सेट 53 मिनट तक चला। फिर चौथा सेट 53 मिनट तक चला और फेडरर ने 6-4 से यह सेट जीतकर मैच को 2-2 से बराबर कर दिया। हालांकि पांचवें सेट में दोनों दिग्गजों ने मैच को रोमांच से भरा दिया। यह सेट दो घंटे और तीन मिनट तक चला जहां जोकोविक ने टाई-ब्रेक में 7-3 से यह सेट और खिताबी ट्रॉफी अपने नाम की। यह पांचवीं सेट जोकोविक ने 13-12 से जीता।

चार घंटे 55 मिनट चला मुकाबला

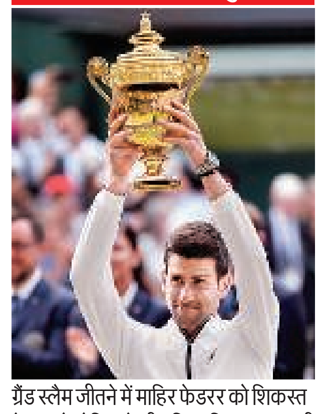

ग्रैंड स्लैम जीतने में माहिर फेडरर को शिकस्त देकर जोकोविक ने जीत लिया खिताब। एपी

जोर का झटका

तंगहाली में घिरे पाक पर 40 हजार करोड़ जुर्माने की मार

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने खनन से जुड़े एक मामले में सुनाया फैसला, बलूचिस्तान में स्थित सोने की खान का ठेका उठाने में हुई थी गड़बड़ी,

इस्लामाबाद, प्रेट्र/रायटर : कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को विश्व बैंक की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जोर का झटका दिया है। न्यायालय ने खनन से जुड़े एक विवाद में फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान पर 5.976 अरब डॉलर (40 हजार करोड़ भारतीय रुपये) का जुर्माना लगाया है। इस मामले में पाकिस्तान सरकार ने 2011 में रेको डिक परियोजना में एक कंपनी को खनन का ठेका देने से गैरकानूनी ढंग से इन्कार कर दिया था।

इस मामले में तेथ्यान कॉपर कंपनी (टीसीसी) ने चिली की खनन कंपनी एंटोफागास्टा और कनाडा के बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन के साथ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। टीसीसी की खनन की अर्जी पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान की सरकार ने अस्वीकार की थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 700 पेज के आदेश में पाक को 4.08 अरब डॉलर का जुर्माना और 1.87 अरब डॉलर का ब्याज देने को कहा है। कंपनी और पाक सरकार के बीच सात साल तक चले मुकदमे के बाद यह फैसला आया है। कंपनी ने इस विवाद में 11.43 अरब डॉलर के नुकसान का दावा करते हुए न्यायालय से उक्त धनराशि पाकिस्तान सरकार से दिलवाने की मांग की थी।

बलूचिस्तान के रेको डिक कस्बे में स्थित है दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी सोने की खदान (सोशल मीडिया)

रेको डिक का बलूची भाषा में मतलब रेतीली चोटी होता है। बलूचिस्तान में इस नाम का कस्बा वहां के चगाई जिले में है। कस्बे में स्थित रेको डिक खान में सोने और तांबे का बड़ा भंडार है। माना जाता है कि यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी सोने की खान है। टीसीसी ने सरकार से समझौते के बाद इलाके का व्यापक सर्वे कर खनन की संभावना से जुड़ी रिपोर्ट अगस्त 2010 में तैयार की। इसके बाद कंपनी ने फरवरी 2011 में खनन का ठेका लेने के लिए आवेदन किया। नवंबर 2011 में बलूचिस्तान सरकार ने आवेदन को अस्वीकार करते हुए इलाके में टीसीसी की सहायक कंपनी के कामकाज पर रोक लगा दी। पाकिस्तान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी ने कंपनी के साथ सरकार की रेको डिक डील रद कर उसे देश के कानून के खिलाफ बताया था।

कोढ़ में खाज की तरह है फैसला : अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का ताजा फैसला पाक के लिए बड़ी मुश्किल से कम नहीं है। यह मित्र देशों और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेकर जैसे-तैसे मुश्किल कम करने में लगा है। मुद्रा कोष हाल ही में छह अरब डॉलर की सशर्त मदद देने को राजी हुआ है। उसी के बाद सरकार ने कई कड़े आर्थिक फैसले लिए हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले ने उसके लिए कोढ़ में खाज की स्थिति बना दी है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूरे मामले में जांच के लिए आयोग गठन का आदेश दिया है। आयोग जांच करेगा कि रेको डिक मामले में पाक को इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस बीच टीसीसी ने पाकिस्तान सरकार के साथ मिलकर परियोजना पर काम करने का विकल्प सुझाया है। पाकिस्तान सरकार ने देर न करते हुए इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और प्रस्ताव को विचारयोग्य बताया है।

11 से 15 सितंबर तक प्रगति मैदान में दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें 135 से अधिक प्रकाशक, स्टेशनरी और कॉरपोरेट गिफ्ट उत्पादक शामिल होंगे।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 15 जुलाई 2019

न्यूज गैलरी

जेल में अपूर्वा तिवारी सीख रही टैरो कार्ड पढ़ना

नई दिल्ली : तिहाड़ जेल में कैदियों को तरह-तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ताकि जेल से बाहर निकलने के बाद वे आत्मनिर्भर हो सकें। इस क्रम में तिहाड़ जेल संख्या छह में भी महिला कैदियों को विभिन्न तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जेल सूत्रों का कहना है कि पति रोहित शेखर तिवारी की हत्या के आरोप में बंद अपूर्वा तिवारी जेल में टैरो कार्ड पढ़ने से जुड़ा कोर्स कर रही है। जेल में इनके साथ अन्य महिला कैदी भी टैरो कार्ड पढ़ना सीख रही है। बता दें कि जेल संख्या छह में महिला कैदियों के लिए फैशन स्टूडियो भी चलाया जा रहा है। यहां इन्हें अत्याधुनिक डिजाइन के वस्त्र एवं आभूषण निर्माण से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। यह स्टूडियो प्रशिक्षण से जुड़े तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। समय-समय पर कैदियों को देश के नामी डिजाइनर इनके बीच आते हैं। (जासं)

छात्राओं को स्कूल में दोबारा दाखिला दिलाए सरकार

नई दिल्ली : 9वीं कक्षा में दो बार फेल होने पर दो छात्राओं को स्कूल से निकाले जाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिए। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दोनों छात्राओं को स्कूल में दोबारा दाखिला दिलाए। याचिका पर अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। 16 वर्षीय छात्रा मोनिका एवं 15 वर्षीय दीपिका ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर की थी। छात्राओं का कहना है कि वे 9वीं में दो बार फेल हो गई थीं। इसके कारण उन्हें दिल्ली सरकार के स्कूलों में शैक्षिक वर्ष 2019-20 में पढ़ाई करने से रोक दिया गया। अशोक अग्रवाल ने पीठ के समक्ष दलील दी कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 10वीं तक सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसे में स्कूल प्रशासन उन्हें दोबारा दाखिला देने से इन्कार नहीं कर सकता। (जासं)

एयरपोर्ट पर यात्री के पास से मिले मैग्जीन, आठ कारतूस

नई दिल्ली : इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आइजीआइ) पर यात्री के पास से मैग्जीन और आठ कारतूस बरामद किए गए हैं। वह मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था। वह सुरक्षाकर्मियों को कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। आइजीआइ एयरपोर्ट थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, मूलरूप से नैनीताल निवासी पी. तिवारी विमान यात्रा के लिए 13 जुलाई को आइजीआइ एयरपोर्ट पहुंचा था। उसका एयर एशिया की उड़ान से मुंबई का टिकट बना हुआ था। चेक-इन के बाद सुरक्षा के तहत सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने उसके हैंड बैगेज की जांच की तो उसमें संदिग्ध सामान मिला। बाद में तलाशी लेने पर बैग से एक मैग्जीन और आठ कारतूस बरामद हुए। ज्ञात हो कि हवाई यात्रा के दौरान हथियार आदि ले जाने पर प्रतिबंध है। (जासं)

आइजीआइ पर दुबई से आया सोना तस्कर गिरफ्तार

नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट पर कस्टम ने सोने की तस्करी में भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर दुबई से दिल्ली आया था। उसके पास से 2.3 किलोग्राम भार की सोने की रॉड बरामद हुई है। इसकी कीमत 72 लाख रुपये है। कस्टम ने सोना जब्त कर लिया है और तस्कर से पूछताछ की जा रही है। आइजीआइ एयरपोर्ट की ज्वाइंट कस्टम कमिश्नर अनुभा सिन्हा ने बताया कि 11 जुलाई को एयर इंडिया की उड़ान दुबई से आइजीआइ एयरपोर्ट पर आई थी। इससे उतरा एक संदिग्ध भारतीय एयरपोर्ट से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। जांच के दौरान पता चला कि उसके द्वारा ले जाए जा रहे ऑटो स्पेयर पार्ट के अंदर सोना छुपाकर रखा गया है। ऑटो स्पेयर पार्ट के अंदर से सोने की रॉड बरामद हुई। पूछताछ में पता चला कि तस्कर हरियाणा का रहने वाला है और पहले भी दुबई से तस्करी कर सोना हैदराबाद ला चुका है। (जासं)

सख्ती ▶ दिल्ली के सभी होटलों व गेस्ट हाउस में आग से बचने के इंतजामों की जांच के साथ बदइंतजामी मिलने पर कार्रवाई हुई तेज

1000 गेस्ट हाउस-होटलों पर अग्निशमन विभाग की तलवार

संचालकों से आग से बचने के उपाय करने को कहा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पहाड़गंज में होटलों का नजारा। दिल्ली में करीब तीन हजार बजट होटल व गेस्ट हाउस हैं। जागरण

दिल्ली के एक हजार से अधिक गेस्ट हाउस और बजट होटलों पर अग्निशमन विभाग की तलवार लटक रही है। इनके संचालकों से प्रतिष्ठान में आग से बचने का इंतजाम करने के साथ ही भूतल व तीन मंजिल से ऊपर के निर्माण को विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं देने की बात कही है। इससे संचालकों में खलबली है। इसे लेकर संचालक दिल्ली सरकार से हस्तक्षेप कर बीच का रास्ता निकालने की मांग कर रहे हैं। इस पर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन व इमरान हुसैन ने बुधवार को होटल व गेस्टहाउस संचालकों के साथ बैठक बुलाई है।

मामला अर्पित होटल में हुए अग्निकांड से जुड़ा है। फरवरी में करोलबाग के होटल अर्पित में भीषण अग्निकांड में 17 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इसके बाद से दिल्ली के सभी होटलों व गेस्ट हाउस में आग से बचने के इंतजामों की जांच के साथ बदइंतजामी मिलने पर कार्रवाई तेज हुई है। दिल्ली सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर भूतल व तीन मंजिल से अधिक के होटल व गेस्ट हाउस को अग्निशमन एनओसी न देने की व्यवस्था की है। इसके बाद से विभाग ने होटल व गेस्ट हाउस के संचालकों को कसना शुरू कर दिया है।

दिल्ली में करीब तीन हजार बजट होटल व गेस्ट हाउस हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मानकों को पूरा न करने वाले होटल व गेस्ट हाउस को एनओसी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही इमारतों में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करने होंगे अन्यथा सिविक एजेंसियों द्वारा ऐसी इमारतों को सील किया जा सकता है। इस मामले के एक जानकार के मुताबिक दिल्ली के 30 फीसद से अधिक बजट होटल व गेस्ट हाउस भूतल व तीन तल के तय मानक का उल्लंघन करते हैं। ये इससे अधिक ऊंचे हैं। इसके अलावा अधिकांश में आग से बचने के इंतजाम नहीं हैं। बहुत कम में आपातकालीन निकास द्वार या सीढ़ियां हैं।

अकेले पहाड़गंज और करोलबाग में ही 300 से अधिक प्रतिष्ठान हैं। इनमें से 100 से अधिक होटल व गेस्ट हाउस 30 से 40 वर्ष पुराने हैं, जिनको जैसा है के आधार पर अग्निशमन विभाग का एनओसी मिलता था। इस बार उन्हें भी नए नियमों की जद में लाया गया है। इन इमारतों में आवश्यक बदलाव करते हुए नए सिरे से अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने को कहा जा रहा है। इसमें इमरजेंसी दरवाजा, हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर व फायर इंडीकेटर, दो सीढ़ियां समेत अन्य इंतजाम करने हैं। इस सख्ती से संचालकों के हाथ-पांव फूले हुए हैं।

दिल्ली होटल महासंघ के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि अक्सर एजेंसियां दुर्घटनाओं के बाद जागती हैं। 2007 में ही होटल व गेस्ट हाउस में अग्निशमन इंतजामों को लेकर कानून बनाया गया, जबकि अर्पित होटल 2009 में बना था। अगर एजेंसियां कानून का सही तरीके से पालन करातीं तो यह हादसा ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि दिल्ली बिल्डिंग प्रोविजन एक्ट के तहत 15 मीटर तक की ऊंचाई में अगर भूतल समेत चार मंजिल बनी हैं तो वह मान्य है। यह कानून 2020 तक लागू है। इसी तरह वर्ष 2000 से पहले बने होटलों को किसी भी मानकों से मुक्त रखा गया था। पुराने होटलों के अंदर न तो पानी की क्षमता बढ़ सकती है न ही किसी तरह के और बदलाव हो सकते हैं। अधिकांश बजट होटल व गेस्टहाउस 50 से 150 गज में बने हैं, जिनके ढांचे में ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता। फिलहाल अब गेंद दिल्ली सरकार के पाले में है। गुप्ता ने उम्मीद जताई कि सरकार बीच का कोई रास्ता निकालेगी।

कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियमों की अनदेखी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

देश की राजधानी होने के साथ ही दिल्ली व्यापार का हब भी बन चुकी है। यहां तमाम तरह की चीजों के निर्माण से लेकर मरम्मत और खरीद बिक्री होती है। कारोबार के लिए दिल्ली के अलग-अलग इलाके में औद्योगिक क्षेत्र विकासित किए गए हैं। वहां स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तमाम सुविधाएं जुटाने के साथ ही आग से बचाव के उपाय पर जोर दिया गया है। इसके लिए नियम-कायदे भी तय हैं। लेकिन सरकारी एजेंसियों की अनदेखी और कारोबारियों में जागरूकता के अभाव के कारण ज्यादातर जगहों पर नियमों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। इस स्थित में आग लगने पर मंजर विकराल हो जाता है और कई लोग आग की चपेट में आकर जान गवां देते हैं। हादसे के बाद एजेंसियां लकीर पीटती रह जाती हैं।

झिलमिल स्थित फ्रेंड्स कालोनी औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह जहां आग लगी थी, वह फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। वहां न तो आग से बचाव के उपाय किए गए थे और न ही मालिक ने दमकल विभाग से अनापत्ति पत्र लिया था। हर स्तर पर लापरवाही बरती गई। लिहाजा आग की घटना में दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई। अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों की बात छोड़ भी दें तो वैध व्यावसायिक क्षेत्र में भी आग से बचाव की स्थित संतोषप्रद नहीं है। दरअसल, स्थानीय निकाय को यह पता ही नहीं है कि वहां किस परिसर में कौन सा व्यवसाय चल रहा है। कई ने बगैर एजेंसी को बताए अपना व्यवसाय बदल दिया तो कुछ ने परिसर को दूसरे को किराये पर दे रखा है। इनमें से कई में तो धड़ल्ले से खतरनाक कारोबार किए जा रहे हैं। गत दिनों बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में पटाखे की अवैध फैक्ट्री में हुई भीषण घटना में कई लोगों की मौत एजेंसियों की लापरवाही का परिणाम है। स्थिति यह है कि रिहायशी इलाके में भी नियमों को ताक पर रखकर औद्योगिक इकाइयों का संचालन किया जा रहा है। एजेंसियों की ओर से सख्ती नहीं होने के कारण कारोबारी कार्रवाई से बच रहे हैं।

> व्यावसायिक परिसर हो अथवा घर, इसकी सुरक्षा के बारे में सोचना मालिक का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन आग के मामले में लोग लापरवाही कर बैठते हैं। इसके कारण आग की छोटी सी घटना बड़ा रूप ले लेती है। लोग परिसर में लगी पुरानी वायरिंग को नहीं बदलते। लिहाजा अधिक लोड के कारण शार्ट सर्किट से आग लग जाती है। वहीं, गैस के सिलेंडर भी आग की एक बड़ी वजह है। सावधानी बरत कर आग के घटनाओं को कम किया जा सकता है।
>
> **-विपिन कैंटल, निदेशक दिल्ली अग्निशमन विभाग**

राजधानी में चल रहे ज्यादातर छात्रावास, कोचिंग इंस्टीट्यूट और प्ले स्कूल इत्यादि भी आग से सुरक्षित नहीं हैं। विशेषज्ञों की मानें तो इनके लिए अलग से कोई नियम ही तय नहीं है। लिहाजा उन्हें दमकल विभाग द्वारा गैर अनापत्ति पत्र लेने की जरूरत नहीं होती। यह मालिक पर निर्भर होता है कि वह परिसर में आग से बचाव के उपाय करता है अथवा नहीं। दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2010 में आग से बचाव के लिए भवनों में नियमित व्यवस्था का प्रावधान है। अवैध इलाके में भी 15 मीटर से ज्यादा ऊंचे आवासीय भवन में आग से बचाव का उपाय किया जाना जरूरी है। वहीं व्यावसायिक तमाम परिसर में अलग-अलग मानक के मुताबिक आग से बचाव की व्यवस्था करनी होती है। लेकिन अमूमन इन नियमों के पालन में लापरवाही बरती जाती है। नियम का कड़ाई से पालन हो, इसके लिए विभागों की जवाबदेही तय नहीं है। अग्निशमन विभाग में कर्मचारियों की कमी भी इन घटनाओं को पूरी तरह से नहीं रोक पाने में एक प्रमुख कारण है। वहीं, लोगों में आग से बचाव के प्रति कम जागरूकता भी घटनाओं की एक बड़ी वजह बन रही है।

सीतारमण ने लगाया आरोप, यमुना पर दिल्ली सरकार ने नहीं किया काम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

तालकटोरा स्टेडियम में कॉपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की ओर से आयोजित पहले महासम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना पर कोई काम नहीं किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वित्त मंत्री ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार इस दिशा में काम करती तो वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट शहर का सबसे बड़ा आकर्षण बन सकता था। उन्होंने केंद्र सरकार के आगामी मिशन पर कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक प्रत्येक नागरिक को घर मिले।

उन्होंने कहा कि गरीब व मध्यम वर्ग को किफायती घर उपलब्ध करवाने के लिए ही इस बार के बजट में 45 लाख रुपये तक के होम लोन पर 3.5 लाख रुपये की कर छूट दी गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व मंत्री विजय गोयल ने कहा कि उपराज्यपाल के साथ उन्होंने बैठक की थी। इसके बाद उपराज्यपाल ने डीडीए को पुनर्निर्माण से संबंधित नीतियों में संशोधन करने के आदेश दे दिए हैं और शीघ्र ही डीडीए सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का सर्वे करेगा। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक सर्वे में सभी सोसाइटी की वर्तमान स्थिति भूखंड का आकार, फ्लैट की संख्या और नागरिक सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। गोयल ने कहा कि उपराज्यपाल के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उन सोसाइटी का पुनर्निर्माण होगा, जिनमें 66 सदस्य या ज्यादा पुनर्निर्माण की मांग करेंगे। गोयल ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे लोगों को अपनी समस्याओं पर संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह महासम्मेलन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज फेडरेशन को हो रही विभिन्न समस्याओं का हल निकालने हेतु आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, सांसद आरके सिन्हा, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी और हंसराज हंस भी मौजूद रहे।

तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित महासम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य भाजपा नेता। इस दौरान वित्त मंत्री ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला। जागरण

जेवर एयरपोर्ट के लिए प्री बिड कांफ्रेंस आज

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्री बिड कांफ्रेंस सोमवार को नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में होगी। कंपनियों की ओर से दी गई क्वेरी का इस कांफ्रेंस में जवाब दिया जाएगा। कांफ्रेंस में उन कंपनियों के भी शामिल होने की उम्मीद है, जिन्होंने अभी तक बिड डॉक्यूमेंट नहीं लिया है। लेकिन वे एयरपोर्ट की बिड में शामिल होने की इच्छुक हैं।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नोएडा इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड (नियाल) ने तीस मई को वैश्विक बिड जारी की थी। अभी तक देश-विदेश की पंद्रह कंपनियों ने एयरपोर्ट की बिड खरीदी है। कंपनियों की ओर से बिड पर क्वेरी दी गई थीं। तीस अक्टूबर तक बिड खरीद व जमा कराई जा सकती है। छह नवंबर को टेक्नीकल बिड खुलेगी और 29 को फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी।

नियाल के नोडल असफर शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि क्वेरी का जवाब देने के लिए नियाल सोमवार को प्री बिड कांफ्रेंस करने जा रहा है। यह कांफ्रेंस नॉलेज पार्क के इंडिया एक्सपो मार्ट में रखी गई है। इस कांफ्रेंस में उन कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिन्होंने क्वेरी दी है। इसके अलावा अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं जो एयरपोर्ट की बिड में शामिल होने की इच्छुक हैं।

ब्लॉक कमेटियों पर है रार शीला ने किया इन्कार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

ब्लॉक समितियों को भंग करने तथा जिला एवं ब्लॉक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने किसी भी रार से साफ इन्कार किया है। उनका कहना है कि उन्हें किसी का कोई विरोध पत्र भी नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने सभी नियुक्तियों को नियमों के तहत बताया है।

दिल की बीमारी के चलते करीब दस दिन तक एस्कॉर्ट अस्पताल में उपचाराधीन रहीं शीला रविवार को घर लौट आईं। वापसी के साथ उनसे मिलने-जुलने वालों का सिलसिला भी शुरू हो गया। पार्टी से जुड़े कई नेताओं ने उनसे मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी और संगठन में बदलाव के मुद्दे पर चर्चा की। शीला ने प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया और प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र कोचर के साथ भी बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव को लेकर बातचीत की और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी रणनीति साझा की।

बाद में दैनिक जागरण से बातचीत में शीला ने कहा कि 280 ब्लॉक कमेटियों को भंग करने तथा 14 जिला एवं 280 ब्लॉक पर्यवेक्षक नियुक्त करने को लेकर उन्हें न तो प्रदेश प्रभारी पीसी चाको का ही कोई पत्र मिला है और न ही तीनों कार्यकारी अध्यक्षों का। जब पत्र मिलेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा और उसके बाद ही उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकेगी। शीला ने यह भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने हाल फिलहाल में जो फैसले लिए हैं, सभी सही हैं और नियम कायदों के मद्देनजर ही लिए गए हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि अभी दो-तीन दिन वह घर पर ही आराम करेंगी और उसके बाद ही प्रदेश कार्यालय जाकर बैठक वगैरह लेंगी। गौरतलब है कि ब्लॉक समितियों को भंग करने और जिला एवं पर्यवेक्षक नियुक्त करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है।

> **चाको के पत्र पर उठे सवाल**
>
> शीला दीक्षित समर्थकों ने शनिवार को चाको द्वारा शीला को लिखे गए पत्र की प्रमाणिकता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विभिन्न वाट्सएप ग्रुपों पर जो पत्र चल रहा है, उस पर चाको के हस्ताक्षर ही नहीं हैं

मुगल विद्वान के मकबरे के पास बनीं आवासीय इमारतों के खिलाफ अर्जी

▶ सुप्रीम कोर्ट में दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती

नई दिल्ली, आइएएनएस: मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान-ए-खाना के मकबरे के आसपास स्थित दो आवासीय इमारतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये इमारतें मकबरे के 100 मीटर के दायरे में आती हैं, जो 'प्राचीन स्मारक व पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958' का उल्लंघन है। मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीन ईस्ट में है। इससे कुछ ही दूरी पर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और हुमायूं का मकबरा स्थित है।

यह याचिका एक वकील ने दायर की है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में स्थित संरक्षित स्मारकों के आसपास हो रहे निर्माण के खिलाफ कानून बनाने की मांग की थी। जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में याची के वकील सुनील फर्नांडीस ने दावा किया कि इस मामले में याचिकाकर्ता का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। वास्तव में इस मामले को देश की अनमोल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों के तहत देखा जाना चाहिए। अधिनियम 1958 की धारा 20ए में साफ कहा गया है कि संरक्षित स्मारक के सौ मीटर के दायरे में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बनाम नरेंद्र आनंद 2012 के एक मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने संरक्षित स्मारक जंतर-मंतर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित कनॉट प्लेस की जनपथ लेन पर निर्माण की वैधता पर सवाल उठाया था। दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान को कोर्ट मित्र के रूप में नियुक्त किया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 2012 के फैसले में साफ कहा गया है कि संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होने वाले 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन एएसआइ ने धारा-20 ए की गलत व्याख्या करते हुए संरक्षित स्मारक के अंदर से 100 मीटर दायरे को गिना है।

आए बादल पर नहीं हुई बारिश

देश के कई हिस्सों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दूसरी ओर राजधानी के साथ मानसून की आंख मिचौली का खेल जारी है। ऐसे में जब रविवार को कुछ देर के लिए काले-काले बादल घिरे तो मौसम खुशनुमा हो गया। इससे लोगों में बारिश की आस जगी। हालांकि इस बार भी लोगो की उम्मीदों पर पानी फिर गया। संजय

आज से ओवर स्पीड वाले भारी वाहन स्वामियों की जेब होगी ढीली

जागरण संवाददाता, नोएडा : नोएडा-ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेस-वे ओवर स्पीड में दौड़ने वाले भारी वाहन स्वामियों की आज से जेब ढीली होगी। यातायात विभाग ओवर स्पीड के साथ स्पीड गवर्नर का भी चालान करेगा। विभाग की कार्रवाई की जद में स्कूल बसें भी शामिल की गई हैं। भारी वाहन स्वामियों को ओवर स्पीड के एक हजार रुपये के साथ 5 हजार रुपये स्पीड गवर्नर डिवाइस के काम नहीं करने पर जुर्माना देना होगा। पुलिस अधीक्षक यातायात अनिल कुमार झा ने सभी कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दे दिया है।

यातायात विभाग का कहना है कि एक्सप्रेस-वे पर ओवर स्पीड वाहनों की वजह से हादसों में इजाफा हो रहा है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी वाहनों के साथ स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर डिवाइस लगाना अनिवार्य है। स्पीड गवर्नर डिवाइड लगे होने पर वाहन निर्धारित गति से अधिक नहीं दौड़ सकते हैं। एक्सप्रेस-वे पर स्कूल बसों की गति सीमा 40 किमी प्रति घंटा निर्धारित है। इसी तरह एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहनों के लिए 80 किमी प्रति घंटा की गति निर्धारित है।

जल संरक्षण

पानी नहीं होने से चार सौ साल पुराने कुएं में लोगों ने डाल दिया था कचरा और मलबा, दिल्ली के पुरातत्व विभाग के सहयोग से आगा खां ट्रस्ट करा रहा इसका संरक्षण

चिड़ियाघर स्थित मुगलकाल के कुएं से बह निकली जलधारा

किशन कुमार, नई दिल्ली

चार सौ साल पुराना मुगलकालीन कुआं इतिहास बन चुका था। पानी नहीं होने की वजह से जिसमें किसी ने कचरा फेंका तो किसी ने मिट्टी डाल दी। नतीजतन इस कुएं से पानी मिलने की उम्मीदें लगभग धूमिल हो चुकी थीं। लेकिन संरक्षण के कार्य से इस कुएं में एक बार फिर जलधारा फूट गई है। यह कुआं चिड़ियाघर में अजीमगंज की सराय में मौजूद। कुएं की गहराई करीब 55 फीट और चौड़ाई 15 फीट के करीब है। इसमें लगे पत्थरों से इतिहासकार यह अनुमान लगा रहे हैं कि यह कुआं 16वीं शताब्दी में बनाया गया होगा।

आगा खां ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतिश नंदा ने बताया कि चिड़ियाघर में मौजूद सराय के संरक्षण के दौरान पानी की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसे में जंगली क्षेत्र होने के कारण यहां पानी का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच यह कुआं नजर आया, जो कि मलबे से भरा हुआ था। इसे जीवंत करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन ट्रस्ट ने इसे स्वीकार किया। इसके बाद दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग के सहयोग से इसके संरक्षण का कार्य शुरू हो गया।

चिड़ियाघर स्थित मुगलकालीन कुएं से मलबा निकालते श्रमिक। इतिहासकारों का अनुमान है कि यह कुआं 16वीं शताब्दी में बनाया गया होगा। फोटो : सौजन्य चिड़ियाघर

15 लोगों ने एक माह में पाई सफलता : ट्रस्ट से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि करीब 16वीं शताब्दी के इस कुएं को जीवंत करने में तकरीबन एक माह का समय लग गया। इस बीच 15 लोग विशेष रूप से इसी के संरक्षण में जुटे रहे। इन लोगों ने कुएं पर एक तख्ता डालकर, बाल्टी और रस्सी के जरिये मलबा बाहर निकाला। बड़ी मात्रा में मलबा बाहर निकालने के बाद इसमें जलधारा फूट गई। हालांकि, शुरुआत में इसमें गंदा पानी निकला था, लेकिन बाद में कुछ साफ हुआ।

कुएं की दीवारों में लगे हैं मुगलकालीन पत्थर : इस कुएं में मुगलकाल के पत्थर लगे हुए हैं। हालांकि, समय के साथ पुराने होने के कारण ये पत्थर अब झड़ने लगे हैं। कुएं के ऊपरी भाग में कुछ पत्थर अपना अस्तित्व खो चुके हैं। वहीं, कुएं के निचले भाग में अधिकांश पत्थर अच्छी खासी हालत में हैं। ऐसे में उम्मीद है कि यदि आगे संरक्षण का काम होता है तो इस कुएं की स्थिति और भी सुधर सकती है।

संरक्षण के बाद ही पीने योग्य होगा कुएं का पानी : ट्रस्ट के प्रयास से इस कुएं में भले ही पानी आ गया है, लेकिन इसके पानी को पीने योग्य बनाने के लिए अभी और संरक्षण की जरूरत है। यदि ऐसा हुआ तो भविष्य में यह कुआं चिड़ियाघर में पानी का बड़ा स्रोत बन सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में जल संरक्षण से जुड़े लोग इसे एक बड़ी उम्मीद की तरह देख रहे हैं।

भूमिहीनों को आवंटित भूमि का मिलेगा मालिकाना हक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीनों को आवंटित की गई भूमि का मालिकाना हक जल्द ही दिलवाएगी। इस मुद्दे पर दिल्ली अनुसूचित जाति/जनजाति मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हाल ही में एक बैठक भी की थी, जिसमें मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, डीएम एवं ग्राम सभा के प्रतिनिधि मौजूद थे।

गौतम ने बताया कि वर्ष 1970 से 1989 के मध्य बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत गरीबों के विकास व उत्थान के लिए लगभग 12 हजार जरूरतमंद परिवारों को भूमि आवंटित की गई थी। इनमें से 7200 परिवारों को अपने मालिकाना हक के लिए लड़ाई आज भी लड़नी पड़ रही है। ये लोग लंबे समय से सरकार से भूमिधर होने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों की इस मांग पर गंभीरता से विचार किया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के गांव के मूल निवासी भूमिहीन परिवारों को प्रति परिवार एक एकड़ जमीन खेती बाड़ी कर जीवन स्तर उठाने हेतू आवंटित की गई थी। भूमिहीन परिवारों की मांग थी कि जब सभी राज्यों में उक्त कार्यक्रम में बांटी गई जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया जा चुका है तो दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। कई वर्षों से ये लोग अधिकारियों एवं मंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण वे कृषि से जुड़े मुआवजे का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं।

मुख्य सचिव ने इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी डीएम को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द तय सीमा के तहत इस मुद्दे को निपटाया जाए। उनका कहना था कि जिनके लिए ये जमीनें दी गईं अगर उन परिवारों को ही इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे सिविल सर्विसेज में होने का कोई फायदा नहीं। इस पर हैरानी जताते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है।

100 करोड़ की वैट चोरी में 12 फर्मों के खिलाफ हरियाणा में केस दर्ज किया गया है। सेल्स टैक्स विभाग ने उन 215 फर्मों की सूची भी पुलिस को दी जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों से इनपुट क्रेडिट का लाभ लिया।

मोदी के अधूरे मिशन कश्मीर को पूरा करने में जुटे शाह

नीलू रंजन, नई दिल्ली

- अनुच्छेद 370, 35ए और परिसीमन जैसे मुद्दों के बीच आम जनता का दिल जीतना पहली प्राथमिकता
- पहली बार सुनिश्चित किया जा रहा है आम जनता तक केंद्रीय योजना का लाभ पहुंचाना

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधूरे मिशन को पूरा करने में जुट गए हैं। वैसे तो इस मिशन के तहत शाह के सामने अनुच्छेद 370, 35ए, सीटों के परिसीमन समेत कई मुद्दे हैं, जिन पर फैसला लिया जाना है। लेकिन फिलहाल उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर आम कश्मीरियों का दिल जीतने की है। हालत यह है कि आम कश्मीरियों के जीवन को प्रभावित करने वाली छोटी-बड़ी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की निगरानी शाह खुद कर रहे हैं।

वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने दो साल पहले ही लालकिले से कश्मीरियों का दिल जीत कर सात दशक पुरानी समस्या के समाधान की घोषणा की थी। कश्मीर में विकास की गति तेज करने के लिए 80 हजार करोड़ का विशेष पैकेज भी दिया था। लेकिन आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद में जकड़े राज्य प्रशासन के कारण जनता योजनाओं के लाभ से वंचित रह गई है। अमित शाह ने गत डेढ़ माह में जरूरतमंदों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया।

कश्मीर मामलों से जुड़े गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कश्मीर घाटी में विधवाओं को पेंशन नहीं पहुंचती थी, लेकिन आज की तारीख में एक-एक विधवा के खाते में उसकी पेंशन पहुंचने लगी है। इसी तरह हर बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन पहुंचने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली समेत बड़े महानगरों

अमित शाह (फाइल फोटो)

में इलेक्ट्रिक बसें भले ही अभी तक सपना हो, लेकिन श्रीनगर में न सिर्फ 30 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गई हैं, बल्कि चलने भी लगी हैं। इसी तरह श्रीनगर में प्रशासन की तरफ से हर जरूरतमंद दिव्यांग के घर तक व्हीलचेयर पहुंचाई जा रही है।

नवनिर्वाचित पंच, सरपंच और शहरी निकायों के प्रतिनिधि ही आम कश्मीरियों का दिल जीतने में सबसे ताकतवर जरिया साबित हो रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में चुने गए 40 हजार जनप्रतिनिधियों के सहारे गांव-गांव, मुहल्ले-मुहल्ले विकास की बयार बहाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन स्थानीय निकायों के खाते में केंद्र की ओर से सीधे 700 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं और चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक 1500-1500 करोड़ रुपये की दो किस्त और भेज दी जाएगी।

पंचायत और स्थानीय निकाय अपनी जरूरत के मुताबिक स्थानीय स्तर पर योजनाएं बना रहे हैं और उन्हें क्रियान्वित भी कर रहे हैं। कश्मीर दौरे के दौरान अमित शाह ने सभी अधिकारियों को दो दिन गांव में बिताने का निर्देश दिया था। इस दौरान अधिकारियों ने न सिर्फ विकास योजनाओं का जायजा लिया, बल्कि पहली बार चुने गए पंचों-सरपंचों को योजनाओं को तैयार करने की ट्रेनिंग भी दी। गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन योजनाओं को लागू होने के बाद अगले छह महीने में कश्मीर में गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू हो जाएगी।

विकास की बयार के साथ-साथ आम जनता का दिल जीतने के लिए शाह ने कानून का शासन घाटी में पूरी तरह स्थापित करने की मुहिम छेड़ दी है। इसके तहत 70 सालों में पहली बार जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का गठन किया गया। एसीबी अब जम्मू-कश्मीर बैंक से लेकर हर विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर रही है। साथ ही भ्रष्टाचार से बनाई गई संपत्तियों की जब्ती का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसके तहत वरिष्ठ नौकरशाहों व राजनेताओं द्वारा किये गए अवैध कब्जे हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। अभी तक आंतकवाद के खिलाफ लड़ाई की आड़ में भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद की ओर आंखे मूंद ली जाती थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जंग का अहम हिस्सा है। एक अधिकारी ने कहा, कश्मीर में आतंक का एक तंत्र विकसित हो गया था, जिसमें अलगाववादियों, आतंकियों, भ्रष्ट नेताओं व अफसरों के साथ-साथ जमाते इस्लामी जैसे संगठन और कई बड़े व्यापारी भी शामिल थे। इस तंत्र में जनता की गुम आवाज को बुलंद करने की ईमानदार कोशिश शुरू हो गई है।

कम हुई पत्थरबाजी की घटनाएं

- वर्ष 2016 में 2,653 के मुकाबले वर्ष 2019 के पहले छह महीने में सिर्फ 40 घटनाएं हुईं

नई दिल्ली, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2016 में जहां पत्थरबाजी की करीब 2,600 घटनाएं हुईं, वहीं वर्ष 2019 के पूर्वार्ध में महज चंद दर्जन वारदातें हुईं। इन घटनाओं में शामिल शरारती तत्वों की गिरफ्तारियां भी करीब 10,500 से घटकर सौ पर आ गई हैं।

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 में पत्थरबाजी की 2,653 घटनाएं हुईं, जिनमें 10,571 शरारती तत्वों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, इनमें से सिर्फ 276 लोगों को जेल भेजा गया। बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में उथल-पुथल का लंबा दौर चला था।

वर्ष 2017 में पत्थरबाजी की 1,412 घटनाएं हुईं। इस दौरान गड़बड़ी फैलाने वाले 2,838 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें 63 जेल भेजे गए। वर्ष 2018 में पत्थरबाजी की 1,458 घटनाएं हुईं, जिनमें 3,797 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें 65 लोगों को जेल भेजा गया। वर्ष 2019 के पहले छह महीने में पत्थरबाजी की करीब 40 घटनाएं हुईं, जिनमें करीब 100 लोग हिरासत में लिए गए।

राज्यपाल शासन में सुधरी सुरक्षा की स्थिति : गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि 19 जून 2018 को राज्यपाल शासन लागू होने के बाद घाटी में सुरक्षा की स्थिति सुधरी है। महबूबा मुफ्ती की नेतृत्व वाली सरकार से भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद प्रदेश में राज्यपाल शासन लागू हुआ था। छह महीने राज्यपाल शासन चलने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो अब भी जारी है। सुरक्षा बलों ने वर्ष 2018 में 240 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया, जबकि पत्थरबाजी के कारण चोट लगने की घटनाओं में भी कमी आई है।

अगले साल मार्च तक तैयार हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय

- तीन मूर्ति भवन परिसर में बन रहा है 'म्यूजियम ऑन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया'
- इसी परिसर में है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी

तीन मूर्ति भवन के इसी परिसर में हो रहा है म्यूजियम का निर्माण। (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी यादों को सहेजने वाला 'म्यूजियम ऑन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया' अगले साल मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने हर हाल में म्यूजियम के निर्माण कार्य को अगले साल मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह म्यूजियम तीन मूर्ति भवन परिसर में बन रहा है जहां पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी (एनएमएमएल) स्थित है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीपीडब्ल्यूडी ने म्यूजियम के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सिविल कार्य, लिफ्ट लगाने, एक्सलेटर, सीसीटीवी तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट समेत अन्य कार्यों के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को चुना है।

बता दें कि तीन मूर्ति भवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सरकारी आवास था। नेहरू की स्मृति में यहां केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान एनएमएमएल की स्थापना की गई थी।

अधिकारी ने बताया कि म्यूजियम के भवन का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। सीपीडब्ल्यूडी की एक बोर्ड बैठक में भवन की फिनिशिंग समेत सिविल कार्य को जल्द पूरा करने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी का चयन कर लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि इन कार्यों में लगभग 66 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

अधिकारी ने कहा कि हमने म्यूजियम के भवन का निर्माण कार्य पूरा कर मार्च 2020 तक इसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को सौंपने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बता दें कि जुलाई 2018 में जब यहां म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई थी तब कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया था। तब तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया था कि म्यूजियम बनाने का उद्देश्य 17 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे नेहरू की विरासत को कम करना नहीं है।

मानने को तैयार नहीं बागी विधायक

कर्नाटक संकट ▸ मुंबई पहुंचते ही बदले नागराज के सुर, कहा–इस्तीफा वापस लेने का सवाल नहीं

कांग्रेस ने दी धमकी, कहा–सरकार के खिलाफ मतदान का नतीजा जानते हैं विधायक

बेंगलुरु, प्रेट्र/एएनआइ : कर्नाटक में सियासी ड्रामे के बीच पल-पल घटनाक्रम बदल रहा है। एक दिन पहले इस्तीफा वापस लेने की बात कहने वाले कांग्रेस के बागी विधायक एमटीबी नागराज पलट गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस्तीफा वापसी का सवाल ही नहीं। कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि उसके विधायक लौट आएंगे और गठबंधन सरकार को बचा लेंगे। वहीं, कांग्रेस और जदएस के 15 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। अदालत ने स्पीकर से तब यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।

कांग्रेस के संकटमोचक माने जाने वाले डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी से शनिवार को मुलाकात के बाद नागराज ने पार्टी के साथ बने रहने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि आखिरी फैसला वह साथी विधायक के सुधाकर से मिलने के बाद करेंगे। बागी विधायकों को मनाकर वापस लाने की बात कह कर नागराज मुंबई आए थे, लेकिन मुंबई पहुंचते ही सुर बदल गए। मुंबई में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस्तीफा वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नागराज को मिलाकर मुंबई में डेरा जमाए बागी विधायकों की संख्या 15 हो गई है।

रेड्डी ने नहीं दिए कोई संकेत : कांग्रेस के एक और विधायक रामलिंगा रेड्डी ने भी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर खंडरे और पार्टी के वरिष्ठ नेता एचके पाटिल ने रेड्डी से उनके घर जाकर मुलाकात की। दोनों रेड्डी को लगभग दो घंटे तक इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाते रहे, लेकिन रेड्डी ने उन्हें कोई संकेत नहीं दिए। मुलाकात के बाद खंडरे ने उम्मीद जताई कि वह पार्टी में बने रहेंगे और विधानसभा से अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे।

कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई: मुख्यमंत्री कुमारस्वामी द्वारा विश्वासमत हासिल करने की घोषणा के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल बढ़ गई है। हालांकि, अभी विश्वास प्रस्ताव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन तेरह महीने पुरानी गठबंधन सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस ने मुहिम तेज कर दी है। कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने यहां रविववार को पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। उन्होंने कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि सभी विधायक शामिल होंगे। कांग्रेस नेता शिवकुमार ने परोक्ष रूप से बागी विधायकों को धमकाते हुए कहा, 'कानून स्पष्ट है। अगर विश्वास मत प्रस्ताव के खिलाफ विधायक मतदान करते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी।' उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी बागी विधायकों की मांगें मानने के लिए भी तैयार है। शिवकुमार ने राज्य में जारी सियासी संकट के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों को मुंबई ले जाने से लेकर उन्हें होटल में ठहराने तक का काम भाजपा ने किया है। नागराज ने शिवकुमार के आरोपों को आधारहीन बताया है।

येद्दयुरप्पा ने सीएम से तत्काल इस्तीफा मांगा : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा ने कहा है कि गठबंधन सरकार ने बहुमत खो दिया है। अगर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति ईमानदार हैं तो पद से इस्तीफा देना चाहिए या सोमवार को सदन में बहुमत साबित करना चाहिए।

गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने प्रमोद सावंत सरकार से समर्थन वापस लिया

पणजी, एएनआइ/आइएएनएस : गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने रविवार को राज्य की प्रमोद सावंत सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा की। राज्यपाल मृदुला सिन्हा को लिखे पत्र में सरदेसाई ने कहा, 'जीएफपी की राजनीतिक समिति व विधायक दल की रविवार को बैठक हुई। इसमें सभी ने एकराय से भाजपा नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापसी का निर्णय किया।' ज्ञात हो, विधानसभा में नेता विपक्ष रहे चंद्रकांत कावलेकर, कांग्रेस के आए दो अन्य विधायकों तथा एक भाजपा नेता को शनिवार को सावंत मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। कावलेकर को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस क्रम में उप मुख्यमंत्री सरदेसाई समेत जीएफपी के तीन नेताओं व एक निर्दलीय विधायक को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। सावंत ने इन सभी को इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। 10 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद अब सदन में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या पांच रह गई है।

संसद परिसर में सफाई अभियान

नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में दो दिनी स्वच्छता अभियान के अंतिम दिन रविवार को भी जोरशोर से अभियान चलाया गया। इस मौके पर लोस अध्यक्ष ओम बिरला और मनोज तिवारी समेत कई भाजपा सांसदों ने सफाई की। शनिवार को बिरला ने इस अभियान की शुरुआत की थी। प्रेट्र

2035 तक भारत में बढ़ेंगे बुजुर्ग, घटेंगे युवा

- साठ साल से अधिक के लोग 8.6 फीसद से बढ़कर 15.4 फीसद हो जाएंगे
- 25–29 साल के लोगों की आबादी 19 फीसद से घटकर 15 फीसद रह जाएगी
- सर्वाधिक गिरावट 15 साल से कम के लोगों में आएगी, यह 17 फीसद रह जाएंगे

बुजुर्गों की देखभाल होगी बड़ी चुनौती। (सोशल मीडिया)

नई दिल्ली, आइएएनएस : युवाओं का देश कहा जाने वाला भारत आने वाले सालों में बुजुर्गों की अधिकता का सामना करेगा। पिछले जनगणना वर्ष 2011 के मुकाबले भारत की आबादी में वर्ष 2036 तक 26 फीसद का इजाफा होने वाला है। साठ साल से अधिक आयु के लोगों की आबादी भी दोगुनी हो जाएगी। जबकि युवा आयुवर्ग के लोगों में कमी आएगी।

सरकारी आंकड़ों और अनुमान के अनुसार, भारत की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 121.1 करोड़ थी जो वर्ष 2035 तक बढ़कर 153.6 करोड़ हो जाएगी। भारतीयों की आबादी में यह बढ़ोतरी 26.8 फीसद होगी। एक अन्य खोज के मुताबिक भारत में वृद्धों की तादाद बेतहाशा बढ़ेगी। साठ साल से अधिक आयु वर्ग के लोग 8.6 फीसद से बढ़कर 15.4 फीसद हो जाएंगे। इसीतरह 25-29 साल के लोगों की संख्या में कमी आ जाएगी। भारतीय युवाओं की आबादी 19 फीसद से घटकर 15 फीसद ही रह जाएगी। आबादी में सबसे अधिक गिरावट 15 साल से कम आयु के लोगों में आएगी। यह आबादी 30.9 फीसद से घटकर 17 फीसद ही रह जाएगी।

भारत में कामकाज और उत्पादन के क्षेत्र में अहम योगदान निभाने वाले 15 साल से 59 साल के लोगों की आबादी में मामूली बढ़ोतरी होगी। वह 60.5 फीसद से 66.7 फीसद हो जाएंगे। वर्ष 2011-15 के बीच 2.4 फीसद रहने वाली प्रजनन दर वर्ष 2031-35 तक कम होकर 1.65 फीसद ही रह जाएगा। शिशुओं की मृत्यु दर में खासी कमी आने का अनुमान है। वर्ष 2011-15 के बीच 43 फीसद रही मृत्यु दर घटकर 30 फीसद ही रह जाएगी। भारत में जन्म दर 19.8 फीसद से घटकर 12 फीसद रहने की उम्मीद है। शहरी आबादी 25 फीसद तक बढ़ने के आसार हैं।

सरकारी तकनीकी समूह की ओर से किए गए भारतीय जनसंख्या का भावी आकलन राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की ओर से किया गया है। यह आंकड़े हाल ही में एक सवाल के जवाब में संसद में भी बताए गए थे। यह भारतीय आबादी का शुरुआती चित्रण है। जब सभी आंकड़े एकत्र हो जाएंगे तो एक और मसौदा तैयार किया जाएगा। समितियां इस पर काम कर रही हैं।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की मई के महीने में हुई बैठकों के आधार पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनगणना आयोग के रजिस्ट्रार जनरल विवेक जोशी ने की थी। उल्लेखनीय है कि दुनिया के कई देशों में बुजुर्गों की तादात काफी ज्यादा है। पड़ोसी मुल्क चीन में भी वरिष्ठ जनों की संख्या काफी है। सरकार इन लोगों की देखभाल के लिए काफी संजीदगी से काम करती है।

बीएल संतोष बने भाजपा के संगठन महासचिव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बीएल संतोष की फाइल फोटो। एएनआइ

- भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने की नियुक्ति
- पार्टी में अध्यक्ष के बाद महासचिव का पद सबसे अहम

भाजपा में लंबे अरसे तक संगठन महासचिव रहे रामलाल की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में वापसी के दूसरे ही दिन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बीएल संतोष को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। कर्नाटक और दक्षिणी राज्यों का जिम्मा देखते रहे संतोष की इस पदोन्नति ने यह साबित कर दिया है कि दक्षिणी और तटीय राज्यों में पार्टी का फोकस अब और ज्यादा बढ़ेगा। रामलाल ने राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर संतोष को बधाई दी है।

संगठन महासचिव का पद भाजपा में अध्यक्ष के बाद दूसरा सबसे ज्यादा अहम पद माना जाता है। रामलाल इस पद पर 13 वर्षों तक रहे थे। उनके बाद कई नामों पर अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन शाह और संघ ने संतोष को चुना। वर्ष 2006 में संघ से भाजपा में आए संतोष आठ वर्षों तक कर्नाटक के संगठन महासचिव रहे थे। 2014 में उन्हें केंद्र से जोड़ते हुए दक्षिण के राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी। दरअसल रामलाल से थोड़े अलग संतोष खुल कर राजनीतिक टिप्पणियां करने वाले प्रचारकों में शामिल हैं। वह मजबूत तरीके से अपनी बात रखने के लिए भी जाने जाते हैं, हालांकि, इसकी वजह से वह स्थानीय राजनीति में विवादों के शिकार भी होते रहे हैं। कर्नाटक में चल रही सियासी उथल-पुथल के बीच भी वह खुल कर अपने विचारों को व्यक्त करते रहे हैं।

चुनावी रणनीतियों के वह कुशल खिलाड़ी माने जाते हैं। भाजपा दक्षिणी और तटीय राज्यों को छोड़कर पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। शाह के एजेंडे में दक्षिण है। ऐसे में संतोष का चुनाव भी एक संदेश है। संतोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विश्वस्त भी माने जाते हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु दक्षिण से दिवंगत नेता अनंत कुमार की पत्नी की जगह नए और युवा उम्मीदवार को उतारने की सलाह उन्होंने ही दी थी। हालांकि इसका कई स्तर पर विरोध हुआ था लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी बात मानी थी। युवा नेता तेजस्वी सूर्या वहां से आसानी से जीत गए।

भाजपा में सगंठनात्मक चुनाव भी जल्द होने वाले हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि गृह मंत्री बनाए गए अमित शाह भाजपा अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं। इस स्थिति में संगठन को आगे ले जाने में संतोष की भूमिका बहुत अहम होगी। गौरतलब है कि दो दिन पहले विजयवाड़ा में संघ की तीन दिवसीय बैठक थी जिसमें विभिन्न स्तरों पर बदलाव की चर्चा हुई थी। उसी बैठक के बाद रामलाल को भी वापस संघ में बुलाया गया था। माना जा रहा है कि अभी और कई स्थानों पर बदलाव होंगे।

पहले इंजीनियरिंग, फिर सियासत

संघ के प्रचारक से भाजपा के संगठन महासचिव तक का सियासी सफर करने वाले बीएल संतोष एक इंजीनियर भी रहे हैं। कर्नाटक के दावणगेरे स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद उन्होंने एक दूरसंचार कंपनी से करियर की शुरुआत की थी। कर्नाटक के चामराजनगर में जन्मे संतोष 1993 में संघ से जुड़े और प्रचारक बन गए। जल एवं ठोस कचरा प्रबंधन, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के हालात, सामाजिक पुनर्गठन आंदोलनों और प्राचीन व आधुनिक विश्व में भारत के योगदान जैसे विषयों पर उन्होंने गहरा अध्ययन किया है। समसामयिक और सामाजिक मुद्दों पर वह लिखते रहे हैं। सामान्य परिवार से आने वाले संतोष के माता-पिता आज भी कर्नाटक के उडुप्पी जिले के एक गांव में रहते हैं। उनकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई भी है।

अध्यादेश लाकर मुद्दा निपटाना चाहते थे चंद्रशेखर

अयोध्या विवाद

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की किताब में किया गया दावा, 1990 में तत्कालीन पीएम चंद्रशेखर ने मुलायम सिंह यादव, शरद पवार और भैरोसिंह शेखावत के साथ विहिप और मुस्लिम नेताओं के बीच इस मुद्दे पर मध्यस्थता की थी

नई दिल्ली, प्रेट्र : वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के दो साल पहले कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर सरकार विवाद के निपटारे के लिए अध्यादेश लाने की योजना बना रही थी। यह दावा पूर्व प्रधानमंत्री पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा लिखी गई एक किताब में किया गया है। इसके सह लेखक रवि दत्त वाजपेयी हैं।

'चंद्रशेखर : द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स' नाम की किताब में कहा गया है कि 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उस समय के मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव, शरद पवार और भैरोसिंह शेखावत के साथ विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और मुस्लिम नेताओं के बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर मध्यस्थता की थी। जयप्रकाश नारायण के करीबी सहयोगी रहे वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय के हवाले से किताब में कहा गया है कि व्यापक तौर पर यह माना जाता है कि चंद्रशेखर सरकार अध्यादेश लागू कर राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को 'सुलझाने के कगार' पर थी।

किताब में दावा किया गया है कि अध्यादेश की तैयारी की सूचना से तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी और उनकी सलाहकार मंडली तनाव में

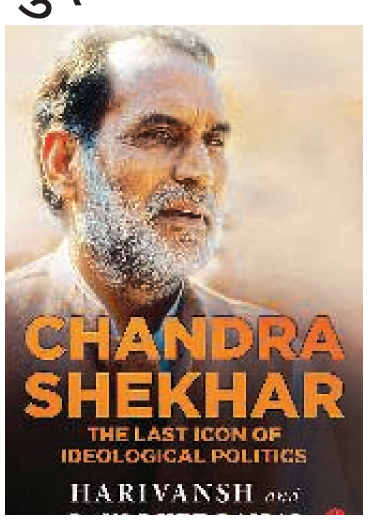

यही है किताब का मुख्य पृष्ठ (सोशल मीडिया से)

आ गई। वे नहीं चाहते थे कि इस जटिल समस्या के समाधान का श्रेय चंद्रशेखर को मिले।

हरिवंश ने आगे लिखा है कि चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान हिंदुओं (विहिप) और मुस्लिमों (बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी) के नेताओं में दुश्मनी को कम करने के लिए कुछ अत्यंत साहसिक कदम उठाए। इसमें कहा गया है, 'चंद्रशेखर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान व पारस्परिक समझौतों के लिए रास्ता तलाशने के उद्देश्य से दावेदारों के दोनों समूहों के बीच वार्ता कराने में सफल रहे।' इसी क्रम में चंद्रशेखर ने राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री व भाजपा नेता भैंरो सिंह शेखावत, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पवार और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर काम करने के लिए आमंत्रित किया था। तीनों मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के बाद ही दोनों पक्षों ने मामलो को सुप्रीम कोर्ट ले जाने और उसका आदेश स्वीकार करने का फैसला किया था।

बनाई गई थीं चार विशेषज्ञ समितियां : किताब में कहा गया है कि विहिप व बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी द्वारा सौंपे गए तथ्यों की जांच के लिए तत्कालीन चंद्रशेखर सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चार विशेषज्ञ समितियों का गठन किया था। इन समितियों को ऐतिहासिकता, पुरातात्विक पहलुओं व राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप तथ्यों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

विधि आयोग के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली, प्रेट्र : कानून मंत्रालय ने जटिल कानूनी मुद्दों पर सरकार को सलाह देने वाले विधि आयोग के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 21वें विधि आयोग का तीन साल का कार्यकाल पिछले साल 31 अगस्त को समाप्त हुआ था। कार्यकाल खत्म होने के बाद एक बार कानून मंत्रालय ने इसके पुनर्गठन का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ सका। बाद में सरकार चुनावों में व्यस्त हो गई।

सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आयोग के पुनर्गठन का प्रस्ताव अगले कुछ दिनों में कैबिनेट में लाया जाएगा। आयोग का नेतृत्व करने वाले जस्टिस बीएस चौहान (सेवानिवृत्त) ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे शामिल थे। विधि आयोग ने एक साथ चुनावों का समर्थन किया था, लेकिन समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर उसका कहना था कि इसके लिए अभी सही समय नहीं है। कैबिनेट विधि आयोग के पुनर्गठन को तीन साल की अवधि के लिए मंजूरी देती है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

1083 मोबाइल टावर और 524 एक्सचेंज ठप पड़ गए हैं बिजली बिल न चुका पाने की वजह से सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के। उप्र में सर्वाधिक 391 टावर और महाराष्ट्र में 178 एक्सचेंजों का बिजली कनेक्शन कट चुका है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 15 जुलाई 2019

मप्र में शिवराज सरकार की योजनाओं को किया बंद

नईदुनिया, भोपाल

▸ किसान आयोग बंद, मूल्य निर्धारण समिति बनी नहीं

▸ कमलनाथ सरकार बनाएगी कृषि सलाहकार परिषद

शिवराज सिंह फाइल फोटो

कमलनाथ फाइल फोटो

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने किसान आयोग की जगह कृषि सलाहकार परिषद बनाने का फैसला किया है। शिवराज सरकार ने आयोग बनाया था पर इसे कोई अधिकार नहीं दिए थे। यही वजह है कि इसकी अधिकांश सिफारिशें कृषि विभाग में धूल खाती रहीं। मंदसौर गोलीकांड के बाद जोर-शोर से मूल्य निर्धारण समिति बनाने की भी घोषणा हुई, लेकिन यह आकार ही नहीं ले पाई। वहीं, कृषि कैबिनेट का तो अता-पता नहीं है। बीते सात माह में इसकी एक भी बैठक नहीं हुई।

शिवराज सरकार ने किसान और सरकार के बीच सेतु का काम करने के लिए किसान आयोग गठित किया था। इसका काम किसानों की समस्याओं को सुनने-समझने और सरकार को सिफारिश करने का था, लेकिन इसे कोई अधिकार ही नहीं दिए गए। आयोग ने जितनी भी सिफारिशें कीं वे कागजी खानापूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं रहीं। यही वजह है कि कृषि विभाग ने भी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इसी तरह कृषि कैबिनेट बनाई गई। इसका काम भी विभागों की योजनाओं को मंजूरी देने तक ही सीमित रहा, जबकि इसे कैबिनेट के समान ही अधिकार दिए गए थे। इसके बावजूद कृषि, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट के पास भेजे जाते रहे। यही स्थिति कमलनाथ सरकार में भी बन गई है। कृषि कैबिनेट का पुनर्गठन नहीं हुआ और न ही इसकी कोई बैठक हुई। जय किसान फसल ऋण मुक्ति योजना, जय किसान समृद्धि योजना, किसानों के बिजली बिल आधे करने जैसे कई अहम फैसले सरकार ने लिए पर इन्हें कृषि कैबिनेट ले जाने की जरूरत ही महसूस नहीं की गई। सूत्रों का कहना है कि कृषि कैबिनेट की व्यवस्था को कमलनाथ सरकार दोहराव मान रही है। यही वजह है कि न तो इसका पुनर्गठन किया गया और न ही इसकी भूमिका का लेकर कोई विचार किया जा रहा है।

बिना अधिकार संस्था का कोई मतलब नहीं : शर्मा : राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा 'कक्काजी' का कहना है कि बिना अधिकार किसान आयोग का कोई मतलब नहीं है। हमने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इसे संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने किसान मंच बनाया था पर बरेली में किसानों पर गोलीचालन के बाद बैठकें बंद हो गईं। अब कमलनाथ सरकार कृषि सलाहकार परिषद का गठन करने जा रही है। यह भी तभी कारगर होगी, जब इसमें किसानों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ हों।

आयोग की सिफारिशों पर गंभीर नहीं रही सरकार : डॉ. कौशल : पूर्व कृषि संचालक डॉ. जीएस कौशल का कहना है कि किसान आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय था। इसकी सिफारिशों पर कुछ नहीं हुआ। जब तक इसकी सिफारिशों को लेकर सरकार गंभीर नहीं होगी तब तक ऐसी व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। कृषि कैबिनेट को भी भंग कर देना चाहिए, क्योंकि यह औपचारिकता निभाने वाली एजेंसी की तरह ही रही। तत्कालीन सरकार ने जो भी निर्णय किए वे केंद्रीयकृत रहे। अब कृषि सलाहकार परिषद बनाई जा रही है। यह भी तभी उपयोगी रहेगी, जब इसमें कृषि के विभिन्न विषयों से जुड़े विशेषज्ञ और किसानों के प्रतिनिधियों को रखा जाना चाहिए।

महाराष्ट्र कांग्रेस की नई नियुक्तियों से संतुलन साधने की कोशिश

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

▸ बालासाहब थोरात को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ पांच कार्याध्यक्षों की नियुक्ति कर कांग्रेस ने क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है। बड़ी बात यह कि ये नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा कर चुके राहुल गांधी की सहमति से की गई हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के त्यागपत्र देने की घोषणा के बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण एवं मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा भी अपने-अपने पद से त्यागपत्र दे चुके हैं। शनिवार देर रात अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के.सी.वेणुगोपाल ने एक विज्ञप्ति जारी कर बालासाहब थोरात को महाराष्ट्र कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। इसके साथ ही, महाराष्ट्र के पांच क्षेत्रों के लिए पांच कार्याध्यक्षों की नियुक्ति भी की गई है। इन कार्याध्यक्षों की नियुक्ति करते हुए क्षेत्रीय, जातीय एवं सामाजिक गणित का पूरा ख्याल रखा गया है। विज्ञप्ति में साफ कहा गया है कि ये नियुक्तियां माननीय कांग्रेस की सहमति से ही की गई हैं। बता दें कि राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और कर्नाटक में भी वहां के विधानसभा चुनावों से करीब एक साल पहले ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई कार्याध्यक्षों की नियुक्तियां की गई थीं। बल्कि महाराष्ट्र में ये नियुक्तियां अपेक्षाकृत देरी से हो सकी हैं। क्योंकि यहां दो माह बाद ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है।

नवनियुक्त अध्यक्ष बालासाहब थोरात प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ मराठा नेता हैं। वह सात बार विधायक रह चुके हैं। अशोक चव्हाण के अध्यक्ष बनने से पहले भी उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चला था, लेकिन तब वह अध्यक्ष नहीं बन सके थे। उनके साथ कार्याध्यक्ष बनाए गए पांच लोगों में युवा और वरिष्ठ नेताओं का संयोग बैठाने की कोशिश की गई है। विदर्भ के नागपुर डिविजन से डॉ. नितिन राऊत और अमरावती डिविजन से यशोमती ठाकुर को कार्याध्यक्ष बनाया गया है।

कोंकण डिविजन से कार्याध्यक्ष बने मुजफ्फर हुसैन डेढ़ टर्म विधान परिषद के अध्यक्ष रहने के साथ-साथ पांच साल तक महाराष्ट्र युवक कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। मूलतः वह भी विदर्भ के अमरावती जनपद के ही मूल निवासी हैं, और मराठीभाषी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बसवराज पाटिल मराठवाड़ा के लिंगायत नेता हैं। जबकि विश्वजीत कदम पश्चिम महाराष्ट्र के मराठा युवा नेता हैं। वह भी युवक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। इस प्रकार कार्याध्यक्षों की नई टीम में युवाओं को तरजीह दी गई है। माना जा रहा है कि मुजफ्फर हुसैन और विश्वजीत जीत कदम के माध्यम से कांग्रेस उनके दौर में बने युवा संगठन का लाभ लेने के साथ यशोमती ठाकुर को आगे लाकर महिलाओं में अपनी पैठ बनाना चाहती है।

फिल्म आर्टिकल–15 पर मंत्री विरोध करने वालों के साथ, विधायक चाहते हैं टैक्स फ्री हो

नईदुनिया, भोपाल : विवादों में घिरी फिल्म 'आर्टिकल-15' को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में दो मत दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा जहां इस फिल्म का विरोध करने वाले अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ खड़े हैं तो उनकी ही पार्टी के करीब दो दर्जन से ज्यादा विधायकों ने फिल्म को टैक्स फ्री कराने का अभियान चलाया है। पार्टी के आदिवासी विधायक डॉ. हीरालाल अलावा इस अभियान की अगुआई कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के चर्चित बदायूं दुष्कर्म कांड पर आधारित फिल्म आर्टिकल-15 को कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता मप्र में प्रतिबंधित करने के लिए पर्दे के पीछे से प्रयास कर रहे हैं तो कुछ नेता सामने आकर टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। मंत्री पीसी शर्मा ने फिल्म को प्रतिबंधित कराने की मांग करने वाले अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कराई थी। मालूम हो, इस संगठन के संरक्षक शर्मा ही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद उन्हें विचार करने के आश्वासन के अलावा कोई ठोस जवाब नहीं दिया और न ही कोई कार्रवाई की।

अब इसी फिल्म को लेकर आदिवासी नेता डॉ. अलावा ने अभियान चलाया है। अलावा ने कहा कि आर्टिकल-15 फिल्म में कोई भी विवादास्पद कहानी नहीं है, बल्कि फिल्म से ईमानदार सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए डॉ. अलावा ने मांग-पत्र तैयार कर दो दर्जन से ज्यादा विधायकों के हस्ताक्षर कराकर मुख्यमंत्री से फिल्म को टैक्स फ्री कराने की मांग की है।

आजम खां पर एक और मुकदमा, 23 की तैयारी

बढ़ी मुश्किलें ▸ जौहर यूनिवर्सिटी के लिए 26 किसानों की जमीन हड़पने का आरोप

तीन किसानों की शिकायत पर दर्ज हो चुका है मुकदमा 23 और ने दी है तहरीर

जागरण संवाददाता, रामपुर

सांसद आजम खां फाइल फोटो

सांसद आजम खां और जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आले हसन खां के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में किसान की जमीन जबरन जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल किए जाने का आरोप है। इसी आरोप में इससे पहले दो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। यह तीसरा मुकदमा है। इन मुकदमों से पहले प्रशासन ने जांच कराई थी। प्रशासन की जांच से पता चला कि आलियागंज के 26 किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया गया है। तब प्रशासन ने राजस्व कानूनगो की ओर से अजीमनगर थाने में सांसद आजम और पूर्व सीओ आले हसन खां के खिलाफ मुकदमा कराया था। इसके बाद अब पीड़ित 26 किसानों ने भी अलग-अलग तहरीर दी है। पहले दो किसानों बन्दे अली और यासीन की तहरीर पर शनिवार को मुकदमे हुए। इसके बाद रविवार को मुहम्मद अहमद ने तहरीर दी, जिस पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अजीमनगर थाना प्रभारी राजीव चौधरी ने बताया कि किसान की तहरीर पर सांसद और पूर्व सीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अन्य 23 किसानों ने भी तहरीर दी है, इन सभी की तहरीर पर अलग-अलग मुकदमे किए जाएंगे।

पुलिस अधीक्षक डॉ. अजयपाल शर्मा का कहना है यूनिवर्सिटी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आले हसन के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। उन्होंने लोगों को डरा धमका कर जमीनों पर कब्जे कराए, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार दबिश दी जा रही है। आजम सांसद हैं। अभी उनकी गिरफ्तारी के प्रयास नहीं किए गए हैं। नियमानुसार जो कानूनी प्रकिया होनी चाहिए, वह अपनाई जाएगी।

आजम पर दर्ज अन्य मुकदमे

जमीन संबंधी मामलों में राजस्व परिषद में आजम के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन बिना अनुमति के खरीदने और सरकारी जमीन के बदले में अनुपयोगी जमीन देने के आरोप हैं।

लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक आचार संहिता उल्लंघन और आपत्तिजनक बयान देने में 15 मुकदमे अलग-अलग थानों में दर्ज किए गए हैं।

सारे मुकदमे फर्जी, अफसरों के खिलाफ जाएंगे हाई कोर्ट : अब्दुल्ला : सांसद आजम खां के बेटे विधायक अब्दुल्ला ने सपा कार्यालय पर मीडिया से कहा कि उनके पिता और जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आले हसन खां के खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, वे सब फर्जी हैं। उन्होंने मीडिया के सामने वीडियो क्लिप पेश की और दिखाया कि आले हसन की पत्नी ने पुलिस पर रिवॉल्वर नहीं ताना, बल्कि पुलिस को तलाशी के दौरान पूरा सहयोग किया। कहा कि उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रख दी तो पुलिस ने झूठा केस बना दिया। कहा कि अफसरों के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे।

विस चुनाव से पहले चल रहा सियासी कद बढ़ाने का दौर

अरविंद शर्मा, पटना

▸ बिहार में चुनाव से पहले सभी दलों में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान

बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में अभी करीब साल भर बाकी है, लेकिन सियासी दलों ने अभी से अपनी ताकत और सामर्थ्य बढ़ाने का उपक्रम शुरू कर दिया है। सभी दलों का जोर सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर है। भाजपा, राजद और जदयू ने विधिवत सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस में यह काम अनवरत चलता है, लेकिन चुनाव को देखते हुए वहां भी तेजी देखी जा रही है।

सदस्यों की संख्या के लिहाज से बिहार के चार बड़े सियासी दलों में भाजपा सबसे आगे दिख रही है। उसके सदस्यों की संख्या 80 लाख पार कर गई है। बिहार प्रदेश भाजपा की सदस्यता अभियान समिति के प्रभारी राधामोहन शर्मा के मुताबिक प्रदेश में उनकी पार्टी के 79 लाख सदस्य पहले से हैं। ताजा अभियान में अभी तक पौने दो लाख सदस्य और जुड़ चुके हैं। सदस्य बनाने का अभियान 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान पार्टी का लक्ष्य 16 लाख नए सदस्य बनाने का है। कोशिश जारी है। हालांकि राधामोहन दावा करते हैं कि समय सीमा खत्म होने से पहले तक 30 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ चुके होंगे। उनका हिसाब अगर कामयाब हुआ तो भाजपा के बिहार में एक करोड़ से ज्यादा सदस्य हो जाएंगे।

सदस्यों की संख्या के मामले में बिहार में जदयू दूसरी बड़ी पार्टी है। जदयू की सदस्यता अभियान समिति के प्रभारी रवींद्र प्रसाद सिंह के मुताबिक अभी पार्टी के 50 लाख सदस्य हैं। आठ जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए अभियान की शुरुआत की है। अधिकतम का लक्ष्य तय नहीं है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। अभियान चल रहा है। सीएम ने शुरुआत कर दी है। समापन की तिथि तय नहीं है। ऑनलाइन भी सदस्य बनाया जा रहा है।

राजद बना रहा बूथ तक पकड़ : लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान राजद को ही हुआ है। इस दौरान सभी दलों के सदस्यों की संख्या बढ़ी, लेकिन राजद की घट गई। तीन साल पहले प्रदेश में उसके 60 लाख सदस्य थे, लेकिन पिछली बार आपाधापी में सिर्फ 30 लाख सदस्यों का ही नवीकरण हो सका। राजद में सांगठनिक चुनाव के पहले सदस्यों का नवीकरण होता है। पिछली बार आधे सदस्यों की खोज-खबर नहीं ली जा सकी। राजद के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन के मुताबिक अबकी पूरी तैयारी है।

अहमियत बढ़ाने में जुटी कांग्रेस : राजद समेत पांच दलों के पुराने महागठबंधन में कांग्रेस अपनी अहमियत बढ़ाने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव में भाजपा-जदयू की संयुक्त ताकत के विरुद्ध लड़कर उसने एक सीट निकालकर राजद पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर के दावे के मुताबिक प्रदेश में कांग्रेस के अभी 16 लाख सदस्य हैं। हालांकि दावे के हिसाब से सदस्य नजर नहीं आते। सदस्यता लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती। कभी भी सदस्य बना जा सकता है।

बीपीएससी ने पूछा क्या राज्यपाल कठपुतली हैं?

जागरण संवाददाता, पटना : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की मुख्य परीक्षा में राज्यपाल को लेकर पूछा गया एक प्रश्न विवादों में घेरे में आ गया है। रविवार को सामान्य ज्ञान के दूसरे पेपर में सवाल था- 'भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या वह केवल एक कठपुतली है?' छात्रों के बीच यह सवाल चर्चा का विषय बना रहा।

इस बाबत प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ डॉ. एम रहमान ने कहा कि कई बार छात्रों की अवधारणा को जानने के लिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मगर प्रश्न में विशेषकर बिहार लिखकर इंगित करने या कठपुतली जैसे शब्द के इस्तेमाल से बचा जा सकता था। कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस के प्राचार्य डॉ. तपन कुमार शांडिल्य ने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। बीपीएससी की ओर से इस तरह का सवाल पूछना गलत है।

इस तरह के प्रश्न पहले भी पूछे जाते रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। वैसे भी हम प्रश्न पहले नहीं देख सकते हैं।
– अमरेंद्र कुमार, परीक्षा नियंत्रक, बीपीएससी

'कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब कांग्रेस की संस्कृति से मुक्ति'

राज्य ब्यूरो, रांची

▸ भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा ने पार्टी के बहुचर्चित नारे का स्पष्ट किया अर्थ

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को रांची में कांग्रेस मुक्त भारत के पार्टी के नारे को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब कांग्रेस की कमीशन और करप्शन की संस्कृति से मुक्ति है। रविवार को यहां भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक अलग तरह की संस्कृति पनपी है, जिसने वोट बैंक व जातिवाद को नकारा है और विकासवाद की राजनीति को स्वीकार किया है। यह संस्कृति हमारी है और इसी विचार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।

जेपी नड्डा ने कर्नाटक के राजनीतिक तूफान पर भाजपा की भूमिका को भी नकारा और विपक्ष के ऐसे आरोपों को तथ्यहीन बताया। कहा, यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। उसके बाद सब लोग अपने-अपने ढंग से इस्तीफा दे रहे हैं। यह उनका विषय है, वे जानें। नड्डा ने अपने प्रवास के दौरान सांगठनिक स्तर पर की गई बैठकों की जानकारी साझा की। कहा, बैठकों में बूथ रचना से लेकर चुनाव की रणनीति और सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। 28 को दोबारा कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसकी रिपोर्ट मैं खुद लूंगा।

मॉब लिंचिंग की घटना पर कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। कानून अपना काम करेगा। भाजपा सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखती है।

धौनी के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर बोले

पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाना हमारा लक्ष्य है। ऐसे में ख्याति प्राप्त कलाकारों, खिलाड़ियों सबका आना स्वीकार है।

अलीगढ़ के चाचा नेहरू मदरसे में बना पूजास्थल, हिंदू बच्चों ने की पूजा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़

अलीगढ़ में मदरसा चाचा नेहरू में एक ही कमरे में एक तरफ मां सरस्वती की पूजा करते हिंदू बच्चे और दूसरी ओर नमाज अदा करते मुस्लिम छात्र। शीलेंद्र कुमार

अलीगढ़ के चाचा नेहरू मदरसे में मंदिर व मस्जिद का निर्माण कराने की घोषणा कर विरोधियों के निशाने पर आईं पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी ने बच्चों के लिए पूजास्थल तय कर दिया है। कमरे में एक तरफ हिंदू बच्चों के लिए सरस्वती की तस्वीर रखी गई, तो दूसरे हिस्से में मुस्लिम बच्चे कुरान पढ़ते हैं।

सलमा अंसारी अलीगढ़ में अलनूर चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत चाचा नेहरू मदरसा चला रही हैं। शनिवार को उन्होंने मीडिया के सामने घोषणा की थी कि वह मदरसे में मंदिर व मस्जिद का निर्माण कराएंगी। मंदिर बनाने का निर्णय हिंदू बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। मंदिर में शिवजी व हनुमानजी की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने एक कमरे में पूजा की व्यवस्था करवा दी है। रविवार को मदरसे में सांप्रदायिक सौहार्द का नजारा था। कमरे में एक तरफ हिंदू बच्चे दीपक जलाकर सरस्वती की पूजा कर रहे थे, दूसरी ओर मुस्लिम बच्चे नमाज अदा कर रहे थे। सलमा अंसारी का कहना है कि मेरा मदरसा है। विरोध करने वाले न तो फंडिंग करते हैं, न कोई और मदद। इनको विरोध का कोई हक नहीं है। मेरे पति हामिद अंसारी को इससे कोई परेशानी नहीं होती। सलमा अंसारी अलीगढ़ में तीन मदरसों का संचालन कर रही हैं। इनमें मदरसा चाचा नेहरू में चार हजार बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 1100 हिंदू हैं।

सिद्धू ने दे दिया इस्तीफा 34 दिन बाद खोला राज

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

▸ विभाग बदले जाने से सीएम अमरिंदर से थे नाराज, राहुल को सौंपा था त्यागपत्र

नवजोत सिंह सिद्धू फाइल फोटो

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा विभाग में बदलाव से नाराज नवजोत सिंह सिद्धू ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा 10 जून को राहुल गांधी को सौंपा था, लेकिन इसे 34 दिन बाद रविवार को सार्वजनिक किया। इस्तीफा भी राहुल को संबोधित है, जो सरकारी स्तर पर कोई मायने नहीं रखता है। हालांकि बाद में सिद्धू ने पुनः ट्वीट कर कहा कि वह अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भी भेज देंगे, लेकिन देर शाम तक उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचा था।

मुख्यमंत्री अमरिंदर ने गत 6 जून को 13 मंत्रियों के विभाग बदले थे। सिद्धू से स्थानीय निकाय विभाग लेकर बिजली महकमा दे दिया गया था जिससे वह काफी नाराज हुए थे। उन्होंने 10 जून को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी की महासचिव प्रियंका भी मौजूद थीं। राहुल ने कैप्टन व सिद्धू के बीच विवाद को खत्म करने के लिए वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को जिम्मेदारी सौंपी थी। सिद्धू ने कहा है कि उन्होंने राहुल को उसी दिन अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इस्तीफे में उन्होंने महज दो पंक्तियों में लिखा है कि वह पंजाब सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। इसके बाद से ही उन्होंने चुप्पी साध ली थी। न तो अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाली और न ही पंजाब में पार्टी के किसी नेता और मंत्री के संपर्क में रहे।

इस बीच अमरिंदर व पंजाब के तीन कैबिनेट मंत्री जरूर अहमद पटेल से मिले। हाईकमान की तरफ से कोई भी सकारात्मक संकेत न मिलता देख सिद्धू ने अपना इस्तीफा ट्विटर एकाउंट पर पोस्ट कर सार्वजनिक कर दिया।

सरकारी स्तर पर देखा जाए तो सिद्धू का राहुल गांधी को इस्तीफा देना कोई मायने नहीं रखता है। उन्हें अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को ही सौंपना पड़ेगा। वह राज्यपाल को भी अपना इस्तीफा भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री ही उनका इस्तीफा मंजूर करेंगे।

ट्विटर पर जब सवाल उठने लगे तो सिद्धू ने दोबारा ट्वीट किया कि वह अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज देंगे। लेकिन सिद्धू की कोठी से महज दो सौ गज की दूरी पर स्थित मुख्यमंत्री की कोठी तक देर शाम तक इस्तीफा नहीं पहुंचा था। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने भी इसकी पुष्टि की है।

अगस्त 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथग्रहण समारोह में समारोह में सिद्धू गए थे। तभी से उनके व कैप्टन के बीच दरार पड़ने लगी थी। कैप्टन नहीं चाहते थे कि सिद्धू उस समारोह में जाएं। उन्होंने सिद्धू को फोन करके मना भी किया, लेकिन सिद्धू नहीं माने। सिद्धू न सिर्फ पाकिस्तान गए बल्कि समारोह में वहां के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से गले भी मिले, जिसे लेकर खासा बवाल मचा। कैप्टन ने भी इसका विरोध किया। बाद में करतारपुर कॉरिडोर के नींव पत्थर रखने के समारोह में भी उनके जाने पर विवाद हुआ था।

कैप्टन मेरे कैप्टन नहीं : पांच राज्यों के चुनाव प्रचार पर गए सिद्धू ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि कैप्टन पंजाब के कैप्टन हो सकते हैं, मेरे नहीं। मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं।

दिखाते रहे पाकिस्तान प्रेम : पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमले के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाने को लेकर बयान दिया। दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर सिद्धू ने कहा कि किसी एक व्यक्ति या संगठन के लिए पूरे राष्ट्र को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

कैप्टन से दूरी बढ़ने की मुख्य वजहें : सिद्धू के कई बयानों की वजह से कैप्टन से उनकी दूरी बढ़ती गई। लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 17 मई सिद्धू ने बठिंडा में रैली को संबोधित करते हुए बिना किसी का नाम लिए कहा था कि मिल-बांट कर खाने वालों को ठोक दो। उनका इशारा साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादलों की ओर था। यही नहीं, सिद्धू ने कहा था कि बेअदबी कांड पर जस्टिस रंजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की बजाए एसआइटी बनाने की क्या जरूरत थी। लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर ने भी कैप्टन पर निशाना साधा था कि कैप्टन के कहने पर ही टिकट काटा गया। सिद्धू ने भी अपनी पत्नी के आरोपों की पुष्टि की थी।

छत्तीसगढ़ के 27 हजार घरों में ऑफ ग्रिड पहुंचेगा 'सौभाग्य'

प्रयास

राज्य के 15 जिले अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं शतप्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य, सात लाख 31 हजार से अधिक घरों तक बिजली पहुंचाई जानी थी

नईदुनिया, रायपुर

छग में बचे रह गए घरों में बिजली पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रतीकात्मक

छत्तीसगढ़ के 27,854 घरों में अब तक केंद्र सरकार के 'सौभाग्य' योजना की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। इसकी वजह से राज्य के 15 जिलों के शतप्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। वन, बाधा और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इन घरों तक खंभे और तारों (ग्रिड) के मध्यम से बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती। इस वजह से वहां गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऑफ ग्रिड बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

अफसरों के अनुसार इसी वर्ष फरवरी में प्रदेश के दौरे पर आए तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने योजना की समीक्षा की थी। बैठक में राज्य सरकार की तरफ से इन सभी 27 हजार से अधिक घरों तक सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने का प्रस्ताव दिया गया था। ऊर्जा विभाग के अफसरों के अनुसार, योजना के तहत राज्य के कुल सात लाख 31 हजार 129 घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से छह लाख 65 हजार 756 घरों तक ग्रिड से और 65 हजार 373 घरों तक ऑफ ग्रिड विद्युतीकरण करना था। अफसरों के अनुसार जहां ग्रिड से परंपरागत तरीके से बिजली पहुंचाई जानी थी उन सभी छह लाख से अधिक घरों को रोशन किया जा चुका है। ऑफ ग्रिड वाले घरों में से 37 हजार 519 तक ही बिजली पहुंच पाई है।

ज्यादातर वनवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र : राज्य के जिन घरों तक अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, उनमें से ज्यादातर वन और नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। राज्य के जिन 15 जिलों में शतप्रतिशत घरों तक बिजली नहीं पहुंचा पाई है उनमें सरगुजा और संभाग के पांच-पांच जिले शामिल हैं। इस सूची में गरियाबंद, राजनांदगांव, कबीरधाम, कोरबा और रायगढ़ जिले में भी शामिल हैं।

छग में अंडे की सियासत में खुलकर उतरी भाजपा

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मिड डे मील में अंडा देने पर अभी तक विभिन्न संगठन मोर्चा खोले चुके हैं, लेकिन अब भाजपा भी अंडे की सियासत में खुलकर मैदान में उतर आई है। भाजपा ने सरकार को अपने फैसले पर एक बार फिर विचार करने की सलाह दी है।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए सरकार से इस पर चिंतन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक आस्था और वैचारिक बात है। मिड डे मील में अंडा देने का विरोध कबीरपंथ के अनुयायी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह ऐसे लोग हैं, जो कबीरपंथ को मानते हैं, जो किसी जाति या धर्म से नहीं है। सरकार का यह फैसला उचित नहीं है। फैसले पर सरकार को चिंतन करना चाहिए।

बता दें कि सरकार यह तर्क दे रही है कि राज्य में कुपोषित बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण प्रोटीन को भोजन में शामिल किया जा रहा है। अंडा सिर्फ उन्हीं बच्चों को परोसा जाएगा जो मांसाहारी हैं। शाकाहारी बच्चों को अन्य प्रोटीनयुक्त खाद्य सामग्री परोसी जाएगी। किसी भी भोजन में अंडा डाल कर उसे तैयार नहीं किया जाएगा।

चंद्रयान-2

18-9-2008 चंद्रयान-2 मिशन भेजे जाने को स्वीकृति मिली

15-7-2019 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लांचिंग

6-9-2019 चांद पर उतरने की तारीख

ऐसा है इसरो का बाहुबली

चंद्रयान-2 को अपने कंधे पर उठाकर चांद की ओर रवाना करने की जिम्मेदारी इसरो ने अपने 'बाहुबली' को दी। 'बाहुबली' इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसका नाम जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हीकल-मार्क 3 (जीएसएलवी-एमके 3) है। यह चार टन वजनी सेटेलाइट ले जाने में सक्षम है। इसका वजन 640 टन और ऊंचाई 43.43 मीटर है।

ऑर्बिटर: 2,379 किलोग्राम वजन वाला ऑर्बिटर एक साल तक चांद की परिक्रमा करेगा। इसमें आठ पेलोड लगे हैं, जो अलग-अलग प्रयोगों को अंजाम देंगे। यह ऑर्बिटर बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क (आइडीएसएन) से संपर्क साधने में सक्षम होगा। इसके अलावा यह लैंडर के संपर्क में भी रहेगा।

लैंडर विक्रम: 1,471 किलोग्राम वजनी लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इस पर तीन पेलोड लगे हैं। यह दो मीटर प्रति सेकंड की गति से चांद की सतह पर उतरेगा। इसे चांद की एक दिन की अवधि तक काम करने के लिए तैयार किया गया है। धरती के हिसाब से यह अवधि 14 दिन की बनेगी। यह लैंडर बेंगलुरु में आइडीएसएन के साथ-साथ ऑर्बिटर और रोवर से संपर्क स्थापित कर सकेगा।

रोवर प्रज्ञान: रोवर प्रज्ञान का नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। 27 किलोग्राम वजन वाले इस रोवर पर दो पेलोड लगे हैं। यह छह पहियों वाला एक रोबोटिक वाहन है। सौर ऊर्जा की मदद से यह एक सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल सकेगा। इसे भी चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिन के बराबर काम करने के लिए बनाया गया है। इस पूरी अवधि में यह चांद की सतह पर कुल 500 मीटर की दूरी तय करेगा।

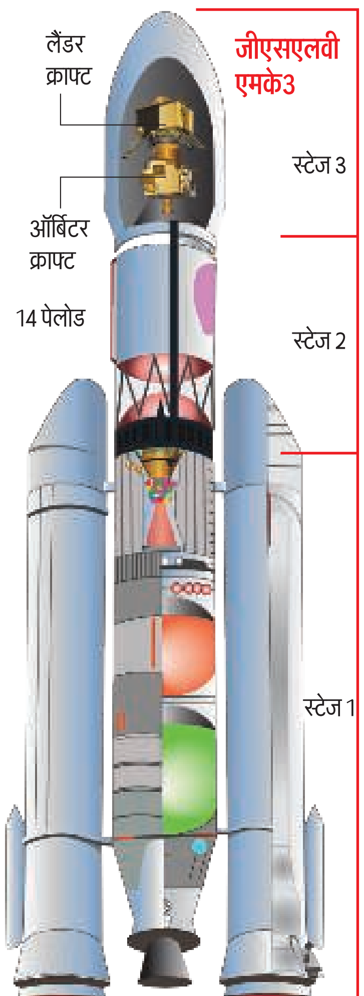

शुभ हो 54 दिन की चांद यात्रा

अपने पहले ही अभियान चंद्रयान-1 से चंद्रमा पर पानी होने की खोज करके भारत ने अपने इरादे जता दिए थे कि भले ही देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। अब तक तीन देश अपने मिशन चंद्रमा पर उतार चुके हैं। अब बारी हमारी है। दुनिया की टकटकी इसलिए भी लगी है क्योंकि भारत का यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के उस हिस्से पर उतरेगा, जहां अब तक कोई देश नहीं जा सका है। लिहाजा किसी अप्रत्याशित खोज को लेकर सबकी उम्मीदें लगी हैं। 54 दिन की अपनी यात्रा पूरी करके जब लैंडर से निकल प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर चलेगा तो हर भारतीय का सीना तारे तोड़ लेने के गर्व से चौड़ा हो जाएगा।

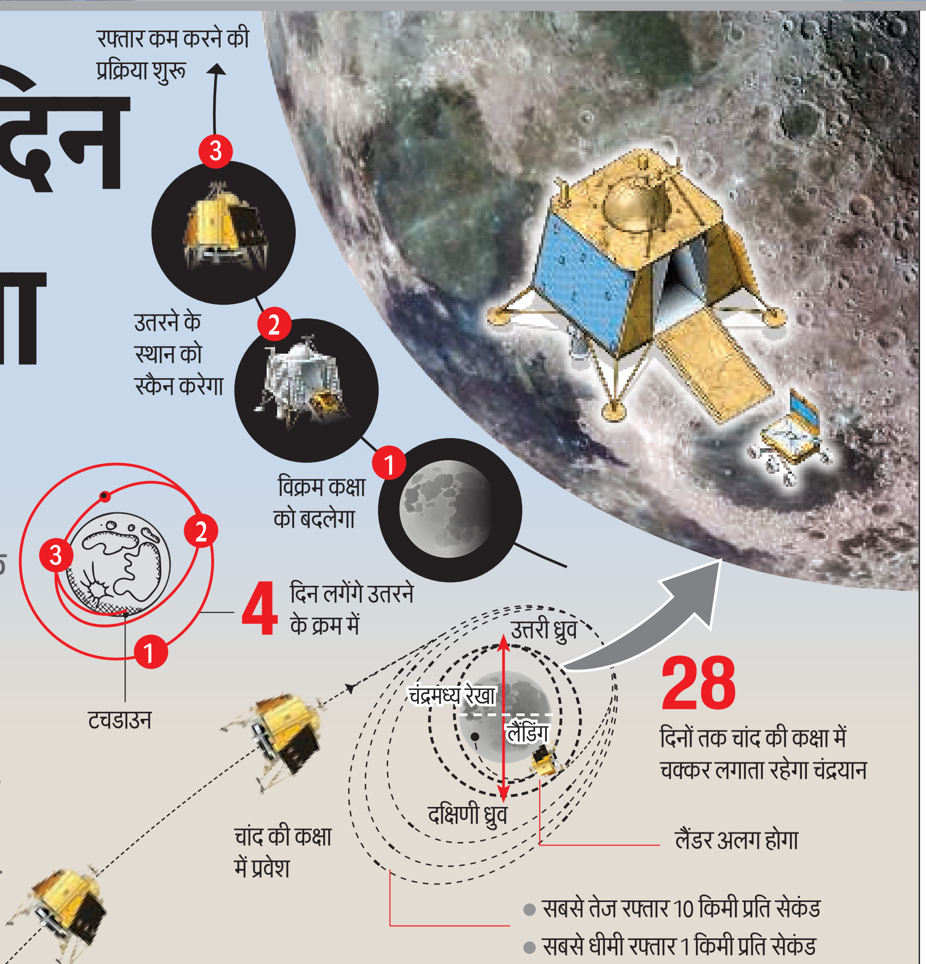

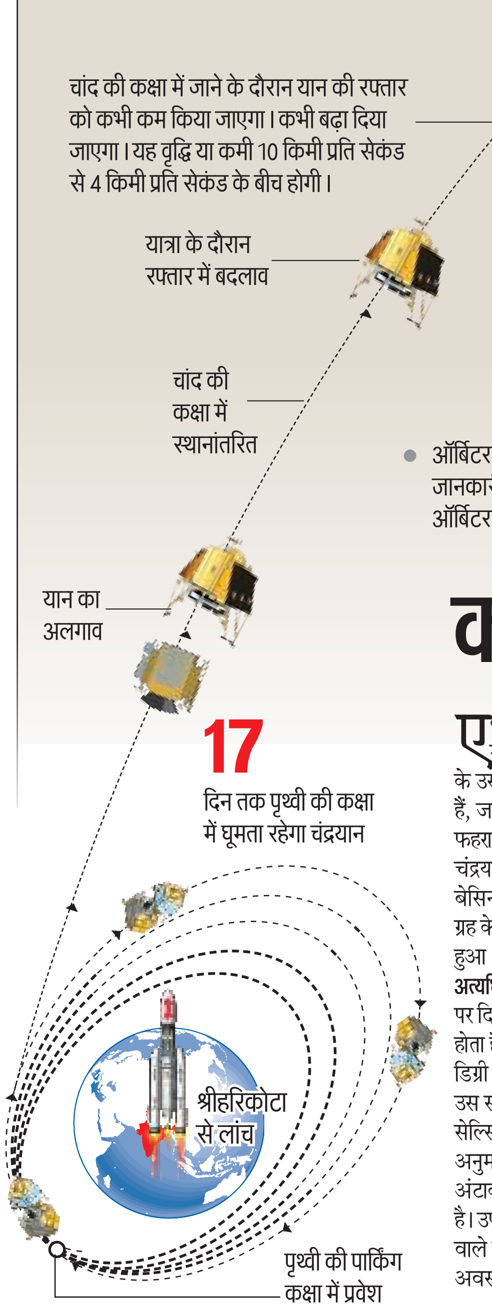

मिशन की लागत

₹978 करोड़

₹5759 करोड़

चांग ई-4 अभियान पर चीन का खर्च

रोवर

लैंडिंग के चार घंटे बाद विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर निकलकर चांद की जमीन पर चलेगा और अध्ययन में जुट जाएगा।

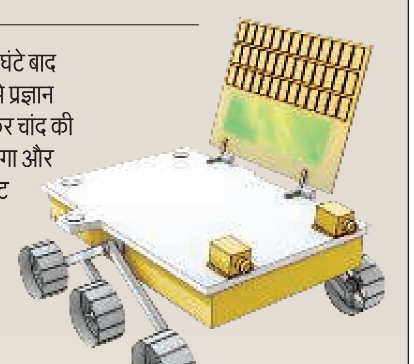

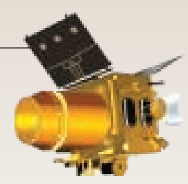

- ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर एक साल तक चक्कर लगाएगा। रोवर प्रज्ञान जानकारी को लैंडर विक्रम से साझा करेगा। विक्रम उस जानकारी को ऑर्बिटर तक पहुंचाएगा। ऑर्बिटर उसे धरती के कमांड सेंटर तक भेजेगा।
- चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर करीब आधा किमी की दूरी नापेगा।

कठिन मौसम की गंभीर चुनौतियां

एक तो चंद्रमा पर पहुंचना ही बहुत मशक्कत का काम है, दूसरे भारत ने चांद के उस स्थान पर पहुंचने की चुनौती स्वीकारी हैं, जहां आज तक किसी देश का झंडा नहीं फहराया है। अपने 54 दिन के अभियान में चंद्रयान-2 चांद के दक्षिणी ध्रुव के एटकेन बेसिन में उतरेगा। इस स्थान पर कभी क्षुद्र ग्रह के टकराने से बने गड्ढे से लावा का प्रवाह हुआ था।

अत्यधिक गर्म और सर्द मौसम: चंद्रमध्य रेखा पर दिन का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि रात में यह तापमान -130 डिग्री तक पहुंच जाता है। विक्रम जहां उतरेगा, उस स्थान का रात में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस सर्दी का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि यह अंटार्कटिका की रात से भी ज्यादा ठंड हो जाती है। उपकरणों और सेंसर्स में लगे ठोस अवस्था वाले इलेक्ट्रॉनिक्स ताप और ठंड की इस अवस्था से ऊपर काम करना बंद कर देते हैं।

तीन अभियानों ने ही बिताई है रात: अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में अब तक तीन ही ऐसे चंद्र अभियान हुए हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर रात बिताने में कामयाबी पाई है। इन सभी अभियानों में उपकरणों को गर्म रखने के लिए रेडियोआइसोटोप्स का इस्तेमाल किया गया था।

धूल का शूल: चंद्रमा पर मशीनों के लंबे समय तक काम करने में बड़ी बाधा वहां की धूल है। चूंकि चंद्रमा पर कोई मौसम प्रणाली नहीं है लिहाजा वहां धूल के कण बहुत धारदार हो जाते हैं। 2005 में नासा की एक तकनीकी रिपोर्ट बताती है कि इस धूल ने कैसे उतरते समय दृश्यता की बाधा पैदा की, मशीनों का काम प्रभावित किया। एक्स्ट्रा वेहिकुलर मोबिलिटी सूट और उपकरणों के कवर को फाड़ दिया। रेडिएटर्स के प्रदर्शन को कमजोर कर दिया। लोगों की आंखों और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाया। अपोलो ल्युनर रोवर व्हीकल के चंद्रयात्रियों का कीमती समय चंद्रमा की धूल को साफ करते हुए बीता। उनके ऊपर धूल की परत होने के चलते सौर ऊर्जा सोखने की दर अप्रत्याशित रूप से कई गुना बढ़ गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव के जिस हिस्से में उतरने वाला है वहां धूल की बड़ी समस्या है।

सही सलामत उतरना: किसी भी चंद्र अभियान के लिए लैंडिंग सबसे बड़ी तात्कालिक चुनौती होती है। बीते अप्रैल महीने में इजरायल के एक निजी मिशन के तहत बेरेशीट लैंडर को चांद पर उतरना था, लेकिन उतरते समय उसकी गति ही धीमी नहीं हो सकी और वह विफल हो गया। चंद्रयान दो में लैंडर चांद की सतह से 100 किमी की ऊंचाई से उतरने के लिए ऑर्बिटर से निकलेगा। उतरते समय उस स्थान की तस्वीरें लेता रहेगा और 30 किमी की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद स्वतः ही तय करेगा कि उतरने के लिए कौन सा स्थान मुफीद होगा। चिंता इस बात की होती है कि उतरने वाला स्थान चट्टानी इलाका नहीं होना चाहिए।

अभियान के पेलोड

दूसरे चंद्र अभियान में कुल 14 पेलोड को शामिल किया गया है। इनमें से आठ पेलोड ऑर्बिटर पर, तीन पेलोड लैंडर पर और दो पेलोड रोवर पर हैं। हर पेलोड के हिस्से में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग को अंजाम देने की जिम्मेदारी रहेगी। इनके अलावा एक लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर ऐरे (एलआरए) पेलोड भी होगा। इससे चांद की आंतरिक बनावट को लेकर जानकारी मिलेगी।

ऑर्बिटर के पेलोड

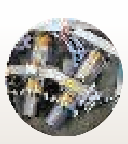

1. **टेरैन मैपिंग कैमरा :** यह कैमरा पूरे चांद का डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार करेगा।

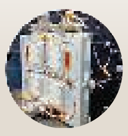

2. **लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर :** चांद की सतह के घटकों का परीक्षण करेगा।

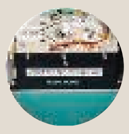

3. **सोलर एक्स-रे मॉनीटर :** सोलर एक्स-रे स्पेक्ट्रम का इनपुट मुहैया कराएगा।

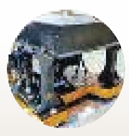

4. **इमेजिंग आइआर स्पेक्ट्रोमीटर :** खनिजों के आंकड़े जुटाएगा और बर्फ की मौजूदगी के प्रमाण तलाशेगा।

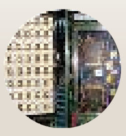

5. **सिंथेटिक अपर्चर रडार एलएंडएस बैंड्स :** ध्रुवीय क्षेत्र को खंगालेगा और सतह के नीचे बर्फ की उपस्थिति के प्रमाण जुटाएगा।

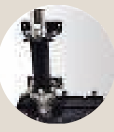

6. **एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर-2 :** चांद के वातावरण का अध्ययन करेगा।

7. **ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा :** चांद की सतह की तस्वीरें लेगा।

8. **डुअल फ्रिक्वेंसी रेडियो साइंस एक्सपेरिमेंट :** चांद के आयनोस्फेयर का अध्ययन करेगा।

लैंडर के पेलोड

1. **इंस्ट्रूमेंट फॉर लुनार सिस्मिक एक्टिविटी :** लैंडिंग साइट पर भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाएगा।

2. **सर्फेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट :** चांद के थर्मल कंडक्टिविटी का अध्ययन करेगा।

3. **लैंगम्यूर प्रोब :** चांद की सतह का अध्ययन करेगा।

रोवर के पेलोड

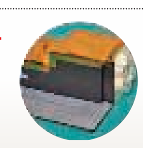

1. **अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर :** चांद की सतह पर घटकों का विश्लेषण करेगा।

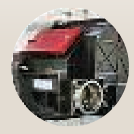

2. **लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप :** लैंडिंग साइट के आसपास विभिन्न घटकों की उपस्थिति जांचेगा।

इसरो की विजयगाथा

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का अबतक का सफर काबिल-ए-तारीफ है। एक समय ऐसा भी था जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पास संसाधनों की कमी की वजह से रॉकेटों को बैलगाड़ी-साइकिल से प्रक्षेपण स्थल ले जाया गया था। लेकिन समय के हिसाब से भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मेहनत की वजह से भारत आज इस क्षेत्र में नए-नए आयाम छू रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की चमत्कारिक उपलब्धियों पर एक नजरः

ऐसे शुरू हुआ सफर

डॉ. साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी। इसरो की स्थापना से पहले साल 1963 में भारत ने पहला रॉकेट छोड़ा था, जिसे साइकिल पर लादकर केरल के थुंबा गांव में स्थित प्रक्षेपण स्थल पर लाया गया था। भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों को लांचिंग पैड बनाया था। समुद्र किनारे खड़े नारियल के पेड़ों पर इस रॉकेट को बांधा गया था। और फिर सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे लांच किया। इस मिशन का दूसरा रॉकेट काफी बड़ा और भारी था, जिसे बैलगाड़ी के सहारे प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया था।

नहीं था दफ्तर

हमारे वैज्ञानिकों के पास अपना दफ्तर नहीं था, वे कैथोलिक चर्च सेंट मैरी मुख्य कार्यालय में बैठकर सारी प्लानिंग करते थे।

आर्यभट्ट, 1975 : आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान जिसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर रखा गया था, देश का पहला उपग्रह था। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह पूरी तरह से स्वदेशी था और 1975 में सोवियत संघ की मदद से इसे लांच किया गया था।

एसएलवी-3, 1980 : भारतीय वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी लांचिंग व्हीकल एसएलवी-3 तैयार किया। इससे 18 जुलाई 1980 को रोहिणी सेटेलाइट को प्रक्षेपण के तौर पर लांच किया गया था।

इंडिया नेशनल सेटेलाइट सिस्टम, 1983 : इनसैट के नाम से लोकप्रिय यह सेटेलाइट सिस्टम उपग्रहों की एक सीरीज, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संचार और प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है। इस सीरीज का पहला उपग्रह 1983 में कक्षा में स्थापित किया गया था। जिसके बाद भारत में टेलीविजन, रेडियो प्रसारण, दूरसंचार और मौसम क्षेत्रों में एक क्रांति की शुरुआत हुई। इनसैट कार्यक्रम के दौरान अंतरिक्ष में भेजे गए 24 उपग्रहों में से 11 अभी भी सक्रिय हैं।

पोलर सेटेलाइट लांच व्हीकल, 1993 : 1990 से इसके निर्माण का काम शुरू हुआ। पीएसएलवी ने 1993 में अपना पहला मिशन पूरा किया। अगले 20 वर्षों के लिए, इसने चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशनों के लिए विभिन्न उपग्रहों को लांच किया। पीएसएलवी एक लांच सेवा प्रदाता के रूप में विभिन्न संगठनों के बीच पसंदीदा है और 19 देशों के लिए 40 से अधिक उपग्रहों को लांच कर चुका है।

चंद्रयान-1, 2008 : यह चंद्रमा पर भेजे जाना वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान था। इस मानवरहित अंतरिक्ष यान को 22 अक्टूबर, 2008 को लांच किया गया था। 8 नवंबर 2008 को यह यान चंद्रमा पर पहुंच गया था। इसने चंद्रमा की कक्षा में 312 दिन बिताए थे। इसने चंद्रमा पर भारत का झंडा भी फहराया। सितंबर 2009 में नासा ने एलान किया था कि चंद्रयान -1 के डाटा को चंद्रमा पर बर्फ होने के सुबूत मिले। यह मिशन दो साल का था, लेकिन उसमें खराबी आने के कारण मिशन एक साल में ही समाप्त हो गया। इस परियोजना के लिए अनुमानित लागत 386 करोड़ रुपये थी।

मंगलयान, 2014 : भारत ने 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह के लिए अपना मंगलयान लांच किया था। 24 सितंबर 2014 को इस यान ने मंगल की कक्षा में पहुंचकर इतिहास रच दिया था और इसके साथ मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश और पहले प्रयास में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना गया था। इसरो ने इस मानवरहित सेटेलाइट को मार्स ऑर्बिटर मिशन नाम दिया। इसका निर्माण भारतीय वैज्ञानिकों ने किया और इसे भारत की धरती से भारतीय रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। इस अभियान पर 450 करोड़ रुपये का खर्च आया।

एक साथ भेजे 104 सेटेलाइट

इसरो ने 15 फरवरी, 2017 को एक साथ 104 सेटेलाइट को लांच करके नया इतिहास रचा दिया। इससे पहले किसी एक अभियान में सबसे ज्यादा उपग्रह भेजने का विश्व रिकॉर्ड रूस के नाम था, जिसने 2014 में एक अभियान में 37 उपग्रहों को भेजने का काम किया था। इस अभियान में भेजे गए 104 सेटेलाइट में से तीन भारत के थे। जबकि बाकी 101 इजरायल, कजाखिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के थे।

बदायूं का युवक चंद्रयान के सफर के निगहबान में शामिल

प्रसून शुक्ल, बरेली

15 जुलाई को चंद्रयान-2 अपने मुकाम की तरफ बढ़ चलेगा। अमेरिका, रुस और चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश होगा जो अपना यान चांद पर उतारेगा। चंद्रयान-2 के पूरे मिशन की कामयाबी में रुहेलखंड के सतपाल अरोरा भी हमसाया बनेंगे। सतपाल अरोरा मूल रूप से बदायूं के उझानी के रहने वाले हैं। वे इन दिनों इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और चंद्रयान-2 मिशन में खास हिस्सा हैं। उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वह पूरी प्रक्रिया में 'पिन प्वाइंट' मानी जा रही है। सेंसर सपोर्ट सिस्टम के तौर पर रॉकेट के तापमान का आकलन करना और उसके बदलाव पर नजर रखकर यान को उसकी कक्षा में स्थापित कराने का अहम मोड़ सतपाल की देख-रेख में एक खास टीम को करना है। मंगलयान मिशन पर असेंबली इंचार्ज की भूमिका निभा चुके सतपाल सेटेलाइट पीएसएलवी या मार्स सेटेलाइट सिस्टम जैसी अहम महत्वाकांक्षी योजनाओं में निरंतर सक्रिय रह चुके हैं।

चंद्रयान-2 की लांचिंग में रामपुर के संदीप भी : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के चंद्रयान-2 की लांचिंग में इसरो के अन्य वैज्ञानिकों के साथ ही रामपुर के संदीप चौहान का भी योगदान होगा। संदीप इससे पहले चंद्रयान-1 के प्रेक्षपण में योगदान दे चुके हैं। संदीप के पिता सीआरपीएफ रामपुर में हवलदार थे। उनके बड़े भाई डॉ. कुलदीप चौहान परिवार के साथ रामपुर में रहते हैं। उन्होंने बताया कि संदीप ने चंद्रयान-2 का बेस तैयार किया है। साथ ही लांचिंग पैड, व्हीकल और व्हीकल फ्यूलिजन तैयार करने वाली टीम में वह शामिल रहे।

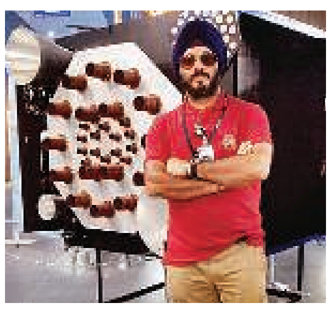

इसरो वैज्ञानिक सतपाल अरोरा उर्फ मिक्कू की उनके परिवार द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीर।

> चंद्रयान-2 का मकसद है कि चांद पर संभावनाएं तलाशे। क्या वहां कुछ तरल है या आइस है, या फिर वहां के बारे में निरंतर हो रहे बदलाव की गणना और आकलन हमारा लक्ष्य है, ताकि हम उनका विश्लेषण कर सकें।
>
> **-सतपाल अरोरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, इसरो**

'चांद' पर आइआइटी कानपुर

जागरण संवाददाता, कानपुर

मिशन चंद्रयान-2 के लिए उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। चंद्रयान जब धरती से चंद्रमा के लिए उड़ेगा, तब आइआइटी कानपुर भी चांद पर होगा। आइआइटी कानपुर को यह उपलब्धि दिलाने वाले प्रो. आशीष दत्ता और प्रोफेसर केएस वेंकटेश उस क्षण की कल्पना कर जहां बेहद रोमांचित हो रहे हैं, वहीं खुद को भी चांद पर महसूस कर रहे हैं। चंद्र अन्वेषण अभियान के लिए भेजे जा रहे चंद्रयान के रोवर 'प्रज्ञान' के लिए आइआइटी कानपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर केएस वेंकटेश व मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर आशीष दत्ता ने मोशन प्लानिंग एवं मैप जेनरेशन सॉफ्टवेयर तैयार कर लूनर रोवर पर सफल परीक्षण किया था। यह सॉफ्टवेयर इसरो को दिया गया, जो चंद्रमा पर रोवर प्रज्ञान को राह दिखाएगा।

रविवार को प्रो. आशीष दत्ता दिनभर अपनी प्रयोगशाला में रहे और आइआइटी में बनाए गए 'लूनर रोवर' के अनुभव बांटे। कहा, चंद्रयान-2 अभियान सफल होगा। इस अभियान का हिस्सा होने के नाते मैं खुद को चांद पर महसूस कर रहा हूं। यह सॉफ्टवेयर चंद्रमा पर उतरने के बाद वहां पानी व खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिए रोवर को राह दिखाएगा। रोवर के सामने क्या चुनौतियां होंगी, इस पर प्रो. दत्ता ने कहा कि छह सितंबर को चंद्रयान-2 के चंद्रमा पर उतरने के बाद पता चलेगा कि क्या-क्या चुनौतियां हैं।

रोवर की मुश्किलें खत्म करेगा सॉफ्टवेयर : प्रो. दत्ता ने बताया कि अभी यह पता नहीं है कि चंद्रमा पर पानी कहां है। कौन-कौन सी बाधाएं हैं, जिन्हें पार करके वहां पहुंचा जा सकता है। मोशन प्लानिंग व मैप जनरेशन के लिए आइआइटी में बनाया गया यह सॉफ्टवेयर चंद्रमा पर रोवर की मुश्किलें खत्म करके राह दिखाएगा। एलगोरिदम के तहत विकसित यह सॉफ्टवेयर पानी की तलाश के साथ उसे जमीन से निकालने में भी रोवर की मदद करेगा।

आइआइटी कानपुर में बनाए गए लूनर रोवर के साथ प्रो. आशीष दत्ता। जागरण

मिशन में बिहार का भागलपुर भी कर रहा कदमताल

अमरेन्द्र कुमार तिवारी, भागलपुर

अंतरिक्ष में एक और सफलता की ओर बढ़ रहे भारत के साथ बिहार के भागलपुर भी कदमताल कर रहा है। शहर और पूरे बिहार को गौरव का यह खूबसूरत पल दिया है भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्र अमरदीप कुमार ने, जो मिशन चंद्रयान-2 की टीम में शामिल हैं। वे इस समय इसरो के वरीय वैज्ञानिक हैं। अमरदीप देवघर के रहने वाले हैं। वह कहते हैं, 'आज जिस मुकाम पर हूं, उसकी बुनियाद भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में ही तैयार हुई।'

प्रोजेक्ट ग्रुप में हैं शामिल : 603 करोड़ की लागत से 3.8 टन वजन वाले चंद्रयान-2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाले इसरो के सबसे भारी रॉकेट जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हीकल मार्क-3 (जीएसएलवी एमके-3) के पहले चरण के प्रोजेक्ट ग्रुप में अमरदीप ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसरो में 12 साल काम कर चुके अमरदीप बताते हैं कि वे पहले चरण में एल110 में काम करते हुए त्रिवेंद्रम में अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रिपोर्ट करते थे। इस इंजन में 110 टन ईंधन भरा होता है, जो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल का सामना करता है। इसकी ऊंचाई 21 मीटर और परिधि चार मीटर होती है। इसमें यूडीएमएच प्लस एन204 का 110 टन ईंधन भरा होता है। यह जीएसएलवी एमके 3 के लिए अति महत्वपूर्ण पार्ट है।

मानव मिशन यान में काम करने की तमन्ना : उन्होंने कहा कि अभी दो वर्षों से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अध्ययनरत हैं। यह अगस्त में पूरा हो जाएगा। इसके बाद गगनयान में काम करने की योजना है। यह भारत का पहला मानव मिशन यान होगा। इस यान में भी उक्त रॉकेट का ही उपयोग किया जाएगा।

अपने संस्थान के छात्र पर गर्व है : भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अचिन्त्य कुमार का कहना है कि यहां के छात्र काफी मेधावी रहे हैं। देश के विकास में महती भूमिका निभा रहे हैं। इसरो सहित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। इससे संस्थान का भी राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ रहा है। हमें अपने छात्रों पर गर्व है।

70 लाख आबादी है कश्मीर घाटी की, इनमें 97 फीसद मुस्लिम हैं। करीब दो दशक पहले कश्मीर में हिंदुओं की आबादी पांच फीसद थी, जो अब न के बराबर है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 15 जुलाई 2019

न्यूज गैलरी

कश्मीर के कुलगाम में हुए धमाके में दो घायल

जम्मू : दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के देवसर में रविवार को हुए एक धमाके में दो लोग घायल हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार यह धमाका उस समय हुआ जब दो युवाओं ने सड़क पर पड़ी बालनुमा चीज को छूने की कोशिश की। उनके छूते ही धमाका हो गया। इससे दोनों युवक घायल हो गए। घायलों की पहचान सुहेल अहमद भट निवासी अडीगाम और संदीप कुमार के रूप में हुई है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. मुजफ्फर जरगर ने बताया कि दोनों की हालत स्थिर है। धमाके की जांच की जा रही है। (राब्यू)

उत्तरकाशी में भूकंप के हल्के झटके, कोई नुकसान नहीं

उत्तरकाशी : उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद की यमुना घाटी में रविवार की शाम 3.42 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप आने पर लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि, किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी जिले के बड़कोट के निकट ब्याली गांव के पास था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता तीन मापी गई। इससे पहले उत्तरकाशी में छह जुलाई को भी भूकंप आया था। उसकी तीव्रता 3.1 मापी गई थी। (जासं)

हिमाचल में चार मंजिला इमारत ध्वस्त एक जवान समेत दो की गई जान

हादसा ▶ सेना के जवानों सहित 37 लोग दबे, 25 को सकुशल निकाला

सेना, सीआरपीएफ और पुलिस सहित एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा

जागरण संवाददाता, सोलन

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कुमारहट्टी में रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुमंजिला इमारत ढह गई। इससे उसमें सेना के जवानों सहित 37 लोग दब गए। अब तक 25 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। जबकि दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें एक सेना का जवान भी शामिल है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्य देर रात तक जारी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हादसे पर दुख जताया है।

रविवार दोपहर बाद कुमारहट्टी बाजार से एक किलोमीटर आगे नाहन रोड पर स्थित सहज तंदूरी ढाबा और चार मंजिला इमारत गिर गई। हादसे के समय ढाबे में भोजन करने आए सेना के जवान और स्थानीय लोग मौजूद थे। भवन गिरते ही आसपास हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही धर्मपुर से पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। भवन में दबे सेना के जवान डगशाई छावनी के थे। कसौली, डगशाई और सुबाथू छावनी से भी सेना के जवान और अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोग, पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ की टीम बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं।

बारिश से राहत कार्य प्रभावित : वहीं, भारी बारिश के चलते बचाव कार्य भी प्रभावित हुआ और हादसे के एक घंटे बाद घायलों को बाहर निकालने में सफलता मिली। जवानों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया और नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया। हालांकि भवन कैसे गिरा इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। समाचार लिखे जाने तक एक महिला और एक जवान के मरने की पुष्टि हो चुकी है। सोलन के उपायुक्त केसी चमन जिले के आलाधिकारियों समेत मौके पर डटे हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश के सोलन में रविवार को कुमारहट्टी-नाहन मार्ग पर एक इमारत मूसलधार बारिश के चलते ढह गई। एएनआइ

उप्र पुलिस ने दिल्ली जाकर दी अजितेश और साक्षी को सुरक्षा

जागरण संवाददाता, बरेली

विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी का अजितेश से प्रेम विवाह करना और साक्षी का अपने पिता से जान का खतरा जताते हुए वीडियो तो वायरल किया लेकिन स्थानीय पुलिस-प्रशासन से सुरक्षा नहीं मांगी। बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की, लेकिन इनके खुद न उपस्थित होने से अगली सुनवाई 15 जुलाई को होनी है। मामला जब मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट तक पहुंचा तो पुलिस ने दोनों को ढूंढ़ना शुरू कर दिया। रविवार को उप्र पुलिस को आखिरकार दोनों दिल्ली में मिल गए। जहां उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई। कल दोनों हाईकोर्ट में पेश हो सकते हैं।

पिछले दो दिनों से साक्षी और अजितेश चैनलों पर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे थे। साक्षी अपने विधायक पिता से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग तो कर रही थी। लेकिन साक्षी या अजितेश ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से संपर्क नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने खुद दोनों को ढूंढ़ना शुरू किया। शनिवार को इज्जतनगर थाने से एक दारोगा व तीन सिपाही नोएडा गए। यहां पता चला कि दोनों दिल्ली में हैं। इसके बाद पुलिस टीम दिल्ली गई। जहां दोनों मिल गए हैं। दोनों को पुलिस सुरक्षा दी गई। अब दोनों दिल्ली में बरेली पुलिस की सुरक्षा में हैं।

इधर, सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में तारीख है। हाईकोर्ट में दोनों के मामले में सुनवाई होनी है।

योगी के पास पहुंचा साजिश का मामला

जागरण संवाददाता, बरेली : साक्षी के अजितेश से प्रेम विवाह करने का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है, जिसके बाद गहन जानकारी जुटाई जा रही है। मामला जब बरेली से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गया, तब राजेश मिश्रा ने अपनी ही पार्टी के दो विधायकों पर साजिश करने का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने सीधे किसी का नाम नहीं लिया था। इससे पार्टी में खलबली मची हुई है। एक पुराने मामले में शनिवार को पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी गौरव अरमान की गिरफ्तारी के बाद बिथरी चैनपुर की राजनीति में हलचल मची हुई है। गौरव अरमान की गिरफ्तारी को भी मामले में साजिशकर्ताओं की मुख्य कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं : कोर्ट

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

मेट्रो सिटी में शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने और फिर दुष्कर्म का आरोप लगाकर प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराने की वारदात आम हो चुकी है। ऐसे ही एक मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली युवती की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यदि शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाया जाता है तब भी यह दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि युवती के बयान में विरोधाभास है और उसके बयान पर भरोसा करके युवक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि एक तरफ युवती का कहना है कि युवक ने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और दूसरी तरफ वह यह भी आरोप लगा रही है कि युवक ने उसके वीडियो-ऑडियो क्लिप को सार्वजनिक करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीठ ने सुबूतों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि युवती ने मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टर से कहा कि उसने अपनी मर्जी से युवक से शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही उसने मेडिकल रेप-किट की जांच कराने से भी इन्कार कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि युवती ने कहीं भी घटना का समय और तारीख नहीं बताया। उसने अपने बयान में कहा कि उसके साथ सात महीने तक दुष्कर्म हुआ, जबकि उसके घर के पास सात से आठ परिवार रहते थे। ऐसे में यह मानना संभव नहीं है कि सात महीने तक दुष्कर्म होने के बाद भी युवती किसी से अपनी बात नहीं कह सकती थी।

यह है मामला

वर्ष 2015 में सब्जी मंडी थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में युवती ने कहा था कि उसका पति नौकरी नहीं करता था और बीमार रहता था। वह अपनी समस्या पड़ोस के युवक से साझा करती थी। कुछ वक्त में दोनों करीब आ गए और पहले तो युवक ने उससे शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उससे दूर होने लगा। युवती ने जब शादी के लिए कहा तो उसने धमकी दी कि वह उसकी आपत्तिजनक वीडियो-ऑडियो क्लिप सार्वजनिक कर देगा। तीस हजारी कोर्ट ने 26 मार्च 2019 को युवती के बयान और सुबूतों का परीक्षण करने के बाद युवक को बरी कर दिया था।

कश्मीरी पंडितों की मर्जी नहीं, जरूरत है अलग टाउनशिप : सत्यपाल मलिक

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▶ राज्यपाल ने कहा, जिन लोगों ने कब्जा किया है, वही लौटाएं तो सबसे अच्छा

▶ मलिक बोले, कश्मीरी नेता पंडितों को घाटी में वापस बुलाएं

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में अलग टाउनशिप उनकी मर्जी का मामला नहीं बल्कि समय की जरूरत है। कश्मीरी नेताओं को चाहिए कि वे पंडितों को सम्मानपूर्वक वापस बुलाएं। इसका सही रास्ता यह है कि जिन्होंने घरों पर कब्जे किए हैं। वही लोग उन्हें वापस बुलाकर उनका घर लौटाएं।

श्रीनगर में एक साक्षात्कार में राज्यपाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सांसद डॉ. फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और हुर्रियत नेताओं का सहयोग जरूरी है। वे अपने लोगों को समझाएं। मेरा काम पंडितों को वैकल्पिक व्यवस्था देना है जहां पर सुरक्षा हो, स्कूल हो और अन्य सुविधाएं हों। उन्होंने कहा कि पंडित इसी वादी में रहे हैं और बड़े हुए हैं। ऐसे में जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के घर छीने हैं, वही उन्हें लौटा दें तो अच्छा कदम माना जाएगा। कश्मीर के नेताओं को एकता का संदेश देना है। क्या उनमें से ऐसा कोई करेगा। सत्यपाल ने कहा कि अलग टाउनशिप उनकी मर्जी का मामला नहीं, बल्कि जरूरत है। हम उन्हें उनकी मर्जी की अच्छी जगह रहने के लिए देंगे। कश्मीर में ऐसी बहुत जगहें हैं जहां वह रहना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें वह दी जाएगी।

अनुच्छेद 35-ए पर मलिक ने फिर दोहराया कि जब राज्य में चुनी हुई सरकार आएगी। वही इस मुद्दे पर फैसला लेगी। एक सवाल के जवाब में राज्यपाल ने कहा, इस समय राज्य में अमरनाथ यात्रा के अलावा हज यात्रा भी चल रही है। कश्मीर में पूरी तरह से शांति है। गत दिनों प्रशासनिक अधिकारी जब आतंकी बुरहान वानी के गांव में पंचायत का काम करवाने के लिए गए तो लोगों ने उनका स्वागत किया। अमरनाथ यात्रा के दौरान हाईवे व कुछ मार्ग बंद करने पर राज्यपाल ने कहा कि यह सब ट्रैफिक प्रबंधन के लिए किया है। अगर ऐसा न किया जाए तो सड़कों पर जाम होंगे। स्थानीय लोगों से कहा जाता है कि यात्रियों को जाने दो, इसके बाद आप भी चले जाओ। अगर किसी को अस्पताल या फिर स्कूल में जाना होता है तो वे अपना पहचान पत्र दिखाकर चले जाते हैं।

अलग टाउनशिप का समर्थन नहीं करते हैं नेता

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और सांसद फारूक अब्दुल्ला कई बार कह चुके हैं कि पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। मगर वे अलग टाउनशिप का समर्थन नहीं करते हैं। वे उन्हें जहां से पंडित उजड़े हैं वहीं बसाने की वकालत कर रहे हैं। गत दिनों अलगाववादी मीरवाइज मौलवी उमर फारूक भी कश्मीर पंडितों को वापसी का न्योता दे चुके हैं।

साक्षी के बाद अब सुर्खियों में प्रयागराज की दीक्षा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

▶ प्रयागराज के पूर्व उप महापौर की पोती ने दूसरे जाति की युवक से की शादी

बरेली के भाजपा विधायक की बेटी साक्षी के बाद अब प्रयागराज के पूर्व उप महापौर की पोती दीक्षा अग्रवाल की कहानी सुर्खियों में आ गई। दीक्षा ने गैर बिरादरी के ऋतुराज सिंह से घरवालों की मर्जी के बगैर शादी कर ली। उसके लापता होने पर घरवालों ने सिविल लाइंस थाने में भोपाल के ऋतुराज और उसके घरवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दीक्षा ने शादी के बाद एक वीडियो जारी कर घरवालों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस के निवासी पूर्व उप महापौर मुरारी लाल अग्रवाल के बेटे पवन अग्रवाल की बेटी दीक्षा इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। पांच जुलाई 2019 की सुबह वह घर से निकली तो नहीं लौटी। खोजबीन के बाद 13 जुलाई को घरवालों ने भोपाल के रहने वाले ऋतुराज सिंह, उसके पिता बाल कृष्ण राजपूत और मां राजू देवी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। आरोप है कि ऋतुराज के बहकाने पर दीक्षा घर से 30 लाख रुपये के गहने, दो लाख रुपये लेकर चली गई। एफआइआर में लिखाया गया कि दीक्षा के नाम परिवार वालों ने करोड़ों की संपत्ति की है। उसी के लालच में उसे घर से भगाकर अगवा किया गया। रिपोर्ट दर्ज कर सिविल लाइंस पुलिस जांच कर रही है।

पूर्व उप महापौर ने दी सफाई : दीक्षा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह आरोप लगा रही है कि घरवाले उसे धमकी दे रहे हैं। मामले पर मुरारी लाल अग्रवाल ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि दीक्षा ने भोपाल के ऋतुराज से शादी कर ली है। इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं। हम लोग मिलने भोपाल गए थे। उसे आशीर्वाद देना चाहते थे, लेकिन ऋतुराज के घरवालों ने हमें भगा दिया। वहां चार दिन हम लोग भटकते रहे, फिर डीआइजी से मदद मांगी। उन्होंने भी बेटी से मिलाने से मना कर दिया। इसके बाद लौट आए। उनका कहना है कि ऋतुराज के घर वाले आरोप लगवा रहे हैं। यह सारी साजिश दीक्षा के नाम हुई संपत्ति हड़पने के लिए है।

योगी ने कहा, कांवड़ियों का अतिथि की तरह सत्कार करना है

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार धार्मिक स्थलों के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। वह रविवार को शिक्षा ऋषि वीतराग स्वामी कल्याणदेव महाराज की 15वीं पुण्यतिथि पर रविवार को मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई से सावन माह शुरू हो रहा है। कांवड़ अभियान को नई ऊंचाई देनी है। कांवड़ियों का अतिथि की तरह सत्कार करना है। सभी भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाओ, गंगा का आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि काशी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना और अयोध्या में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। इस धारा में शुकतीर्थ को भी जोड़ा जाएगा।

श्रीशुकदेव आश्रम परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी कल्याणदेव की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। गोशाला में गायों को चारा खिलाया। हवन में आहुति दी। इसके बाद सभागार में पहुंचकर दस करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुकतीर्थ में प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के अवशेष हैं। यहां बड़े-बड़े रेत के टीले 5000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को संजोए हुए हैं।

बनारस-दिल्ली नए रेल मार्ग पर दौड़ सकेंगी हाईस्पीड ट्रेनें

जागरण संवाददाता, वाराणसी

रेल प्रशासन ने बनारस से दिल्ली तक एक नया रूट बनाने का फैसला किया है। इस नए रूट की विशेष बात ये होगी कि इसमें लखनऊ को शामिल नहीं किया गया है। रेल प्रशासन ने वाराणसी से मुरादाबाद तक दोहरी नई रेल लाइन के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ऐसे में ये रूट तैयार होने के बाद बनारस से दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी समेत काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें बिना लखनऊ जाए दिल्ली की ओर जा सकेंगी। इसके लिए उन्नाव में एक रेल फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। हालांकि ये उन्नाव से कहां निकलेगा अभी तय नहीं है। इससे रेल प्रशासन दो तरह के लाभ की बात कर रहा है। पहला कि इस नए रूट से बनारस की ट्रेनें लखनऊ से कटकर उन्नाव होकर निकल जाएंगी। ऐसे में लखनऊ में ट्रेनों का दबाव कम हो जाएगा। दूसरा वाराणसी से दिल्ली तक एक दोहरे ट्रैक वाला नया रेलखंड तैयार होने से इस पर वंदे भारत और तेजस जैसी हाईस्पीड ट्रेनों को दौड़ाने में आसानी होगी।

इन जगहों का सफर होगा आसान : इस नए रेल खंड के बनने के बाद वाराणसी से जम्मूतवी, अमृतसर, दिल्ली व देहरादून जैसे स्थानों तक ट्रेनों को तेज रफ्तार पहुंचाने में आसानी होगी।

कुछ ऐसा होगा सफर

वाराणसी-उन्नाव	339 किमी वाया सुलतानपुर
उन्नाव-बालामऊ	100 किमी
बालामऊ-मुरादाबाद	257 किमी

बजट में उत्तर रेलवे की योजनाओं के लिए आवंटन

रेल परिचालन	322 करोड़ रुपये
ब्रिज, सुरंग व अन्य रेल सेतु	120 करोड़
सिग्नलिंग व सूचना तंत्र	309 करोड़
यार्ड सुविधा विस्तार	137 करोड़
कर्मचारी सुविधा	110 करोड़
रेल ओवर ब्रिज व अंडर पास	400 करोड़

सचिवालय की छत पर मोर्चे में तैनात जवान की गोली लगने से मौत

जासं, जम्मू : जम्मू शहर के बीचोबीच बने नागरिक सचिवालय की छत पर स्थित मोर्चा नंबर 13 में सुरक्षा के लिए तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान की गोली लगने से मौत हो गई। जवान को दो गोलियां लगीं, जो उसकी सर्विस राइफल से चली थीं। पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम करवाने के लिए सीआरपीएफ अधिकारियों को सौंप दिया। मृतक की पहचान कांस्टेबल पी राम कुमार पुत्र आर प्लानी स्वामी निवासी कासिम व्याल, जिला निलगरिस, तमिलनाडु के रूप में हुई।

नागरिक सचिवालय की छत से गोली चलने की आवाज से वहां दहशत फैल गई। मौजूदा समय में सचिवालय का कामकाज कश्मीर में चल रहा है, जिसके कारण सचिवालय की इमारत में केवल सुरक्षाकर्मी हीं तैनात हैं। गोली चलने की यह घटना रविवार शाम करीब चार बजे की है। इमारत की छत पर सुरक्षाकर्मियों का मोर्चा बना है। वहां ड्यूटी पर कांस्टेबल पी राम कुमार तैनात था। अचानक गोली चलने की आवाज से वहां तैनात सुरक्षाकर्मी सचिवालय की छत की और दौड़े। जवानों ने मोर्चे के भीतर कांस्टेबल का खून से सना हुआ शव देखा। कांस्टेबल का शव मोर्चे के अंदर बेंच पर पड़ा था।

कारगिल युद्ध में वायु सेना ने तोड़ दिया था पाकिस्तान की सेना का मनोबल

कारगिल युद्ध के 20 साल...

नई दिल्ली, आइएएनएस : कारगिल युद्ध के दौरान भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर फिर से कब्जा जमाने में वायु सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक पूर्व अधिकारी के मुताबिक अपने हमलों से वायु सेना ने पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया था। यह पहला युद्ध था जब वायु सेना ने जीपीएस का इस्तेमाल किया था। साथ ही रेकी और नवाचार के उपयोग ने कारगिल युद्ध की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मई 1999 में शुरू हुए कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने पर एयर वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त) मनमोहन बहादुर ने बताया कि वायु सेना ने इस दौरान 15000 फीट और उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित पोस्ट पर हथियार पहुंचाए। ऐसा विश्व में पहले कभी नहीं हुआ था। एयर चीफ मार्शल एवाई टिपनिस के तत्कालीन स्टाफ आफिसर रहे बहादुर ने कहा कि भारतीय वायुसेना के हमलों से पाकिस्तानी सेना को बहुत नुकसान हुआ, इससे उन चोटियों पर कब्जा जमाने में सेना को बहुत सहूलियत हुई, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। टाइगर हिल पर सटीक तौर पर लेजर गाइडेड बम (एलजीबी) के हमले भारतीय वायु सेना के चलते ही संभव हो सके। ग्रुप कैप्टन (सेवानिवृत्त) संदीप मेहता ने बताया कि पाक के आपूर्ति डिपो पर सटीक हमले वायुसेना द्वारा जुटाई गई सटीक खुफिया सूचनाओं के कारण ही संभव हो सके थे। चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे दुश्मनों की सही संख्या के बारे में पता लगाने के लिए भी तमाम नवाचारों का उपयोग किया था।

बांध केसरिया बाना दुश्मनों को खदेड़ने की खाई थी कसम : तोलोलिंग चोटी पर कब्जा जमाए बैठे घुसपैठिए गोलियों की बारिश कर रहे थे, लेकिन 2 राजपूताना राइफल्स के सैनिकों ने अपने सिर पर केसरिया बाना बांधकर प्रण कर लिया था कि चोटी पर फिर से कब्जा किए बिना वे वापस नहीं लौटेंगे। इस दौरान बुरी तरह घायल हुए और उन्हीं वजहों से समय से पहले सेवानिवृत्त हुए कैप्टन अखिलेश सक्सेना ने कहा कि एक जून को 'तोलोलिंग' और 29 जून को '3 पिंपल्स' चोटी पर फिर से कब्जा करने में कई बहादुर सैनिकों को अपनी शहादत देनी पड़ी। इनमें कैप्टन विजयंत थापर और मेजर पद्मपति आचार्य भी शामिल थे। अत्यधिक खून बहने से अधिकांश सैनिकों की मौत हुई थी। टाटा पावर में उपाध्यक्ष सक्सेना की कारगिल युद्ध शुरू होने से एक महीने पहले ही शादी हुई थी और 3 पिंपल्स की लड़ाई के दौरान सक्सेना बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्होंने युद्ध के दौरान बोफोर्स तोप की भूमिका की भी तारीफ की।

पुलवामा ने दिखाया कि भारत हमला करने में संकोच नहीं करेगा : पार्थसारथी

यह ठीक है कि बार-बार पिटने के बावजूद पाकिस्तानी सेना का रवैया नहीं बदला है, लेकिन पुलवामा के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक से यह साफ हो गया है कि भारत ऐसा हमला फिर से करने में संकोच नहीं करेगा। यह मानना है कि कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान में उच्चायुक्त रहे जी पार्थसारथी का। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध से अंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंतित था, लेकिन चीन सहित किसी भी देश ने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि वर्तमान इमरान सरकार निर्वाचित नहीं, बल्कि सेना द्वारा चुनी गई सरकार है।

तैयारी

वन विभाग की अनुसंधान शाखा पहली बार करेगी जैव विविधता के अनछुए पहलुओं पर शोध, अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक में दी गई विभिन्न शोध कार्यों को मंजूरी

उत्तराखंड वन विभाग सहेजेगा कीटभक्षी पौधे, उड़न गिलहरी को भी संरक्षण

राज्य ब्यूरो, देहरादून

जैव विविधता के लिए मशहूर उत्तराखंड में जैव विविधता से जुड़े अनछुए पहलुओं पर वन विभाग की अनुसंधान शाखा पहली बार अनुसंधान करेगी। इसके तहत हिमालयी क्षेत्र में मिलने वाले कीटभक्षी पौधे सहेजे जाएंगे तो उड़न गिलहरी को भी संरक्षण मिलेगा। यही नहीं, लाइकेन, बांस, जंगली मशरूम, बेंत, बुरांश, आर्किड के अलावा जलीय पौधों की प्रजातियों पर भी शोध कर इनके संरक्षण-संवर्द्धन को कदम उठाए जाएंगे। गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में सेलेक्स प्रजाति के वृक्षों की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। सेलेक्स की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट के बल्ले बनाने में होता है। वन विभाग की अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक में रखे गए अनुसंधान से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।

अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) की वन मुख्यालय में हुई बैठक में इस वर्ष के अनुसंधान कार्यों के मद्देनजर अनुसंधान शाखा ने कई प्रस्ताव रखे थे। गहन मंथन के बाद इनमें से अधिकांश को हरी झंडी दे दी गई। वन संरक्षक अनुसंधान वृत्त संजीव चतुर्वेदी के अनुसार आरएसी की अनुमति मिलने के साथ ही अब वन विभाग की अनुसंधान शाखा राज्य में पहली बार जैव विविधता से जुड़े अनछुए पहलुओं पर अनुसंधान करेगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।

गोपेश्वर के मंडल में संरक्षण : आइएफएस चतुर्वेदी के अनुसार आरएसी ने राज्य में कीटभक्षी पौधों के संरक्षण-संवर्द्धन के लिए अनुसंधान को मंजूरी दी है। कीटभक्षी पौधों की कुछ प्रजातियां राज्य में रालाम घाटी, थलकेदार, मंडल और नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। इन सभी का गोपेश्वर के मंडल में प्राकृतिक वास में संरक्षण किया जाएगा।

पता चलेगा कहां-कहां है उड़ने वाली गिलहरी : प्रदेश में देवलसारी समेत एकाध अन्य स्थलों में उड़ने वाली गिलहरी देखी गई हैं। अब आरएसी की हरी झंडी के बाद अनुसंधान शाखा ये पता लगाएगी कि यह राज्य में कहां-कहां और किन क्षेत्रों में है। यह भी देखा जाएगा कि कहीं इनके वासस्थल खतरे में तो नहीं हैं। रिपोर्ट तैयार इनके संरक्षण को कदम उठाए जाएंगे।

हिमाचल के सहयोग से तलाशेंगे सेलेक्स की संभावनाएं : पड़ोसी राज्य हिमाचल में सेलेक्स के पेड़ों की कई प्रजातियों को बढ़ावा देने में सफलता मिली है। अब हिमाचल की डॉ. वाइएस परमार बागवानी एवं वानिकी विवि सोलन के सहयोग से उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में सेलेक्स की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। अनुसंधान शाखा इसके लिए गहन अध्ययन कर कुछ स्थानों पर सेलेक्स के पौधे लगाएगी। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो कृषि वानिकी के क्षेत्र में यह एक अहम कदम साबित होगा।

बुरांश की छह प्रजातियों को संरक्षण : आरएसी ने कुमाऊं के मुनस्यारी क्षेत्र में राज्य में पाई जाने वाली बुरांश की सभी छह प्रजातियों के साथ ही अन्य राज्यों से भी इसकी प्रजातियां यहां लाकर संरक्षण प्रदर्शन स्थल को मंजूरी दी है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल में गोपेश्वर के नजदीक मंडल में आर्किड प्रजातियों को प्राकृतिक वासस्थल में संरक्षित करने और इसे ईको टूरिज्म के तौर पर विकसित करने को भी अनुमति दी है। यही नहीं, राज्य में पाई जाने वाली जलीय पौधों की प्रजातियों पर भी शोध की मंजूरी दी गई है।

उड़न गिलहरी के वासस्थलों का निरीक्षण कर पता लगाया जाएगा कहीं यह प्रजाति खतरे में तो नहीं। फाइल

इनमें भी अनुसंधान को मंजूरी

लाइकेन :- मास यानी लाइकेन की मुख्य प्रजातियों में झूला घास समेत अन्य प्रजातियों का संरक्षण मुनस्यारी में होगा।

बांस :- उत्तराखंड में मिलने वाली बांस की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण व विपणन के लिए नैनीताल क्षेत्र में प्रदर्शन स्थल विकसित होगा।

बेंत :- बेंत प्रजाति की संभावनाओं को देखते हुए इसके लिए तैयार होगा प्रदर्शन स्थल।

जंगली मशरूम :- राज्य के जंगलों में कई प्रकार की मशरूम भी निकलती है। खासकर गुच्छी मशरूम का बड़े पैमाने पर अनियंत्रित दोहन हो रहा है। मशरूम की प्रजातियों का देववन में प्राकृतिक वासस्थल में संरक्षण किया जाएगा।

प्राकृतिक वन :- आरएसी ने राज्य में जापान की मियावाकी तकनीक से प्राकृतिक रूप से वनों को पनपाने के प्रस्ताव को भी प्रयोग के तौर पर चलाने की मंजूरी दी है।

जय श्रीराम का नारा न लगाने पर इमाम से मारपीट, बदसुलूकी

जागरण संवाददाता, बागपत : इमाम ने 10-12 लोगों पर जय श्रीराम का नारा न लगाने पर उनसे मारपीट और बदसुलूकी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इमाम की तहरीर पर अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस घटना को केवल मारपीट बता रही है।

मुजफ्फरनगर निवासी इमलाकुर्रहमान मेरठ के सरधना की साबरी मस्जिद में इमाम हैं। बागपत में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार शनिवार शाम लगभग छह बजे वह सरधना से बाइक पर अपने गांव जा रहे थे। आरोप है कि मेरठ-करनाल हाईवे पर 10-12 युवकों ने उनकी बाइक रुकवा ली। युवकों ने उन पर जय श्रीराम बोलने का दबाव बनाया। उन्होंने मना किया तो उनकी दाढ़ी नोंचते हुए टोपी गिरा दी और गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। इमाम ने शोर मचाया तो वहां से बाइक पर जा रहे उनके ही गांव के लोगों से बचाया। आरोपित उन्हें धमकी देकर चले गए। एसओ रमेश सिंह सिद्धू का कहना है कि जांच में केवल मारपीट की घटना सामने आई है।

50 लाख करोड़ रुपये का निवेश रेलवे के विकास के लिए किया जाएगा। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन का सपना भी पूरा होगा। रांची में 64वें रेलवे राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के दौरान यह बात रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने कही।

न्यूज गैलरी

ताज में विदेशी पर्यटक से महिला सुरक्षाकर्मी ने की अभद्रता

आगरा : ताजमहल देखने आई ऑस्ट्रेलिया की पर्यटक से सीआइएसएफ की महिला कांस्टेबल ने अभद्रता कर दी। टिकट चेकिंग के दौरान काफी देर तक हंगामा हुआ। मामला पर्यटन थाने पहुंचा। पर्यटक का मेडिकल कराया गया। बाद में पर्यटक ने कानूनी कार्रवाई से इन्कार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की पर्यटक सानिया मोहिद्दीन रविवार दोपहर 12 बजे चार भारतीय पर्यटकों के साथ ताजमहल देखने आई थीं। प्रवेश के दौरान पहचान पत्र मांगने पर सीआइएसएफ की एक महिला कांस्टेबल से पर्यटकों की तकरार हो गई। काफी देर तक हंगामा चला। महिला पर्यटक ने इसकी शिकायत पर्यटन थाने में की। सीआइएसएफ की महिला कांस्टेबल पर मारपीट का भी आरोप लगाया। (जासं)

दहेज में बाइक नहीं मिली तो दे दिया तीन तलाक

बाराबंकी : दहेज में मोटर साइकिल (बाइक) न मिलने पर निकाह के 12 घंटे बाद ही शौहर ने तलाक दे दिया। पीड़िता के पिता ने फतेहपुर कोतवाली में तहरीर दी है। बाराबंकी के कुतुबुद्दीन ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रुखसाना का निकाह शाहआलम के साथ शनिवार (13 जुलाई) को किया था। रविवार को चौथी ले जाने की तैयारी हो रही थी, तभी फोन आया कि रुखसाना की तबीयत खराब है। ससुराल पहुंचे तो रुखसाना देखते ही रोने लगी और बताया कि बाइक की मांग को लेकर पति नाराज हैं और परेशान कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन ने बताया कि उन्होंने दामाद शाह आलम व उसके परिवारीजन को काफी समझाया, मगर किसी ने एक न सुनी। इसी बीच, गुस्से में आकर शाह आलम ने सबके सामने रुखसाना को एक साथ तीन बार तलाक कहकर घर से निकल जाने को कहा। (जासं)

'वाई' को 'टी' समझ धर्मेंद्र प्रधान की कार का चालान

नोएडा : यातायात विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही का ताजा मामला केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ा है। कर्मचारियों ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टोयटा कार का ई-चालान दिखाते हुए उसकी कॉपी घर भेज दी। यह चालान 25 जनवरी को किया गया, जबकि उस दिन उनकी कार शहर में नहीं थी। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री का चालक चालान की कॉपी लेकर नोएडा सेक्टर-14ए स्थित विभाग के कार्यालय पहुंचा। चालक ने एसपी ट्रैफिक अनिल कुमार झा से मिल कर गलत चालान की शिकायत की। जांच में पता चला कि वैगनआर कार का ई-चालान किया गया था और उसके नंबर प्लेट पर सीएवाई लिखा है, जबकि केंद्रीय मंत्री की टोयटा कार है और उनकी कार का नंबर सीएटी से शुरू है। कर्मचारी ने वाइ अक्षर को टी समझ लिया और बाकी नंबर में समानता होने की वजह से केंद्रीय मंत्री के यहां चालान की कॉपी भेज दी। विभाग ने अपनी गलती मानते हुए चालान को रद कर दिया। (जासं)

रोष ▸ मधुबनी में सांसद को पीड़ितों ने बनाया बंधक, मौके पर देर से पहुंचने पर थे नाराज

बिहार में लगातार हो रही बारिश से टूटे कई तटबंध, 19 लोग डूबे

मुजफ्फरपुर जिले में दो हजार घरों में घुसा बाढ़ का पानी

जागरण टीम, पटना

बिहार में उफनाई नदियों का पानी उत्तर बिहार, कोसी और सीमांचल के जिलों के गांव और शहर में घुसकर कहर ढा रहा है। रविवार सुबह मधुबनी में सात और दरभंगा में चार जगहों पर तटबंध टूट गए। इससे दर्जनों गांवों में पानी घुस गया है। विभिन्न जगहों पर 19 लोग डूब गए।

एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश रविवार को थोड़ी थमी, लेकिन कोसी-सीमांचल के लोगों की मुसीबत शुरू हो गई है। सुपौल से कोसी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। शनिवार रात को कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोले जाने के कारण सुपौल-सहरसा के लगभग 12 दर्जन गांव जलमग्न हो गए थे। अब सुपौल-सहरसा में तो कोसी घट रही है, लेकिन बराज से निकला पानी कटिहार में कोसी के जलस्तर को बढ़ा रहा है। जिन गांवों में पानी घुस गया है, वहां के लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में बाहर निकल रहे हैं।

मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी का जलस्तर स्थिर रहने के बावजूद कटरा व औराई में बाढ़ की स्थिति नाजुक बनी है। दो हजार घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पूर्वी चंपारण के नए इलाकों में पानी तेजी से प्रवेश कर रहा है। मधुबनी में कमला बलान व धौस नदी का तटबंध टूटने से जिले में त्राहिमाम है। दो दर्जन गांवों में पानी फैल गया है। पांच घंटे बाद डीएम व स्थानीय सांसद अशोक यादव के पहुंचने पर आक्रोशित लोगों ने सांसद को घंटों बंधक बनाए रखा। मधुबनी में रविवार को तीन जगहों पर टूट गया। दरभंगा में चार जगहों पर कमला नदी का तटबंध टूट गया। लोगों के घरों में पानी भर गया है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बिहार में अररिया जिले के पिपरा गांव निवासी मुकेश कुमार का विवाह हाल ही में कटिहार में हुआ है। जब वह दुल्हन को लेकर गांव जाने के लिए फारबिसगंज पहुंचा तो यहां बाढ़ के हालात ने मुश्किल पैदा कर दी। ऐसे में गांववासियों ने ड्रम की नाव बनाकर दूल्हा-दुल्हन को उसके घर पिपरा पहुंचाया। जागरण

सुपौल में डरा रही कोसी

सुपौल में कोसी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आधी रात को घरों में पानी घुसने से तटबंध के अंदर के गांवों में अफरा-तफरी मच गई। किसी का घर बह गया तो किसी के मवेशी बह गए। कोसी के आक्रामक रुख के कारण तटबंध के दर्जनों बिंदुओं पर दबाव बना हुआ है। अररिया शहर के लगभग 10 हजार लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं।

सीतामढ़ी पर बाढ़ का खतरा

सीतामढ़ी जिले में बाढ़ का कहर जारी है। रविवार को पुपरी प्रखंड की हरिहरपुर पंचायत अंतर्गत तेम्हुआ गांव में दो स्थानों पर मरहा नदी का बीररवा तटबंध टूट जाने से स्थिति गंभीर हो गई। सीतामढ़ी-पुपरीपथ में बाजपट्टी में पानी का तेज बहाव जारी है। बाजपट्टी में सोनमनी पुल बह गया। मंडल टोला का दोमंजिला स्कूल भवन भी ध्वस्त हो गया।

नवरात्र से हनुमानधारा पर रोप-वे कराएगा दर्शन

शिवा अवस्थी, चित्रकूट

रोप-वे से प्रकृति के अद्भुत नजारे देखेंगे श्रद्धालु। जागरण

▸ चित्रकूट में लक्ष्मण पहाड़ी के बाद उत्तर प्रदेश का बनेगा दूसरा रोप-वे

▸ जमीन से 317 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी से देख सकेंगे मनमोहक दृश्य

प्रभु श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट में अभी तक करीब एक हजार सीढ़ियां चढ़कर हनुमानधारा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहां शारदीय नवरात्र से रोप-वे से दर्शन होंगे। साथ में 317 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी से प्रकृति के अद्भुत नजारे भी दिखेंगे। प्राकृतिक हरियाली के दीदार संग हनुमान जी से जुड़े प्रसंग भी जान सकेंगे। लक्ष्मण पहाड़ी के बाद यह उत्तर प्रदेश का दूसरा रोप-वे होगा।

चित्रकूट में प्रतिदिन हजारों और प्रत्येक माह की अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। दीपावली, श्रावणी व आषाढ़ अमावस्या पर यह संख्या 15 से 35 लाख तक पहुंच जाती है। हनुमान धारा की ऊंची चढ़ाई के कारण 40 से 50 फीसद श्रद्धालु ऊपर चढ़ने में कतराते हैं। रोप-वे बनने के बाद श्रद्धालु आराम से हनुमानधारा के साथ ऊपरी तल पर स्थित सीता रसोई तक पहुंच सकेंगे। रोप-वे का निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था दामोदर रोप-वे एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी इसका संचालन 30 साल तक लीज पर करेगी।

दामोदर रोप-वे एंड इंफ्रा लिमिटेड के जनरल मैनेजर एसके तिवारी बताते हैं कि 317 मीटर लंबे रोप-वे में 13 पिलर का निर्माण होना है। इसमें करीब 10 पिलर का निर्माण पूरा हो चुका है। अब ऊपर के दो मुख्य पिलर का काम तेजी से शुरू है। इसमें मंदिर के किनारों के पत्थर में ड्रिल नहीं होने की दिक्कत होने से केमिकल के सहारे पिलर बनाए जाएंगे फिर प्लेटफार्म बनाकर संचालन होगा। इसके नवरात्र से शुरू होने पूरी उम्मीद है। चित्रकूट में हनुमान धारा का विशेष महात्म्य है। हनुमान जी को यहां पर वह सुख और शांति मिली थी, जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिली। किवदंती है कि लंका दहन में हनुमान जी का शरीर काफी तपा था। लंका विजय के बाद उन्होंने प्रभु श्रीराम से शरीर की शीतलता का उपाय पूछा। इस पर प्रभु ने उनको विंध्य पर्वत श्रेणी पर ऋषियों-मुनियों की पवित्र भूमि की प्राकृतिक छटा में तप की सलाह दी। हनुमानजी ने इसी पहाड़ी में श्रीराम रक्षा स्त्रोत का पाठ किया था। अनुष्ठान पूर्ण होने पर जलधारा प्रकट हुई। उसी से शीतलता मिली। वह धारा वर्तमान में भी अविरल बह रही है।

100 अरब की जमीन बेचने में बिशप समेत 16 पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

▸ फर्जी सोसाइटी-ट्रस्ट बनाकर प्रयागराज में अरबों की भू-संपदा हड़पी

▸ देश में जमीन हड़पने का सबसे बड़ा घोटाला : जॉन अगेस्ट्रीन

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इंडियन चर्च ट्रस्टीज, डायसिस ऑफ लखनऊ के अधीन आने वाली 100 अरब रुपये की जमीन बेचकर रुपये की बंदरबांट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज के जरिए सिविल लाइंस की सौ अरब रुपये की जमीन दूसरे संस्थानों में फर्जी तरीके से ट्रांसफर कर बेची गई। मामले में बिशप डायोसिस आफ लखनऊ, मेट्रोपोलियन चर्च ऑफ इंडिया जॉन अगेस्ट्रीन ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। अरबों की संपत्ति हेरफेर के मामले में बिशप समेत 16 बड़े पदाधिकारियों को नामजद किया गया है।

इन संस्थाओं की संपत्तियों को लेकर पहले भी मुकदमे दर्ज होते रहे हैं। इस बार राजाजीपुरम, लखनऊ के रहने वाले बिशप जॉन अगेस्ट्रीन ने सिविल लाइंस थाने में जो मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें कई अज्ञात भी हैं। नामजद किए गए 16 बड़े पदाधिकारियों में पीसी सिंह, पीपी मरांडी, पीके समन्तोराय, एल्वान मसीह, जयंत अग्रवाल, पाल दुपहरे पीपी हाविल, बिशप पीटर बलदेव, सुरेश जैकब, राजीव चंद्र, एआर स्टीफन, एचआर मल, मार्विन मैसी, प्रेम मैसी, अशोक विश्वास, प्रबल दत्ता, शशि प्रकाश हैं। सभी पर आरोप है कि फर्जी सोसाइटी, एसोसिएशन बनाकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए डायसिस आफ लखनऊ की प्रयागराज स्थित 25 महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस की अरबों की संपत्ति का बंदरबांट किया। आला अफसरों के निर्देश पर सिविल लाइंस पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है।

मुख्यमंत्री और डीजीपी से मिले बिशप जॉन अगेस्ट्रीन

मुकदमा दर्ज कराने वाले बिशप जॉन अगेस्ट्रीन ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डीजीपी ओपी सिंह से मुलाकात कर दस्तावेज सौंपे। जांच के बाद सिविल लाइंस थाने में गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। जॉन अगेस्ट्रीन का कहना है कि सौ अरब की जमीन तो महज प्रयागराज में बेची गई। देशभर में अरबों की संपत्ति हड़पी गई है। उनका आरोप है कि फर्जी सोसाइटी, ट्रस्ट बनाकर यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है।

तमिलनाडु के अंसारुल्ला मामले में एनआइए ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

चेन्नई, एएनआइ : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने तमिलनाडु के अंसारुल्ला नाम के आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को चेन्नई स्थित जांच एजेंसी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। एनआइए के मुताबिक आरोपित हसन अली और हरीश मुहम्मद देश में बड़े आतंकी हमले की तैयारी में थे और इसके लिए वे धन एकत्र कर रहे थे।

एनआइए ने नौ जुलाई को तीन संदिग्धों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। ये संदिग्ध आतंकी चेन्नई और नागपट्टिनम जिले के रहने वाले थे। इनसे हुई पूछताछ के आधार पर शनिवार को दोनों शहरों के चार स्थानों पर छापेमारी की गई थी और इस्लामिक देश स्थापित करने के इरादे से देशभर में आतंकी हमले की तैयारी कर रहे एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था।

जांच में पता चला था कि ये भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश रच रहे थे। इन दहशतगर्दों ने अंसारुल्ला नाम का आतंकी संगठन बना रखा था। छापेमारी की कार्रवाई में नौ मोबाइल, 15 सिम कार्ड, सात मेमोरी कार्ड, 3 लैपटॉप, पांच हार्ड डिस्क, छह पेन ड्राइव, दो टैबलेट और तीन सीडी और डीवीडी बरामद हुई थीं। इसके अलावा तमाम मैगजीन, बैनर्स, नोटिस, पोस्टर्स और किताबें भी बरामद की गई थीं।

पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा से रोशन होगी सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत

माला दीक्षित, नई दिल्ली

▸ मलबे का किया गया है इस्तेमाल, बुधवार को राष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन

12 एकड़ में फैली सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत न सिर्फ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी इमारत है, बल्कि इसमें सबसे ज्यादा मलबे (डिमोलीशन वेस्ट) का भी इस्तेमाल हुआ है। पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा से लैस विश्वस्तरीय खूबियों वाला सुप्रीम कोर्ट का यह नया परिसर वहीं है, जहां कभी अप्पू घर होता था। 883 करोड़ रुपये की लागत से इसे सात वर्षों में तैयार किया गया है। यहां कोर्ट का प्रशासनिक कामकाज, रिकार्ड और रजिस्ट्री आदि होगी, लेकिन अदालतें पुराने भवन में ही रहेंगी। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 जुलाई को करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत 28 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रारंभ में इसका कामकाज संसद भवन के कुछ हिस्से में होता था। 1958 में भगवान दास रोड पर सुप्रीम कोर्ट के भवन का निर्माण हुआ। नई इमारत इसका विस्तार है। इसका निर्माण 2012 में शुरू हुआ और वर्ष 2019 में पूरा हुआ। इसमें तीन स्तरीय कार पार्किंग है, जहां 1800 कारें खड़ी हो सकती हैं। भवन निर्माण का काम देख रहे एक अधिकारी बताते हैं कि इसके निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती जमीन के पानी के दबाव को रोकने की थी। यमुना के पास होने के कारण यहां दो-ढाई मीटर नीचे ही पानी मिल जाता है, जबकि तीन मंजिला पार्किंग 16 मीटर नीचे बनाई गई है। पानी का दबाव रोकने के लिए स्पेशल स्वायल एंकर लगाए हैं, ताकि भवन मजबूत रहे।

इमारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है, लेकिन बहुत कम गहराई पर भूजल उपलब्ध होने के कारण यह कारगर नहीं होता, इसलिए यहां एक-एक लाख लीटर वाले तीन टैंक बनाए गए हैं, जिसमें एकत्रित बारिश के पानी का दोबारा इस्तेमाल होगा। भवन में तीन गेट हैं। इसे भी सुप्रीम कोर्ट की पुरानी इमारत से मेल खाते लाल पत्थर से फिनिश किया गया है। यहां आग लगने की स्थिति में भी साफ हवा आने का इंतजाम है, ताकि दुर्भाग्यवश स्थिति में लोगों का दम न घुटे। यहां 40 फीसद बिजली सौर ऊर्जा से मिलेगी व शून्य फीसद सीवर म्यूनिसिपल डिस्चार्ज होगा। इमारत के अंदर ही एसटीपी लगा हुआ है। शोधित पानी का एसी कूलेंट सिस्टम और फ्लश में उपयोग होगा।

पुराने भवन से तीन भूमिगत रास्तों के जरिये जुड़ी है नई इमारत

यहां एक ब्लॉक में वकीलों के लिए 500 चैंबर बनाए गए हैं। पुरानी से नई इमारत तक आने-जाने के लिए तीन भूमिगत रास्ते हैं, जिनमें से एक जजों के लिए, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के रिकार्ड के लिए और तीसरा वकीलों के लिए है।

पहला ऑडिटोरियम

नई इमारत में 620 सीटों वाला सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑडिटोरियम व 230 सीटों वाला बहुद्देश्यीय सभागार भी है। इसमें बड़े-बड़े कांफ्रेंस हाल हैं। नई इमारत में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस, मेडिएशन सेंटर के अलावा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस भी होगा। इसमें कैंटीन भी है।

भूजल बचाने के लिए चाहिए राष्ट्रीय कानून

रूमा सिन्हा, लखनऊ

117 लाख सिंचाई नलकूप हैं देश में

01 नंबर पर हैं हम भूजल दोहन में

43.5 लाख सिंचाई नलकूप हैं यूपी में

भूमिगत जल के दोहन पर अंकुश लगाने को सख्त नीति की दरकार

भूजल के दोहन से हालात विकट हो गए हैं। प्रतीकात्मक

देश में जारी अंधाधुंध भूजल दोहन से दिन-ब-दिन हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार इस पर अंकुश लगाने की बातें तो कर रही है, लेकिन जमीन पर कुछ हो नहीं रहा। जल संसाधन मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार गहराई में स्थित एक्यूफर स्टेटा से भूजल दोहन की अनुमति नहीं है, लेकिन बोरिंग के जरिए धड़ल्ले से इस जलनिधि को खाली किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित देश के तमाम राज्यों में अब इन गहरे सुरक्षित स्रोतों से भूजल दोहन किया जा रहा है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक बीबी त्रिवेदी के मुताबिक देश में बेलगाम दोहन पर प्रभावी अंकुश न लग पाने के लिए समग्र राष्ट्रीय कानून का न होना बड़ा कारण है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में भूजल एक्ट बनाया तो गया है, लेकिन यह दोहन रोक पाने में विफल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2014 में जल नियामक आयोग गठित किया गया पर 10 माह पहले अध्यक्ष की तैनाती के बाद भी क्रियाशील नहीं हो सका। भूजल दोहन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय कानून की सख्त दरकार है।

कैसे पहुंचाएंगे घर-घर नल से पानी : त्रिवेदी बताते हैं कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में उपलब्ध 411 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) भूगर्भ जल का 60 फीसद से अधिक 253 बीसीएम पानी कृषि, पेयजल, औद्योगिक कार्यों के लिए निकाला जा रहा है। शहरों में बड़ी तादाद में निकाला जा रहा भूगर्भ जल इसमें शामिल नहीं है। ऐसे में खत्म होते भूजल भंडार से सरकार का घर-घर नल से पानी पहुंचाने का दावा पूरा होना कठिन दिखता है।

एनजीटी सख्त, सुनवाई 19 को : 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत सरकार ने 1997 में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया, लेकिन स्पष्ट कानून के अभाव में गत 22 वर्षों में प्राधिकरण भूजल दोहन रोकने में नाकाम रहा। नाराज एनजीटी ने गत जनवरी में देशभर में बेलगाम भूजल दोहन पर अंकुश लगाने के मकसद से 50 वर्षों की आवश्यकताओं को देखते हुए मसौदा तैयार कर 30 जून तक ट्रिब्यूनल को सौंपने को कहा। अब 19 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है।

मुठभेड़ में पांच-पांच लाख के दो इनामी नक्सली ढेर

नई दुनिया, दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में रविवार को डिस्ट्रिक रिजर्व गार्ड (डीआरजी) ने मुठभेड़ में दो हार्डकोर नक्सली मार गिराए, जिनमें एक महिला है। दोनों पर पांच-पांच लाख का इनाम था।

पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर शनिवार रात जवानों को किरंदुल थाना क्षेत्र के गुमियापाल जंगल में भेजा गया। रविवार सुबह जवानों को देख नक्सलियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दो नक्सली मारे गए। तलाशी में मौके से दोनों शव तथा एक राइफल, एक कट्टा, एक टिफिन बम और अन्य समान बरामद किया गया। मृतकों की शिनाख्त मंगली हेमला और शंकर हेमला के रूप में हुई है। मंगली दरभा डिवीजन मेडिकल टीम प्रभारी तथा मलांगिर एरिया कमेटी की सदस्य थी, जबकिशंकर सीएनएम कमांडर है। मंगली का पिता देवा उर्फ विनोद और पति जगदीश सीसी मेंबर हैं। उन पर क्रमशः आठ व 10 लाख रुपये का इनाम घोषित है।

कार से स्टंट कर रहा था कैप्टन अभिमन्यु का भतीजा, केस दर्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ निशान जीटीआर से लगाए विजय चौक के तीन चक्कर

▸ सीसीटीवी कैमरे के जरिये हुई पहचान, पुलिस ने बरामद की कार

राष्ट्रपति भवन और संसद भवन से चंद कदम की दूरी पर स्थित विजय चौक पर शनिवार तड़के चार बजे कार चालक के स्टंट किए जाने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में स्टंट की वीडियो की जांच में कार चालक की पहचान कैप्टन अभिमन्यु के भतीजे के रूप में हुई। कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री हैं। दिल्ली पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर कार को भी बरामद कर लिया है।

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जन संपर्क अधिकारी एसीपी अनिल मित्तल ने बताया कि विजय चौक पर स्टंट करने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने छानबीन की। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि विजय चौक पर आने के बाद कार चालक ने तेज रफ्तार में चौक के तीन चक्कर लगाए और फिर वहां से फरार हो गया। जांच में पता चला कि सफेद रंग की कार निशान जीटीआर है। इसका नंबर डीईसी 0003 है और उस पर देव जिला लिखा हुआ था। कार कैप्टन अभिमन्यु के भाई रूद्र सेन सिंधु के बेटे सर्वेश सिंधु की है। इसे कापसहेड़ा के सिंधु फार्महाउस से बरामद कर लिया गया। यह गाड़ी पंजाबी बाग में एसएच ट्रांसपोर्ट से रजिस्टर्ड है। स्टंट के दौरान सर्वेश ही कार चला रहा था। उसके खिलाफ लापरवाही से कार चलाने के मामले में कार्रवाई की गई है।

जानकारी के अनुसार, सर्वेश को स्पोर्ट्स कार का शौक है। पहले वह गाड़ी ठीक चला रहा था, लेकिन विजय चौक पर खाली एरिया देखकर उसका स्टंट करने का मन बना। निशान जीटीआर की कीमत करीब दो से ढाई करोड़ है। ऐसी गाड़ियां भारत में बेहद कम हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

लक्ष्मण झूला पुल को हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी

जासं, ऋषिकेश : उत्तराखंड सरकार के आदेश के बाद लोनिवि ने लक्ष्मण झूला पुल को हमेशा के लिए बंद करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रविवार को पुल पर दुपहिया वाहन तो नहीं चले, लेकिन पूरे दिन पैदल आवाजाही जारी रही। मियाद पूरी कर चुके 90 वर्ष पुराने लक्ष्मणझूला पुल को आमजन के लिए खतरा मानते हुए शासन ने इसे बंद करने के आदेश दो दिन पहले जारी किए थे। लोगों के विरोध को देखते हुए लोक निर्माण विभाग नरेंद्र नगर खंड को पुल के दोनों ओर बल्लियां लगाकर सिर्फ पैदल चलने की छूट देनी पड़ी। रविवार को पुल पर दुपहिया वाहन नहीं चले, लेकिन पैदल आवाजाही जारी रही। यमकेश्वर क्षेत्र की विधायक रितु खंडूड़ी ने भी अधिकारियों के साथ पुल की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके ही लोनिवि के अधिकारी भी पुल को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला ले चुके हैं। रविवार को आइजी जोन अजय रौतेला ने भी मुनि की रेती में आयोजित बैठक में लोनिवि के अधिशासी अभियंता मोहम्मद आरिफ खान से पुल के संबंध में जानकारी मांगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुल को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। शाम को एडीएम टिहरी शिवशंकर द्विवेदी, एएसपी टिहरी स्वप्निल कुमार सिंह, एसडीएम नरेंद्रनगर युक्ता मिश्रा व पुलिस उपाधीक्षक पीएस शाह के साथ लोनिवि के अधिशासी अभियंता एसएल गोयल ने पुल का मौका-मुआयना किया। उधर, लक्ष्मणझूला पुल पर दुपहिया वाहनों की आवाजाही रुकने के कारण रामझूला पुल पर दुपहिया का लोड बढ़ गया है।

लक्ष्मणझूला पुल को हमेशा के लिए बंद करने के फैसले की भनक लगते ही लक्ष्मण झूला क्षेत्र के व्यापारी और स्थानीय लोग लामबंद होने लगे हैं। व्यापार मंडल स्वर्गाश्रम के अध्यक्ष डॉ. नारायण सिंह रावत ने कहा कि पुलिस-प्रशासन की मंशा अब कावड़ यात्रा की आड़ में रामझूला पुल पर भी दुपहिया वाहनों को रोकने की है। इसका कड़ा विरोध किया जाएगा, क्योंकि ऋषिकेश से आवाजाही का रामझूला के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।

नारी सशक्तीकरण

पोलियो से सौ फीसद दिव्यांग परी संवार रही दूसरों का जीवन, बुजुर्ग मां-बाप और बड़ी बहन का बनी हुई हैं सहारा

'परी' के कद पर नहीं, उनके मकसद पर जाइए

सुभाष चंद्र, बठिंडा

▸ हौसले की उड़ान का साक्षात उदाहरण हैं सीता गिरी, खुद कर रही एमसीए, बारहवीं तक के बच्चों को देती है कोचिंग

बठिंडा में बच्चों को पढ़ाती हैं दिव्यांग सीता गिरी। जागरण

दीप सिंह नगर स्थित घर के एक कमरे में 'छोटी सी बच्ची' किसी स्कूल की कक्षा की तरह बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। सुंदर नैन नक्श.. आंखों में अद्भुत चमक। कुर्सी पर पालथी मारकर बैठे होने के कारण उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे। दरअसल, 22 वर्षीय यह युवती देखने में बच्ची जैसी है। दो वर्ष की उम्र में पोलियो का अटैक हो जाने के कारण पैरों का विकास नहीं हो पाया। शारीरिक विकास भी रुक गया, लेकिन मानसिक मजबूती और प्रबल इच्छाशक्ति के कारण वह सब पर भारी पड़ी। सौ फीसद दिव्यांग होने के बावजूद वृद्ध माता-पिता का सहारा बनी हुई है। उसके हौसले और मेहनत को देखकर हर कोई चकित रह जाता है।

अपने दम पर घर का खर्च चला रही परी : यूं तो उनका नाम सीता गिरी है, लेकिन दीप सिंह नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में सब परी के नाम से ही जानते हैं। पुलिस पब्लिक स्कूल में पढ़ते हुए आठवीं कक्षा में ही ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी और अपना खर्च खुद ही निकालने लगी। आज वह एमसीए (मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन) कर रही हैं। तीसरी से लेकर बारहवीं तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रही हैं, अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण भी देती हैं। अच्छा गा लेती हैं, पेंटिंग करती हैं। बड़ी बहन दीपा गिरी उनकी मदद करती हैं। उन्हें उठाकर वाशरूम, कक्षा आदि तक लेकर जाती हैं। पिता एसपीओ थे। अस्थायी। इसलिए काफी साल पहले जब सेवानिवृत्त हुए तो कोई सुविधा नहीं मिली। बाद में छत से गिरकर टांग टूट गई। अपना घर तक नहीं है। मकान के किराये से लेकर तमाम खर्च परी की कमाई से ही चल रहे हैं।

परी के इलाज को पिता ने बेच डाला सब कुछ : परी की चर्चा करते हुए पिता टुक लाल गिरी भावुक हो जाते हैं। बताते हैं कि बेटी के इलाज के लिए अपना घर बार, पत्नी के गहने... सब कुछ बेच डाला। फिर भी इलाज नहीं हुआ। एक डॉक्टर की सलाह पर स्कूल में दाखिला करा दिया। आज बेशक वह घर चला रही है, लेकिन उसके भविष्य को लेकर वह बेहद चिंतित हैं। खुद वृद्ध हैं। कोई बेटा नहीं है। बड़ी बेटी की शादी हो जाएगी तो इसका क्या होगा।

परी की प्रतिभा का हर कोई कायल

परी से पढ़ चुके रोहन और करनजोत कहते हैं कि परी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का अंदाज भी अच्छा होता है। इलाके की ही किरनजीत कौर और रेखा बताती हैं कि परी में गजब का हौसला है। वह खुद पढ़ने के साथ अन्य बच्चों को भी पढ़ाती हैं।

कोचिंग खोलना परी का है सपना, ताकि दूसर लोगों की कर सकें मदद

चिंतित पिता को परी हौसला देती हैं। वह कहती हैं कि बेशक कदम-कदम पर चुनौती है, लेकिन उसमें हर चुनौती का मुकाबला करने की शक्ति है। दिव्यांग व्यक्तियों में भी तमाम गुण होते हैं। स्कूल में दाखिल कराते समय लोग कहते थे कि यह क्या कर लेगी। यह तो खुद ही भगवान की मारी हुई है। कई ने तो पिछले जन्म का पाप तक करार दिया था, लेकिन अपने हौसले के दम पर वह हर चुनौती को पार कर रही हैं। उनका सपना है कि शहर में ऐसा कोचिंग सेंटर स्थापित करें, जिसमें जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में भी मदद कर सके। परी कहती हैं कि दिव्यांग कभी भी अपने आपको कमजोर समझकर हीन भावना का शिकार न हों, बल्कि हौसले से परिश्रम करें।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/positive-news

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 15 जुलाई 2019

दैनिक जागरण
दौड़ने से पहले हमें चलना सीखना चाहिए

कश्मीर में नई मुहिम

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुआई में मोदी सरकार ने कश्मीरियों का दिल जीतने की जो मुहिम शुरू की है उसमें सफलता मिले, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही केंद्रीय सत्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कश्मीर में अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त तत्वों पर लगाम लगे, क्योंकि इन तत्वों की सक्रियता पर रोक लगाए बगैर केंद्रीय योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने और ऐसा करके कश्मीरियों का दिल जीतने के लक्ष्य को हासिल करना कठिन हो सकता है। इससे इन्कार नहीं कि पिछले कुछ समय में अलगाववादी तत्वों पर एक हद तक लगाम लगी है, लेकिन फिलहाल इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि उनका दुस्साहस पस्त पड़ चुका है। हुर्रियत कांफ्रेंस सरीखे शरारती संगठनों की आतंक परस्ती और पाकिस्तान भक्ति पहले जैसी नजर आ रही है। इसके अलावा इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कश्मीर घाटी में मजहबी कट्टरता और आतंकवाद को नए सिरे से हवा देने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों अल-कायदा की ओर से दी गई गीदड़ भभकी यही बताती है कि कश्मीर घाटी को जिहादी आतंकवाद का गढ़ बनाने की कोशिश हो रही है। ध्यान रहे कि ऐसी कोशिश पहले भी होती रही है और इसका प्रमाण यह है कि वहां रह-रहकर खूंखार आतंकी संगठन आइएस के काले झंडे लहराए गए हैं। इस सबके अलावा यह तो जग जाहिर ही है कि पाकिस्तान कश्मीर को अशांत एवं अस्थिर रखने की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।

अमन पसंद आम कश्मीरियों का दिल जीतने के लक्ष्य को हासिल करने में मुख्यधारा के राजनीतिक दल भी बाधक बन सकते हैं। इसकी पुष्टि तब हुई थी जब नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया था। यह फैसला इस बहाने किया गया था कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 35-ए एवं अनुच्छेद 370 को हटाने के इरादे जाहिर कर रही है। इन राजनीतिक दलों को इस पर भी आपत्ति थी कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 35-ए की संवैधानिकता पर सुनवाई क्यों कर रहा है? अब तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर भी सुनवाई करने को तैयार है। देखना है कि अब नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी क्या रवैया प्रदर्शित करती हैं? उनका रवैया जो भी हो, इस बात को ओझल नहीं किया जा सकता कि फिलहाल ये दोनों दल यह मांग करने में लगे हुए हैं कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव जल्द हों। निःसंदेह राज्य में विधानसभा चुनाव कराने ही होंगे, लेकिन बेहतर यह होगा कि पहली प्राथमिकता वहां के हालात सुधारने को दी जाए। हालात सुधार कर ही उस माहौल का निर्माण किया जा सकता है जिसमें केंद्रीय योजनाओं पर आसानी से अमल किया जा सके। यह सही है कि राज्यपाल शासन विभिन्न क्षेत्रों में नए-तौर तरीकों का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। उम्मीद की जाती है कि राज्यपाल के नए सलाहकार फारूक खान के आने से स्थितियां बदलेंगी। वे बदलनी भी चाहिए। वास्तव में जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन में वृद्धि को केंद्र सरकार को एक अवसर में तब्दील करना चाहिए, क्योंकि इसके आसार कम हैं कि वहां के राजनीतिक दल हालात बदलने में मददगार साबित होंगे।

सराहनीय पहल

उत्तराखंड सरकार की देश के सभी हिमालयी राज्यों को एक मंच पर लाने की पहल सराहनीय है। यह जरूरत भी है। लंबे अरसे से हिमालयी राज्यों का साझा मंच बनाने की पैरवी की जा रही है। दरअसल पूरे हिमालयी क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र बेहद संवेदनशील है। इस तंत्र पर देश के बड़े भू-भाग की पर्यावरणीय सुरक्षा का दारोमदार है। इन राज्यों में उत्तराखंड की स्थिति ज्यादा संवेदनशील है। यह हिमालयी क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा वाटर टैंक माना जाता है। गंगा और यमुना जैसी बड़ी राष्ट्रीय नदियों का उद्गम स्रोत भी उत्तराखंड है। अपने कुल भू-भाग के करीब 71 फीसद वन क्षेत्र और बड़े पारिस्थितिकी तंत्र की बदौलत यह राज्य पूरे देश को करीब तीन लाख करोड़ से अधिक की पर्यावरणीय सेवाएं मुहैया करा रहा है। इसमें करीब एक लाख करोड़ की हिस्सेदारी वनों की आंकी गई है। देश को बड़ा योगदान देने के बावजूद पर्यावरणीय बंदिशों ने उत्तराखंड की अपनी प्रगति के साथ ही आम लोगों की खुशहाली को भी सीमित कर दिया है। पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से अवस्थापना विकास कार्यों और निर्माण कार्यों की लागत मैदानी राज्यों की तुलना में ज्यादा पड़ रही है। इस वजह से शत-प्रतिशत केंद्रपोषित योजनाओं में भी राज्य को अपने पल्ले से धन खर्च करने को मजबूर होना पड़ रहा है। कमोबेश सभी हिमालयी राज्यों के हालात इसी तरह हैं। बुनियादी सुविधाओं का ढांचा खड़ा करने में राज्यों के पसीने छूट रहे हैं। आर्थिक संसाधनों के पिछड़ेपन और सीमित होने के कारण ही हिमालयी राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से विशेष दर्जा दिया गया है। हालांकि इस विशेष दर्जे को छीनने की कोशिशें भी होती रही हैं। इन राज्यों के सामने अन्य बड़ी चुनौतियां हिमालयी संस्कृति, पर्यावरण, आर्थिकी, सामाजिकी समेत सरोकारों को बचाए रखने की भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमालय के लिए अलग मंत्रालय के गठन पर अपनी सहमति जता चुके हैं। नीति आयोग में भी अलग हिमालयी प्रकोष्ठ अस्तित्व में आ चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हिमालयी राज्यों की संयुक्त आवाज राष्ट्रीय नीति नियोजन का हिस्सा बनेगी।

दुनिया को मुश्किल में डालते ट्रंप

पॉल क्रुगमैन

ट्रेड वार में कभी कोई स्पष्ट विजेता नहीं बनता, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था पर उनके निशान अक्सर लंबे समय तक देखे जाते हैं

अवधेश राजपूत

डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 'ट्रेड वार बढ़िया है और उसे जीतना आसान होता है।' उनका यह बयान निश्चित रूप से इतिहास की किताबों में दर्ज होगा, मगर यह भी तय है कि वह सही अर्थों में नहीं लिया जाएगा। इसके बजाय यह इराक युद्ध से पहले डिक चेनी की उस भविष्यवाणी की तर्ज पर याद किया जाएगा जिसमें चेनी ने कहा था कि, 'हम तो वास्तव में मुक्तिदाता माने जाएंगे।' ये बयान उस अहंकार और नादानी को दर्शाते हैं जो अक्सर महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर फैसला लेने में असर दिखाते हैं। हकीकत यही है कि ट्रंप इस ट्रेड वार को जीतने नहीं जा रहे। यह भी सच है कि उनकी प्रशुल्क दरों यानी टैरिफ ने चीन सहित अन्य अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उनसे अमेरिका को भी क्षति उठानी पड़ी है। न्यूयॉर्क फेड में अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि इसके चलते बढ़ी हुई कीमतों के कारण एक औसत परिवार को सालाना एक हजार डॉलर अधिक खर्च करने पड़ेंगे। यानी लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। फिर ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे कि टैरिफ से ट्रंप के अपेक्षित लक्ष्य हासिल हो पा रहे हैं जिनका मकसद दूसरे देशों पर नीतियों में बदलाव के लिए दबाव डालना है।

आखिर ट्रेड वार क्या है? इस जुमले को न तो अर्थशास्त्रियों और न ही इतिहासकारों ने गढ़ा है जिसमें घरेलू राजनीतिक कारणों के चलते कोई देश टैरिफ में बढ़ोतरी करता है जैसा अमेरिका 1930 के दशक से नियमित रूप से करता आया है। ट्रेड वार की स्थिति तभी बनती है जब कोई देश दूसरे देश पर दबाव के जरिये नियंत्रण के मकसद से टैरिफ दरें बढ़ाता है ताकि उसे अपने पक्ष में नीतियां बदलने के लिए मजबूर कर सके। हालांकि इसमें दर्द तो वास्तविक रूप से महसूस हो रहा है, लेकिन नियंत्रण स्थापित होता नहीं दिख रहा। कनाडा और मेक्सिको पर ट्रंप ने इस मकसद से टैरिफ बढ़ाया कि वे उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार अनुबंध यानी नाफ्टा पर नए सिरे से वार्ता के लिए तैयार हो सकें। इस कड़ी में हुआ नया समझौता एकदम पुराने जैसा है जिसमें मैग्निफाइंग ग्लास लगाकर भी कोई नई बात देखने को नहीं मिलेगी। इस नए समझौते को भी अभी तक कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली।

वहीं जी-20 देशों के हालिया सम्मेलन में ट्रंप ने चीन के साथ जारी ट्रेड वार पर विराम लगाने को लेकर सहमति जताई। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने नए टैरिफ को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हालांकि इस समझौते की भाषा बहुत अस्पष्ट है। इस बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि ट्रंप का ट्रेड वार आखिर क्यों नाकाम हो रहा है? एक भीमकाय अर्थव्यवस्था के बगल में मेक्सिको बहुत छोटी सी अर्थव्यवस्था है जिसके बारे में आपको लगेगा और ट्रंप ने तो लगभग मान ही लिया कि उसे धमकाना आसान है। चीन अपने आप में एक आर्थिक महाशक्ति है, लेकिन वह अमेरिका से जितना खरीदता है उसकी तुलना में कहीं अधिक बेचता है तो आपने यही सोचा कि वह अमेरिकी दबाव के आगे कमजोर पड़ जाएगा। तब आखिर ट्रंप अपने आर्थिक मंसूबों में कामयाब क्यों नहीं हो सकते? मेरी नजर में इसके तीन कारण हैं।

पहला तो यही विश्वास था कि अमेरिका आसानी से ट्रेड वार जीत सकता है। यह कुछ उसी किस्म का मुगालता था जिसने अमेरिका की ईरान नीति का सत्यानाश कर दिया। अमेरिका में शक्तिशाली पदों पर बैठे तमाम लोग यह हकीकत नहीं समझ पाए कि दुनिया में हम इकलौते ऐसे देश नहीं जिसकी अपनी खास संस्कृति, इतिहास और पहचान है और जिसे अपनी आजादी पर नाज है। अमेरिका रियायतें देने का बहुत अनिच्छुक हो गया जो उसकी नजर में दुनिया के दबंग देशों के लिए खैरात जैसी है। 'रक्षा पर अरबों का खर्च और परोपकार के लिए धेला नहीं' यह खास अमेरिकी भावना तो बिल्कुल नहीं है। खासतौर से यह विचार बहुत ही मूर्खतापूर्ण है कि चीन बाकी देशों के साथ मिलकर ऐसे समझौते पर सहमति बना लेगा जो अमेरिका के लिए बहुत अपमानजनक होगा।

दूसरी बात यही कि टैरिफ के मामले में ट्रंप के रणनीतिकार अतीत के दौर में जी रहे हैं जो आधुनिक अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं से अनभिज्ञ हैं। वे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैक्किनले के दौर की यादों में खोए हैं। मगर उस वक्त यह पता होता था कि 'आखिर यह वस्तु कहां बनी?' लेकिन इन दिनों लगभग प्रत्येक विनिर्मित वस्तु वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ी है जो कई देशों की सीमा से गुजरते हुए तैयार होती है।

इसमें बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। नाफ्टा में हलचल की संभावनाओं को लेकर अमेरिकी कंपनियां अजीब पसोपेश में हैं, क्योंकि अमेरिकी उत्पादन एक बड़ी हद तक मेक्सिको से होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति पर निर्भर है। फिर यह टैरिफ के प्रभाव के गणित को भी गड़बड़ा सकता है, क्योंकि यदि आप चीन में विनिर्मित वस्तुओं पर कर की दर बढ़ाएंगे, लेकिन अगर उनमें बड़े पैमाने पर कोरिया या जापानी कलपुर्जे लगे हों तब भी उनकी असेंबलिंग अमेरिका में स्थानांतरित न होकर वियतनाम जैसे किसी एशियाई देश में ही होगी।

ट्रंप का ट्रेड वार खासा अलोकप्रिय भी है। कई सर्वेक्षणों से यह साबित हुआ है जिसका असर ट्रंप की लोकप्रियता पर भी पड़ रहा है। इससे वह विदेशी पलटवार को लेकर राजनीतिक रूप से खासे संवेदनशील हो गए हैं। चीन भले ही अमेरिका से उतनी खरीदारी न करता हो जितनी वह बिक्री करता है, लेकिन चीन का कृषि बाजार उन किसान बाहुल अमेरिकी राज्यों के लिए बेहद अहम है जिनके वोटों पर पकड़ बनाए रखने की ट्रंप को कड़ी मशक्कत करने की दरकार है। इस तरह ट्रंप जिस ट्रेड वार को आसानी से जीतने की हसरत पाले हुए थे वह एक राजनीतिक युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। इस लड़ाई में टिके रहने के लिहाज से भी वह चीनी नेतृत्व की तुलना में कम सक्षम हैं जबकि चीन को भी इसकी तपिश झेलनी पड़ रही है। तब आखिर यह कैसे खत्म होगा? ट्रेड वार में कभी कोई स्पष्ट विजेता नहीं बनता, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था पर उनके निशान अक्सर लंबे समय तक देखे जाते हैं। ऐसी ही एक नाकाम कोशिश अमेरिका ने 1964 में की थी जब टैरिफ के जरिये यूरोप को फ्रोजन चिकन खरीदने के लिए मजबूर किया गया था।

वह ट्रेड वार की एक हल्की-फुल्की कड़ी थी और ट्रंप का ट्रेड वार अतीत के मुकाबले कहीं बड़ा है, लेकिन इसका नतीजा भी संभवतः वही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ विदेशी रियायतों को बंद कर ट्रंप इसे अपनी जीत के रूप में प्रचारित करेंगे, लेकिन इसका असल परिणाम हर किसी की जेब में सेंध लगाने के रूप में निकलेगा। वहीं पुराने व्यापार समझौतों को लेकर ट्रंप के खराब रवैये ने अमेरिका की साख को बुरी तरह प्रभावित करने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय कानूनों को भी कमजोर किया है। फिर जिन मैक्किनले का मैंने जिक्र किया था तो टैरिफ ने उन्हें उस समय खासा अलोकप्रिय बना दिया था। इस मसले पर अपने अंतिम भाषण में मैक्किनले ने स्वीकार किया था कि व्यापारिक युद्धों से कोई भला नहीं होता और उन्होंने कारोबारी मामलों में दोस्ताना रिश्तों के साथ सद्भावना की जरूरत जताई थी।

(नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखक द न्यूयार्क टाइम्स के स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

चांद को छूने की नई चाहत

सृजन पाल सिंह

चंद्रयान-2 न सिर्फ भारत के तकनीकी विकास की मिसाल बनेगा, बल्कि अन्य ग्रहों पर बसावट में भी एक कड़ी बन सकता है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) चंद्रयान-2 मिशन के जरिये चंद्रमा की एक नई यात्रा पर निकल चुका है। दुनिया में अंतरिक्ष को खोजने की यह होड़ अक्टूबर 1957 में शुरू हुई थी जब तत्कालीन सोवियत संघ ने स्पुतनिक-1 को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर एक नए युग का सूत्रपात किया था। स्पुतनिक-1 दो फुट चौड़ा गोला था जो धरती की तरफ रेडियो वेव संचालित करता था। स्पुतनिक-1 अंतरिक्ष में महज तीन सप्ताह तक ही बचा रहा और फिर उसकी बैटरी समाप्त हो गई, परंतु सोवियत संघ के उस छोटे से सैटेलाइट ने विश्व में अंतरिक्ष की होड़ शुरू कर दी जिसमें अमेरिका और रूस प्रमुख प्रतिद्वंद्वी थे। इस प्रतिस्पर्धा के दूसरे चरण में भी सोवियत संघ की जीत तब हुई जब अप्रैल 1961 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले मानव बने, परंतु इस स्पर्धा के प्रमुख चरण में अमेरिकियों ने तब विजय प्राप्त की जब 20 जुलाई, 1969 को नासा ने दो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर पहुंचा दिया। उस मिशन का नाम था अपोलो-11 और इसके बाद कुल 12 व्यक्तियों ने चंद्रमा पर कदम रखा। ये सभी अमेरिकी थे। 1972 में अपोलो-17 के साथ नासा ने चंद्रमा पर अपने मिशन को विराम दे दिया।

अब अपोलो-11 के पूरे पचास साल बाद भारत का इसरो चांद पर अपना सबसे महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-2 शुरू कर रहा है। चंद्रयान-2 धरती से चांद तक की 3,84,000 किलोमीटर यात्रा की शुरुआत 15 जुलाई को अलसुबह 2 दो बजकर 51 मिनट पर कर चुका है। चंद्रयान-2 के तीन प्रमुख हिस्से हैं। पहला लगभग 2400 किलोग्राम का ऑर्बिटर जो चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होकर उसका चक्कर लगाएगा। दूसरा हिस्सा है लैंडर जिसका नाम 'विक्रम' रखा गया है। यह नाम इसरो के संस्थापक और उसके पहले प्रमुख डॉ. विक्रम साराभाई के सम्मान में है। जब ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो जाएगा तब यह 1500 किलोग्राम का लैंडर विक्रम उससे अलग हो जाएगा। फिर वह चंद्रमा के आकाश को सटीकता से भेदते हुए उसके धरातल पर पहुंच जाएगा। ऐसा करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि चंद्रमा पर उतारते समय उसकी गति नियंत्रित रहे जिससे कि उसे कोई क्षति न पहुंचे। वह बहुत ही नाजुक घड़ी होगी और इसे हम सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। अब तक किए गए 38 ऐसे प्रयासों में महज 20 बार ही हम इस कार्य में सफल हुए हैं।

विक्रम के चंद्रमा के धरातल पर पहुंचते ही उसमें से एक 27 किलोग्राम और छह पहियों की अंतरिक्ष गाड़ी यानी रोवर निकलेगा। इस तीसरे हिस्से को इसरो ने नाम दिया है प्रज्ञान। प्रज्ञान लगभग एक चंद्र दिवस तक अपनी बैटरी पर जीवित रहकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के 500 मीटर तक के दायरे तक में खोजबीन करेगा। गौरतलब है कि एक चंद्र दिवस यानी चांद पर एक पूरा दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। इन दो हफ्तों में प्रज्ञान चांद के टुकड़ों का अध्ययन करेगा, चांद की तस्वीरें लेगा और उस पर जीवन के होने या जीवन के लिए जरूरी संसाधनों पर शोध करेगा। प्रज्ञान की बैटरी समाप्त होने के बाद भी चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हमारा ऑर्बिटर लगभग एक साल तक चांद की तस्वीरें हमें भेजता रहेगा।

चंद्रयान-2 वर्ष 2008 के चंद्रयान-1 मिशन से कही ज्यादा विकसित है। चंद्रयान-1 का मिशन सिर्फ ऑर्बिटर को चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाना था, जबकि चंद्रयान-2 का लक्ष्य ऑर्बिटर के साथ-साथ चंद्रमा की सतह तक पहुंचना और उसकी सतह पर रोवर चलाने का है। इस मिशन के बाद हम चंद्रमा पर उतरने वाले चौथे देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएंगे।

चंद्रमा पर उतरने के लिए उसके दक्षिणी ध्रुव का चयन एक विशेष महत्व रखता है। यहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। ऐसे में इस विशाल क्षेत्र का तापमान शून्य से लगभग 250 डिग्री नीचे तक चला जाता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में जमा हुआ जल यानी बर्फ पाई जा सकती है। यदि यह सच हुआ तो आने वाले समय में मानव जाति चंद्रमा पर मौजूद इस बर्फ से जल बना कर और फिर उस जल से ऑक्सीजन निकाल कर वहां पर स्थाई रूप से रहना शुरू कर सकती है। इसी जल से हम हाइड्रोजन भी बना सकते हैं जो चंद्रमा पर हमारा ईंधन बनेगा। चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर करोड़ों वर्ष से वहां जमी इसी बर्फ को खोजने का प्रयास करेगा। इसके अलावा चंद्रमा पर कई दुर्लभ खनिज भी हैं। इसमें टाइटेनियम, प्लेटिनम और सोना तो हैं ही, पर वैज्ञानिकों की विशेष रुचि एक नए पदार्थ पर है। यह है हीलियम-3, जो कि धरती पर न के बराबर है, लेकिन चंद्रमा पर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। हीलियम-3 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिससे हम फ्यूजन (विखंडन) के जरिये बड़ी मात्रा में परमाणु ऊर्जा बना सकते हैं।

मालूम हो कि चंद्रयान-2 छह सितंबर, 2019 को चंद्रमा पर दो विशाल गड्ढों के बीच मौजूद समतल पर उतरेगा। इस पूरी यात्रा का खर्च 123 मिलियन डॉलर यानी 843 करोड़ रुपये होगा, जो कि अब तक के सभी चंद्र अभियानों से काम है और हॉलीवुड की इस वर्ष की सबसे प्रचलित फिल्म 'द अवेंजर्स एंडगेम' को बनाने में आई लागत की आधी है। इस प्रकार से इसरो दुनिया में किफायती चंद्र मिशन की एक मिसाल कायम कर रहा है।

चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। उन्होंने चांद पर पहला कदम रखते हुए कहा था, 'एक मानव का यह छोटा-सा कदम मानवता के लिए एक विशाल छलांग है।' इसरो का चंद्रयान मिशन ऐसी ही एक और छलांग साबित होने वाला है। चंद्रयान-2 न सिर्फ भारत के तकनीकी विकास का एक उदाहरण बनेगा, बल्कि मानव जाति के दूसरे ग्रहों पर बसने के स्वप्न को पूरा करने में एक हिस्सा बनेगा। कुल मिलाकर अपोलो-11 से लेकर चंद्रयान-2 तक के चंद्रमा पर मानव के विभिन्न अभियान उस दिन की ओर बढ़ते हुए कदम हैं जब हम अपने घर के पते में चंद्रमा का शब्द जोड़ सकेंगे।

(लेखक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के पूर्व तकनीकी सलाहकार हैं और अंतरिक्ष विषय पर कई पुस्तक लिख चुके हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अधीर क्यों

मनचाहा फल न मिलने पर अधीर हो जाना मनुष्य का सामान्य स्वभाव है। जब वह कर्म करता है तो फल की इच्छा को साथ ही जोड़ लेता है। प्रत्येक कर्म एक निश्चित उद्देश्य के लिए होता है। कर्म की दिशा तय करने के लिए यह आवश्यक भी है। समस्या लक्ष्य को इच्छा में बदल देने से होती है, क्योंकि कर्म और इच्छा में कोई समानुपातिक संबंध नहीं होता। आसमान में मेघ उमड़ते हैं। वे गरजते भी हैं। उनका उमड़ना, गरजना उनके बरसने को सुनिश्चित नहीं करता। ऐसा भी होता है कि उमड़ने, गरजने के बाद भी वे बरसते नहीं। बरसने के लिए कुछ तय मानक होते हैं। जब वे मानक पूरे नहीं होते तो बिन बरसे बादलों का चले जाना उनके गुण को प्रकट करता है कि वे नियति से बंधे हुए हैं। मनुष्य में यह गुण दुर्लभ है इसलिए वह बादलों की तरह चुपचाप लौटता नहीं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। प्रतिक्रिया कम या अधिक हो सकती है, किंतु यह उसकी अज्ञानता का प्रतीक है।

जब मनुष्य में काम, लोभ, मोह, अहंकार आदि प्रबल होते हैं तो उनकी पूर्ति न होना क्रोध पैदा करता है। वह भूल जाता है कि जीवन में जो कुछ मिलना है वह निश्चित है और निश्चित समय पर ही मिलेगा। परमात्मा की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त करना असंभव है। मनुष्य निश्चय ही कर्म करता है, किंतु यह कर्म परमात्मा की कृपा के योग्य बनने के लिए होते हैं। एक परीक्षा में लाखों छात्र सम्मिलित होते हैं, किंतु उत्तीर्ण कुछ सौ छात्र ही होते हैं। जो सफल हुए वे परमात्मा की कृपा के योग्य सिद्ध हुए। जो असफल हुए उन्हें निराश होने के स्थान पर परमात्मा की कृपा योग्य बनने के लिए ऊर्जा केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जीवन भी प्रतिदिन परीक्षा है।

जब मनुष्य संयम अपना लेगा तो उसकी अधीरता स्वयं समाप्त हो जाएगी। परमात्मा पर आस्था टिकाना आ जाएगा। अपने कर्मों के साथ जब परमात्मा पर विश्वास को भी जोड़ दिया जाता है तो वे कर्म, प्रयास धर्म साधना बन जाते हैं। नदी का प्रवाह तभी बनता है जब वह अपने किनारों में बंधकर बहती है। किनारों का ध्यान न रखने पर प्रवाह टूटता है और जलराशि का अपव्यय होता है। अपने जीवन को गुणों और परमात्मा कृपा की सीमाओं में बांधने वाला ही कहीं पहुंच पाता है।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

जल को तिलांजलि देता समाज

फिर से

अचानक हमारे समाज को क्या हो गया कि हमने नदियों और झील-तालाबों को कूड़ेदान समझ लिया?

सूखा। इस शब्द से शुष्क और दरार से फटी जमीन और ऊपर चिलचिलाता मेघविहीन आसमान दिमाग में कौंधता है। बारिश गड़बड़ हो जाती है तो नदी-नाले, गांव के कुएं सब सूख जाते हैं। खेत धूल से भरे कटोरों में बदल जाते हैं। जानवर और परिंदे प्यासे भटकते हैं। ऐसे में याद आता है कि हमारी सदानीरा नदियों का क्या हुआ? नदीसूत्र को हमने क्यों भुला दिया है। आखिर जिस देश ने अपने शहर नदियों के किनारे बसाए, जिस देश ने अपने पूजा-संस्कार की विधियां नदियों के किनारे और नदियों को लेकर विकसित किए, नदियां देवी मानी गईं, वहां यह सूत्र गायब कैसे हो गया? आखिर हमारे सबसे पुराने ग्रंथों, जो देवों की वाणी भी हैं, ऋग्वेद समेत तमाम वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणों में नदियों और उसकी महिमा का विस्तार से जिक्र है तो अचानक हमारे समाज को क्या हो गया कि हमने नदियों और झील-तालाबों को कूड़ेदान समझ लिया? उन्हें सुखा देने की साजिश करने लगे। हमारे देश की हर नदी के साथ लोकगीत हैं, उनसे जुड़ी लोककथाएं हैं। थोड़ा इतिहास भी है और थोड़ा विज्ञान भी। परंपरा और रीति-रिवाज तो खैर हैं ही। ऐसे में नदियों को लेकर हम क्या सोचते हैं, नदीसूत्र उसका एक किस्म का रियलिटी चेक भी है।

नदियों के विज्ञान को लेकर विश्वविद्यालयों में होने वाली पढ़ाई में बड़ा संकट है। नतीजतन समाधान की रूपरेखा में ही परिपक्वता की कमी रही है। मसलन नदी की संकल्पना और सिद्धांत आम से लेकर खास तक के लिए स्पष्ट नहीं हैं। आमतौर पर माना जाता है कि नदी का काम पानी ले जाना है, जो आगे जाकर समुद्र में मिल जाती है, लेकिन क्या हमने कभी यह सुना है कि नदी का काम गाद ले जाना भी है? खासकर गंगा जैसी नदियों के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण है। यह बुनियादी सोच ही शायद योजनाओं और परियोजनाओं में जगह नहीं बना पाई, नतीजा फरक्का बराज जैसी परियोजनाएं होती हैं। जिसने न केवल लाखों लोगों को बेघर कर दिया, बल्कि हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन भी विसर्जित हो गई। गंगा जैसी नदी हमारी सभ्यता, हमारे पाप-पुण्य सबको संभालती रही, लेकिन आबादी और उम्मीदों के बोझ ने उसे आज हरा दिया है। अक्सर अपने गंगा की सफाई से जुड़ी परियोजनाओं और अभियानों में भ्रष्टाचार से जुड़ी कहानियां जरूर सुनी होंगी। देश के किसी भी हिस्से में नदियों और नदी घाटियों को लेकर सरकारी सोच में एक निरंतरता मिलती है यानी बड़ी परियोजनाएं बनाना और लागू करना।

असल में बड़ी परियोजनाओं का फायदा सबको मिलता है, सिर्फ नदी और उनके बेटों को छोड़कर यानी बड़ी परियोजनाएं, बड़ी राशि, बड़ा कट। बड़ी सामान्य-सी बात है, लेकिन परियोजनाएं भी वैसी बनीं और बनाई गईं और अभी भी बुनी जा रही हैं, जिनको पश्चिमी देशों ने नकार दिया है। फरक्का बराज इसी का उदाहरण है। सूखा भयावह रूप अख्तियार कर रहा है। हमें नदियों को साथ रखकर आगे बढ़ना सीखना होगा। एकआयामी विकास नहीं, बल्कि सतत विकास की ओर बढ़ना होगा, जिसमें साफ-सुथरी, जीवित और कलकल-निर्मल-अविरल नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

(साभार : गुस्ताख ब्लॉग में मंजित ठाकुर)

मेलबाक्स

कांग्रेस को उबरने की जरूरत

संजय गुप्त ने अपने आलेख 'लगातार कमजोर होती कांग्रेस' में एक सशक्त विपक्ष की दृष्टि से कांग्रेस के मजबूत होने की जो जरूरत महसूस की है, वह देश-काल-परिस्थिति के अनुरूप बिल्कुल सही है। वर्तमान में मोदी के नेतृत्व में उभरती भाजपा पुनः केंद्र की सत्ता पर विराजमान है। कुछ राज्यों को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों में भी उसकी सत्ता है। जबकि दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस अपनी बची-खुची राज्य इकाइयों को भी बचा पाने में असहाय दिखाई दे रही है। कर्नाटक और गोवा राज्य के अवसरवादी कांग्रेसी विधायक पार्टी से इस्तीफा देकर अपने सुखद भविष्य की तलाश में जुटे हुए हैं। यह विरोधात्मक स्थिति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। माना कि स्वार्थपरक अवसरवादी राजनीति में उगते सूरज को सलाम करने का चलन है, लेकिन भारतीय राजनीति में इस चलन का एक परंपरा के रूप में विकसित होना ठीक नहीं है। राजनीति से जुड़े लोगों में सत्तासुख की लालसा उनकी दलीय निष्ठा से कहीं ऊपर दिखाई देती है। जिसकी झलक कर्नाटक और गोवा में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। निःसंदेह इस प्रवृत्ति के लिए वह नेतृत्व ही दोषी है जो अपने नेताओं में उस दलीय निष्ठा को पैदा नहीं कर पाया जो हर स्थिति में एकजुट रहकर पार्टी को मजबूत कर पाते। वस्तुतः अब समूची कांग्रेस को इस प्रश्न पर मंथन करने की जरूरत है कि क्या वह नेहरू परिवार के बिना एकजुट रहकर सशक्त विपक्ष के रूप में अपने को स्थापित कर सकती है? यदि हां! तो उसे अपेक्षित सावधानी के साथ नए नेतृत्व के चयन में देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले भी नेहरू परिवार से इतर सीताराम केसरी और नरसिंहा राव जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं, लेकिन नेहरू परिवार की चाटुकारी निष्ठा से ग्रस्त कांग्रेसी नेता पर्दे के पीछे रहकर उनकी टांग खिंचाई करते रहे। अपनी डूबती कस्ती को संभालने के लिए कांग्रेस को इस बेढब स्थिति से भी बचने की जरूरत है।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

बढ़ती जनसंख्या

गत 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए और निरंतर बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की गई। लगातार बढ़ती जनसंख्या पूरी दुनिया के लिए और खासकर हमारे देश के लिए एक विकट समस्या बन गई है। दिनोंदिन बढ़ रही जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधन सिमटते जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और यहां तक कि भारतीय जेलों में उनकी असल क्षमता से कई गुना अधिक जनसंख्या का भार व्याप्त हो गया है। दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य के लिए लाइन लगाना एक परंपरा सी बन गई है। जल, जंगल और जमीन का दायरा सिमटता जा रहा है। जीव-जंतुओं के आश्रय और हमारी प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है। देश में गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण और बेरोजगारी लगातार अपने पैर पसार रही है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम से हमें हर रोज जूझना पड़ता है। सरकार को इस संवेदनशील मामले पर तुरंत विचार करना चाहिए और एक ठोस जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू करना चाहिए। विकास की रफ्तार को हम जितना मर्जी तेज कर लें जब तक देश में जनसंख्या स्थिर नहीं की जाएगी तब तक विकास अधूरा ही रहेगा। आम नागरिकों को भी इस विषय पर चिंतन करना चाहिए।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव

जजों की कमी

देश की निचली अदालतों में जजों की भारी कमी को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों से जजों की नियुक्ति पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सर्वविदित है कि देश की निचली अदालतों में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन उनका निस्तारण करने वाले जज ही उपलब्ध नहीं हैं। मुकदमों का बोझ अदालतों के ऊपर दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित व्यक्ति न्याय की उम्मीद में अदालत आता है और मुकदमा दायर करता है, लेकिन तारीख लेकर लौट जाता है। धीरे-धीरे तारीख ढोते-ढोते वह थक जाता है। कई बार तो जब मुकदमे के फैसले का वक्त आता है, तब तक उसे दायर करने वाला दुनिया से जा चुका होता है। कहा गया है कि देर से मिला न्याय न्याय ना मिलने के बराबर है, इसलिए सरकारों को चाहिए कि इस समस्या का त्वरित संज्ञान लेकर मानक के अनुरूप जजों की भर्ती अतिशीघ्र कराई जाए।

brijlaltiwari476@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

26.7 करोड़ से अधिक है भारत में तंबाकू और इससे जुड़े विविध उत्पादों का सेवन करनेवालों की संख्या।

आजकल

शर्तों पर आधारित हो रेलवे का निजीकरण

भारतीय रेलवे में यदि एक मल्टी मॉड्यूल नियमन प्राधिकरण के तहत निजी निवेश को आमंत्रित किया जाए तो रेलवे भी भारत में टेलीकॉम की तरह एक बड़ी परिवहन क्रांति का सूत्रधार बन सकती है। रेलवे का निजीकरण करना चाहिए, लेकिन परंपरागत निजीकरण के मॉड्यूल पर नहीं, बल्कि एक ऐसे होशियारी भरे नियमन प्राधिकरण के तर्ज पर जिसमें रेलवे में अल्प निवेश का सांप भी मर जाए और निजी क्षेत्र के मुनाफे की लूट की लाठी भी बच जाए। यह सब रेलवे के निजीकरण के रणनीतिकारों की सूझ-बूझ पर भी निर्भर होगा

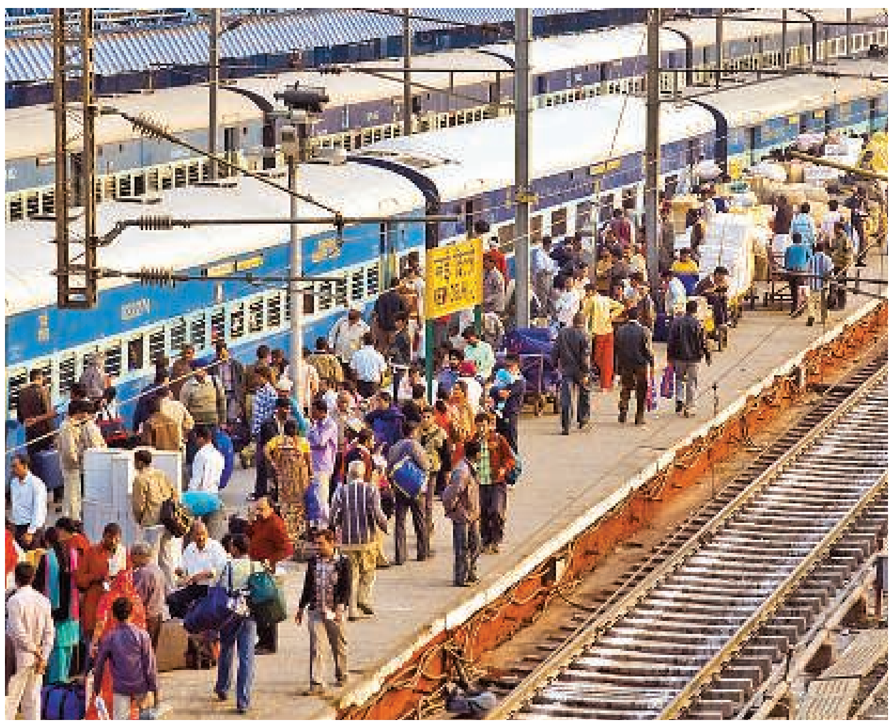

मनोहर मनोज
वरिष्ठ पत्रकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट में वैसे तो कई सारे आर्थिक विजन प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु इन सबमें भारतीय रेलवे में निजी क्षेत्र के आमंत्रण का जो उल्लेख है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी परिघटना है। दरअसल भारतीय रेल के इतिहास में निजी क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका की पहली बार कोई रूप रेखा प्रस्तुत की गई है। रेलवे की मौजूदा स्थिति में इस पहल की जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है, वह है भारतीय रेलवे में अगले एक दशक के दौरान करीब 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की दरकार। यह विशाल निवेश राशि अकेले सरकार के बूते की बात नहीं, लिहाजा निजी क्षेत्र को भी इसमें भागीदारी का न्योता दिया गया है।

हालांकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि निजी क्षेत्र के आने के बाद भारतीय रेलवे, जो विशाल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अपना सरीखा परिवहन माध्यम है, वह नहीं रहेगा और महंगा हो जाएगा। दरअसल भारतीय रेलवे को किसी भावुकता भरी नजरों से सरकारी सामाजिक उपक्रम के रूप में देखकर हम इसकी मौजूदा स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारतीय रेलवे सरकारी स्वामित्व में चलकर भारत के करोड़ों लोगों को केवल गुदगुदाता ही हो, यह उतना ही रुलाता भी है। इसमें लंबी दूरी की यात्रा हो या कम दूरी की, बहुत ही बुरे हालात में लोग यात्रा करते हैं।

भारतीय रेलवे की सभी विशिष्टताओं को बरकरार रखते हुए तथा इसमें मौजूद अक्षमताओं, कमियों व लीकेज को दूर करने हेतु हमें निजीकरण का एक सक्षम मॉड्यूल बनाना होगा। इस निजीकरण मॉड्यलू की पूरी मैकेनिज्म निर्धारित होने के उपरांत ही इसमें निवेशजनित निजीकरण को अमली जामा पहनाने का काम तय हो पाएगा। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारतीय रेलवे का नेटवर्क आजादी के समय करीब 50,000 किलोमीटर था, जो पिछले सात दशकों में बढ़कर केवल 65,000 किलोमीटर हो पाया है, जबकि यात्रियों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। हमें इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि भारतीय रेलवे को यात्री टिकट से उसकी पूरी आमदनी में केवल एक तिहाई का योगदान ही हो पाता है, जबकि उसके कुल खर्चे का दो तिहाई यात्रियों की आवाजाही पर होता है।

दूसरी तरफ माल परिवहन रेलवे की आमदनी में दो तिहाई का अंशदान करता है, और खर्चे का केवल एक तिहाई उपयोग करता है। जाहिर है रेलवे का यात्री गाड़ियों का संचालन पूरी तरह से क्रॉस सब्सिडी के जरिये होता है। रेलवे के पास करीब छह हजार स्टेशन, देश का दूसरा सबसे बड़ा भूमि बैंक, करीब 15 लाख लोगों का कार्यबल, लगभग एक करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार देने का गौरव तथा भारत की समूची अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन होने का श्रेय हासिल है, फिर भी इसका कुल कारोबार महज डेढ़ लाख करोड़ रुपये का ही है। इससे ज्यादा कारोबार तो एक पेट्रोलियम सार्वजनिक उपक्रम कर लेता है, जबकि खुद रेलवे के पास एक दर्जन अपने सार्वजनिक उपक्रम हैं। कहीं न कहीं हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय रेलवे का मुनाफा टिकट परीक्षक, दलाल, ठेकेदार, भ्रष्ट रेलकर्मी और बड़े अधिकारियों समेत अनेक राजनीतिज्ञों की जेब में जा रहा है। इसीलिए यह सोचने की नौबत आ गई है कि भारतीय रेलवे को एक मामूली मुनाफा कमाने के लिए भी संघर्ष क्यों करना पड़ता है? जाहिर है कि एकाधिकार की स्थिति चाहे सरकारी स्वामित्व में हो या निजी स्वामित्व में, उसकी अपनी विरूपताएं होती ही हैं। पिछले सात दशकों के दौरान रेलवे में बहुस्तरीय संरचनात्मक परिवर्तन का एक व्यापक विजन आया ही नहीं। इसलिए भी आज भारतीय रेलवे में व्यापक बदलाव की जरूरत है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में लोकल ट्रेनों में न तो टिकट चेकिंग होती है और न ही टिकट आसानी से मिल पाते हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे का राजस्व मारा जाता है।

यदि सरकार वेंडिंग मशीन के जरिये राजस्व कमाने में अक्षम है तो निजी क्षेत्र को इसमें शामिल करे। निजीकरण तब तक खराब नहीं है जब तक यात्रियों पर अनाप-शनाप बोझ न डाला जाए। रेलगाड़ियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो, ऑन डिमांड टिकट हमेशा उपलब्ध हो, पार्सल बुकिंग सरल तरीके से हो जाए। हालांकि पिछले चार सालों में मोदी सरकार के दौरान रेलवे में सालाना पूंजीगत निवेश में काफी वृद्धि हुई है। पिछले पांच साल में रेलवे में पूंजीगत निवेश में करीब छह गुना बढ़ोतरी हुई। रेलवे का विद्युतीकरण बढ़ा है, ट्रैक का नवीनीकरण बढ़ा है। परंतु अभी भी भारतीय रेलवे में तमाम विसंगतियां हैं। कई जगहों पर पर्याप्त किराया नहीं लिया जाता है जबकि कई जगह यात्रियों को हजारों रुपये का जुर्माना देना पड़ता है।

यदि इन तमाम कार्यों के निष्पादन में निजी क्षेत्र को न्यौता दिया जाता है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं, बशर्ते निजीकरण का एक ऐसा मल्टी मॉडल गठित हो जिसमें कई चीजों को समाहित किया गया हो। मसलन इसमें निजी और सार्वजनिक भागीदारी भी हो तथा आपसी प्रतियोगिता भी हो। टेलीकॉम की तरह इसमें बहुस्तरीय नियमन प्राधिकरण का गठन हो। निजी क्षेत्र के लिए खुले चरने के लिए इसमें मलाइदार क्षेत्र का आबंटन नहीं, बल्कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के तहत प्रशुल्क और मुनाफा कमाने की बंदिशें हों।

आज वाकई रेलवे में सबसे ज्यादा निवेश की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में देश भर में नए रेलवे ट्रैक बिछाने की जरूरत है। यदि नए नियमन प्राधिकरण के तहत निजी क्षेत्र इसमें निवेश करते हैं तो उन्हें भविष्य में निवेश के हिसाब से राजस्व की हिस्सेदारी देने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ट्रेन के संचालन की जिम्मेदारी बिजली वितरण के क्षेत्र में कार्यरत निजी उपक्रमों के तर्ज पर दी जा सकती है। परंतु किराया, जुर्माना और सुविधा समेत रोजगार सृजन का निर्धारण सरकारी नियमन प्राधिकरण के तहत होना चाहिए। जब एक अच्छे रेलवे स्टेशन बनाने की लागत एक शॉपिंग मॉल के ही बराबर है तो फिर एक शॉपिंग मॉल के तर्ज पर एक स्टेशन से भी राजस्व क्यों नहीं अर्जित किया जा सकता है। आज का आर्थिक दौर नियमन प्राधिकरण का है। सरकारी एकाधिकार व निजी एकाधिकार दोनों उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। आखिर भारतीय रेलवे की प्रीमियम ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है? वह भी निजी क्षेत्र की तरह लूट का एक सरकारी नमूना है।

- इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर

रेलवे को बदलना होगा रवैया

संदीप/ बी रामकृष्ण राजू

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल पिछले काफी समय से लगातार यह कह रहे हैं कि भारतीय रेल के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। हालांकि इतना जरूर है कि भारतीय रेल पर्यटन वाले मार्गों पर रेल संचालन हेतु निजी क्षेत्र की इकाइयों को आमंत्रित करेगी। शुरू में भारतीय रेल अपने ही उद्यम आइआरसीटीसी को दो गाड़ियां संचालन हेतु देगी जिसमें सालाना किराये के बदले गाड़ियों का स्वामित्व उसे मिल जाएगा। यह एक प्रकार से निजीकरण की शुरुआत है। सरकारी एयरलाइंस के क्षेत्र में भी निजीकरण की शुरुआत कुछ इसी तर्ज पर हुई थी, जिसके बाद इसका क्या हश्र हुआ वह हमारे सामने है।

भारतीय रेल के गैर जिम्मेदाराना रवैये का पता सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के प्रति उसके नजरिये से चलता है जिसमें कई बार यात्री जानवरों के झुंड की तरह यात्रा करते हैं। द्वितीय श्रेणी और गैर-वातानुकूलित शयनयान श्रेणी में समय के अनुकूल बहुत ही कम सुधार हुआ है और यात्री सुविधाओं में अल्प बढ़ोतरी ही हो पाई है। हां, यदि उच्च श्रेणी की बात करें तो इसमें जरूर यात्रा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यह इस बात को भी स्पष्ट करता है कि सामान्य श्रेणी की यात्रा को सुगम बनाने की ओर रेल अधिकारियों ने ज्यादा प्रयास नहीं किया है। उदाहरण के लिए पूरी तरह से वातानुकूलित डिब्बों वाली गाड़ियां तो बड़ी संख्या में शुरू की गई है, किंतु जिन मार्गों पर भीड़ ज्यादा है उन पर सभी सामान्य श्रेणी के डिब्बों वाली मेल-एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने के बारे में नहीं सोचा गया। दिव्यांगों के लिए डिब्बे भी गाड़ी के एक छोर पर ही लगाए जाते हैं जबकि ऐसे यात्रियों का डिब्बा स्टेशन पर बीच में होना चाहिए ताकि प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने के बाद कम से कम चल कर अपने डिब्बे तक पहुंचा जा सके।

लंबी दूरी की गाड़ियों में शौचालयों में पानी आपूर्ति हेतु पानी भरना रेल के लिए, जब तक कोई शिकायत न करे, प्राथमिकता नहीं होता, जिससे यात्रियों को होने वाली असुविधा की कल्पना की जा सकती है। आजकल ट्रेनों में बायो-शौचालय लगाए जा रहे हैं जिनमें से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। बंद जगह पर मिथेन से इंसान को घुटन महसूस होती है। भारत में प्रत्येक वर्ष सीवर में घुसने व मीथेन के घुटन से मरने वालों की संख्या औसतन 1,800 है। खुले आसमान में मीथेन छोड़ने से जलवायु परिवर्तन की स्थिति बदतर होगी। भारतीय रेल के पास मीथेन भंडारण या प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है।

कई बार स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही गाड़ी को बाहर इतनी देर के लिए रोक लिया जाता है कि यात्री गाड़ी से उतर कर प्लेटफॉर्म की ओर पैदल ही चल देते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि प्लेटफॉर्म खाली होते हुए भी क्यों गाड़ियों को स्टेशन के बाहर रोक लिया जाता है? सवाल खड़ा होता है कि कंप्यूटरीकरण के दौर में तकनीक के इस्तेमाल से उपलब्धता के अनुसार गाड़ियों को प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं भेजा जा सकता है, ताकि विलंब की वजह से यात्रियों को परेशान न होना पड़े? देश में कई रेलमार्गों और स्टेशनों पर मरम्मत का काम पूरा होने के बावजूद वहां से 'कॉशन' खत्म नहीं किया जाता, जिस कारण वहां से रेलों को गुजरने में ज्यादा समय लगता है।

लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में खानपान से जुड़ी कई शिकायतें आती हैं। आइआरसीटीसी द्वारा खाने-पीने की चीजों की ज्यादा कीमत वसूली जाती है। जो शाकाहारी खाना 50 रुपये में मिलना चाहिए उसके लिए यात्रियों से सौ- डेढ़ सौ रुपया तक वसूला जाता है। सवाल पूछने पर पेंट्री का कर्मचारी बताता है कि सब्जी में पनीर डाला गया है इसलिए ज्यादा कीमत वसूली जा रही है। परंतु यात्री को बिना पनीर की सब्जी का विकल्प ही नहीं दिया जाता और पनीर की सब्जी की भी औपचारिक कीमत तय होनी चाहिए। सात रुपये की टी-बैग वाली चाय खुलेआम 10 रुपये में बेची जाती है। पानी की बोतलें भी तय कीमत से ज्यादा दर पर बेची जाती हैं।

सवाल खड़ा होता है कि रेलवे को इतना महंगा पानी बेचने की क्या आवश्यकता है? रेलवे की यह जिम्मेदारी है कि सभी यात्रियों को साफ पीने का पानी निःशुल्क उपलब्ध कराए, लेकिन आज देश के अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर आपको पीने का साफ पानी निःशुल्क नहीं मिल सकता है। स्टेशनों पर पानी भी केवल रेल नीर ही मिलना चाहिए जबकि ऐसा होता नहीं है।

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं)

खरी-खरी

इक बगल में चांद, दूजी में रोटियां

मुकेश जोशी

दुनिया भले चांद पर पहुंच जाए, इंसान की पहली जरूरत रोटी ही होती है। कविता वाले लिख गए हैं- भूख में रोटी का टुकड़ा भी चंदा लगता है। आदमी कितना भी तरक्की-पसंद हो गया हो, धोती-कुर्ता छोड़ जींस-टीशर्ट में आ गया हो, साइकल से फटफटी पर होते हुए महंगी कारों में आ गया हो, पर उसके रोटी के सवाल वहीं, वैसे के वैसे खड़े हैं। और वो आज भी खड़ा है एक अदद रोटी की कतार में।

कतार की बात पर यकीन न हो तो कोई भी मैरिज गार्डन, विवाह मंडप, होटल-धरमसाला में हो रही शादी में हो आइए, गरीब से लेकर रईस तक तप रहे तंदूर के सामने तेज आंच पर ठप-ठप, फट-फट आटे की लोई दबाकर बनाई जा रही रोटी के लिए हाथ में प्लेट लिए खड़े मिलते हैं। पसीने में नहाए 'रोटीबाज' के सामने तब सब भिखारी से लगते हैं। वहां कई 'रोटीराम' एक के ऊपर एक प्लेट टांगे खड़े होते हैं, एक रोटी का सवाल है बाब के स्टाइल में। मजे की बात ये कि तंदूरची तो किसी की तरफ देखता भी नहीं। भले सामने अंबानी खड़ा हो, वह तो जैसे ही आठ-दस रोटियां तंदूर से एक साथ निकालता है, निष्काम भाव से सामने खड़े गरीबों में बांट देता है। अब रोटी आठ-दस और लपकने वाले 15-20! यहां से शुरू होता है उस सधे हुए कौशल का प्रदर्शन कि रोटी छीन भी ली जाए और किसी को ये भी न लगे कि अपन भुक्खड़ हैं। जिसे मिली, वो बाहर खिसियानी मुस्कराहट और अंदर विजेता भाव लिए, जीती हुई ट्रॉफी को प्लेट में रख, प्लेट को प्लेन की तरह उड़ाते हुए एक कोने में निकल लेता है।

कच्ची-पक्की, जली-भुनी, चीठी-चामठी, घी लगी-रुखी... कैसी भी हो, वो दीन-हीन उसे वैसे ही स्वीकारता है, जैसे भंडारे की पूड़ी। दूल्हा कौन है, दुल्हन का लहंगा कित्ते लाख का है या उन दोनों के बाऊजी के कित्ते के काम लग गए हैं, उससे उसे क्या लेना-देना! जो देना था, स्टेज पर दे दिया, अब तो जो लेना है, उसी के पानीपत में लट्टूम रहे हैं। 'रोटी का संघर्ष' हर विवाहोत्सव की दृश्यावली है। पंगत (पंक्तिभोज) के दिन याद कीजिए, जब कार्यक्रम में रोटी बनती ही नहीं थी। सब्जी-पूड़ी, दाल-भात, गुलाब जामुन, और गर्मी थोड़ी ज्यादा हुई तो पीने-फैलाने के लिए रायता। तब लोग गरीब थे पर भोजन अमीरी का हुआ करता था। मेजबान सबके पास आकर मनुहार करता और ठाठ से जिमाता। अब लगे हैं रोटी की झीना-झपटी में।

ट्वीट-ट्वीट

जो अध्यक्ष महोदय खुद इस्तीफा दे चुके थे उन्हें अपना इस्तीफा सौंपने वाले नवजोत सिंह सिद्धू जी ने इस्तीफे की चिट्ठी महीने भर बाद सार्वजनिक की है। कैबिनेट से इस्तीफा देना है तो मुख्यमंत्री को क्यों नहीं सौंपा? महीने भर में दाल नहीं गली तो अब वे यह कौन सा नया पैंतरा अपना रहे हैं?
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

भारत चांद की ओर कदम बढ़ा रहा है। मैं चंद्रयान-2 की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं। मैं हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सलाम करता हूं जिन्होंने इसे संभव बनाया। भारत माता की जय। आपने हमें गर्वान्वित किया।
तारिक फतेह@TarekFatah

जल्द ही तुर्की में वृक्षारोपण के लिए एक राष्ट्रीय अवकाश की व्यवस्था शुरू होगी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में भी ऐसी व्यवस्था करने का आग्रह करता हूं। वृक्षारोपण के साथ ही पेड़ों को नियमित रूप से पानी देना भी सुनिश्चित किया जाए। इस मकसद से छुट्टी के लिए बरसात के आसपास का दिन सही रहेगा।
ध्रुव राठी@dhruv_rathee

आशुतोष शुक्ल
संपादक, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश डायरी

यूपी प्रशासन पर बैठा है आक्टोपस

तीन दिन पहले यानी 12 जुलाई की रात आगरा से लखनऊ आ रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की एक बस पलटते-पलटते बची। पहले तो पंक्चर टायर पर बस चली और जब चालक सो गया तो कंडक्टर ने गाड़ी चलाई। हलक में दिल लिए डरे सहमे यात्री किसी तरह लखनऊ पहुंचे। यह घटना उस आगरा एक्सप्रेस वे की है जिस पर केवल चार दिन पहले एक हृदयविदारक दुर्घटना में 29 लोगों की मौत हो चुकी थी और राज्य सरकार आगे ऐसे हादसे न होने देने की कसमें खा रही थी।

पाठकों, यही है असली उत्तर प्रदेश। जिद्दी और मासूमों का दुश्मन। हादसे जहां महज चर्चा के लिए होते हैं। दुर्घटना होती है, बयान आते हैं, सरकारें दावे करती हैं, लेकिन चंद ही दिनों में फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर लोग मरते हैं और फिर बयान आ जाते हैं। दल निरपेक्ष यह बेशर्मी उत्तर प्रदेश का आभूषण है। आगरा हादसे के बाद परिवहन मंत्री ने आदेश दिया कि अब से चालक मार्ग में खाना खाने के बाद यदि बस चलाएगा तो पहले वज्रासन करेगा। हुआ क्या? यूनियनों और प्रशासनिक लापरवाही के मारे परिवहन निगम ने उल्टे जनता को वज्रासन करा दिया। आगरा एक्सप्रेस वे पर ढाई साल में चार सौ मौतें हो चुकी हैं, लेकिन उनसे कोई सबक नहीं लिया जा सका। चार सौ परिवार सदा के लिए शोक संतप्त हो गए, लेकिन उनका दुख चार लाइनों के प्रेस नोट से अधिक महत्व न पा सका। यही कारण है कि लोग अब इस सड़क पर चलने से डरने लगे हैं। आमजन का यह भय यूपी सरकार की चिंता होना चाहिए। परिवहन निगम का हाल बहुत बुरा है। बसें ठीक करने की वर्कशॉप में मैकेनिकों के 70 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। आप पूछेंगे कि फिर काम कौन कर रहा है? यात्रियों की जान अकुशल श्रमिकों के भरोसे है। 80 हजार किलोमीटर चलने के बाद बस का इंजन ऑयल बदला जाता है और उसके पिछले टायर पुराने लगाए जाते हैं। नए टायर केवल आगे लगते हैं। अब तो भाजपा सरकार को भी सवा दो साल हो गए हैं लिहाजा पिछली सरकार पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। वैसे बीते हफ्ते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर सीबीआइ छापों से निकली। सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति बड़े घोटाले में आरोपित हैं। उनके घर और दफ्तरों पर 10 जुलाई को सीबीआइ छापे पड़े तो उनके साथ चार आइएएस अधिकारियों को भी घेरा गया। उनके यहां भी सीबीआइ पहुंची। इनमें बुलंदशहर के डीएम अभय सिंह और आजमगढ़ के सीडीओ डीएस उपाध्याय भी थे। इन अधिकारियों पर अपनी पिछली तैनाती के दौरान अवैध खनन कराने का आरोप है। यूपी में नौकरशाही इस कदर बेलगाम हो चुकी है कि अभय सिंह के यहां मिली नकदी को गिनने के लिए सीबीआइ को मशीन मंगानी पड़ी। उनके यहां 49 लाख रुपये मिले। सामान्य नौकरीपेशा आदमी के लिए इतनी बड़ी रकम कल्पनातीत है। किसी प्रथम श्रेणी अधिकारी के पीएफ जितनी रकम एक छापे में निकल आना इस बात का प्रमाण है कि आखिर क्यों नोटबंदी से पहले प्रापर्टी की कीमतें आसमान छूती थीं। इन छापों में अफसरों के यहां नकद रकम भी मिली और अनेक दस्तावेज भी। योगी सरकार बेशक कह सकती है कि छापों के तत्काल बाद अफसरों को हटा दिया गया, लेकिन प्रश्न है कि सपा सरकार के खराब छवि वाले अधिकारियों को बढ़िया तैनाती मिल कैसे गई। यही वह मूल कारण है जो उत्तर प्रदेश में नागरिक सुविधाओं को पनपने नहीं देता। यूपी के प्रशासनिक तंत्र को आक्टोपस की तरह जकड़ चुकी है नौकरशाही। नेता और अफसर यहां गलबहियां करते हैं और कालेधन का सावन उन्हें गीत सुनाता है। सरकार बच्चों को जूते मोजे बांटने का ऐलान करती है, लेकिन कहीं-कहीं तो मोजे हफ्ते भर भी नहीं चल पाते। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में आम लोग तड़प कर रह जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती।

अब एक खबर राजनीति से...

चुनाव हारने के बाद 10 जुलाई को पहली बार राहुल गांधी अमेठी पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भावुक संवाद किया। डेढ़ दशक अमेठी से सांसद रहे राहुल का उससे लगाव स्वाभाविक है। कार्यकर्ताओं ने उनसे अध्यक्ष बने रहने की अपील भी की। राहुल को यदि यूपी में कांग्रेस को जीवित करना है तो अमेठी से नाता जारी रखना होगा। अच्छा या बुरा, अमेठी का संदेश बहुत जगह जाएगा।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

बच्चों के साथ बढ़ते दुष्कर्म के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता से अंकुश लगेगा?

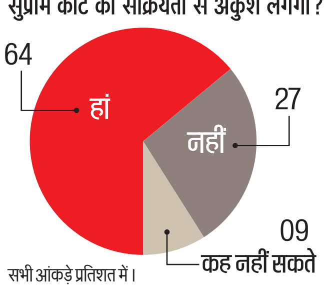

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

कांग्रेस की राज्य इकाइयों में अस्थिरता शीर्ष नेतृत्व में अनिश्चितता के कारण उत्पन्न हुई है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

इस्तीफा खुद दे चुका है जो पक्षाध्यक्ष,
इस्तीफा देना उसे नौटंकी प्रत्यक्ष।
नौटंकी प्रत्यक्ष न यूं सिद्धू दिखलाओ,
इस्तीफा ले आप कैप्टन के घर जाओ।
ले घोड़े की लीद न जाए आंगन लीपा,
दो सीएम को जाय प्रेम से तुम इस्तीफा।
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

ई-सिगरेट पर पाबंदी का प्रभाव

भारत में ई-सिगरेट को लेकर संदेह काफी बढ़ रहा है। ऐसे में आवश्यक यह है कि हम धूम्रपान करनेवालों तक इतनी विश्वसनीय सूचना पहुंचा सकें कि वे उस पर भरोसा कर सकें

डॉ. आमिर उल्लाह खान
वरिष्ठ अर्थशास्त्री

भारत में तंबाकू की समस्या एक चिंता का विषय है। हमारे देश में तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों का सेवन करनेवालों की संख्या 26.7 करोड़ पार कर गई है। चिंताजनक यह है कि तंबाकू से होने वाली बीमारियों के कारण प्रत्येक मिनट पांच लोगों की मौत हो जाती है। एक अनुमान के मुताबिक विश्व भर में धूम्रपान करने वालों में से 11.2 फीसद लोग भारत में रहते हैं। ऐसे में देश के नीति निर्माताओं द्वारा ई-सिगरेट पर अपनाया गया सख्त रवैया इस पूरे मुद्दे पर उपभोक्ता के दृष्टिकोण को पीछे छोड़ता हुआ दिखाई देता है।

सिगरेट के धुएं से कई तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे फेफड़ों का कैंसर, धमनी रोग, फेफड़े की बीमारी और हृदय रोग आदि। धूम्रपान करने वालों में से करीब 50 फीसद तो असमय ही धुएं से संबंधित रोग के कारण मर जाते हैं। इन सब खतरों के बावजूद, करोड़ों लोग प्रतिदिन धूम्रपान करते हैं। अनुमान बताते हैं कि अगर ऐसे ही धूम्रपान की दर जारी रही तो 21वीं सदी में धूम्रपान से संबंधित रोगों के कारण एक अरब लोगों की मौत हो जाएगी। हालांकि धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए कई तरह की दवाइयां बाजार में उपलब्ध है, लेकिन बहुत से धूम्रपान करनेवाले उन्हें आजमाना नहीं चाहते। इनमें से जो लोग इसका उपयोग करते भी हैं, उनमें से अधिकांश विफल हो जाते हैं या एक साल के भीतर फिर से धूम्रपान करने लगते हैं।

ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि लोगों को सिगरेट की जगह कम हानिकारक विकल्प का रुख करना चाहिए। 'धूम्रपान के विकल्प' पर एक हालिया परिचर्चा में बार-बार एक सवाल उठा- क्या विकल्पों पर प्रतिबंध से धूम्रपान करनेवाले धूम्रपान करना छोड़ देगा? क्या शराब पर पाबंदी लगाने से लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया? इन सब सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। पिछले दस सालों से सिगरेट का सेवन करने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि उसने धीरे-धीरे ई-सिगरेट को अपनाया ताकि सेहत का कम नुकसान हो, लेकिन इस पर पाबंदी से वह घबराया हुआ है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने किसी बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के लिए बड़े समाधान के तौर पर पाबंदी का रास्ता अपनाया हो।

प्रतिबंध लगाने से समाचार तो अच्छे बनते हैं, लेकिन नीतियां बुरी बनती हैं। कराधान, कठोर नियमों आदि के माध्यम से तंबाकू के बोझ को कम करने के अनगिनत प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस संबंध में कामयाबी नहीं मिल पाई है, क्योंकि यह 'छोड़ने की कोशिश करने' और 'छोड़ देने' के बीच की लड़ाई है। इस समस्या का मुख्य केंद्र है- तंबाकू की लत। हमारे समय के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट में से एक से निपटने का कोई शॉर्टकट नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, तंबाकू नियंत्रण के एक स्तंभ के रूप में इससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिम को मान्यता देता है। इस तरह के मुद्दों पर नीतिगत निर्णय कठोर वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित होने चाहिए और व्यक्ति को ईएनडीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम के साथ-साथ धुआं छोड़ने वाली सिगरेटों के संबंधित जोखिमों पर भी विचार करना चाहिए। उपलब्ध वैज्ञानिक सबूतों के अनुसार यह स्पष्ट है कि धूम्रपान का यह तरीका स्मोकिंग के जोखिम का एक हिस्सा भर है। यह लगभग 95 प्रतिशत कम हानिकारक है। बड़ी बात यह है कि हमारे शहरों के हर गली मोहल्ले में बीड़ी और तंबाकू सिगरेट उपलब्ध हैं, तब आप ई-सिगरेट के विरोध में कोई तर्क कैसे दे सकते हैं, क्योंकि यही संभवतया इकलौता सुरक्षित विकल्प है?

अब अतीत से जुड़े कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। गुजरात पूर्ण शराबबंदी को लागू करने वाला पहला राज्य था, पर यहां शराब की खपत बहुत अधिक है और यह अवैध रूप से फल-फूल रही है तथा अवैध और नकली शराब की आपूर्ति का संपन्न व्यवसाय है। अहमदाबाद में पिज्जा से ज्यादा तेजी से शराब की होम डिलीवरी हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित कोहिमा और दीमापुर में शराब ग्रॉसरी, कंफेक्शनरी और गारमेंट शॉप्स, रेस्तरां, और यहां तक कि पान की दुकानों में भी आसानी से उपलब्ध है। य

ादि आप सार्वजनिक बेहतर स्वास्थ्य लाभ के दृष्टिकोण से देखते हैं तो अधिक जहरीली सिगरेट तक पहुंच रखने वाले लोगों के लिए कम नुकसानदेह ई-सिगरेट को प्रतिबंधित करना बेतुका तर्क है। भले ही सरकार युवाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले ई-सिगरेट के प्रभाव, गुणवत्ता मानकों, निकोटीन सामग्री, विपणन, प्रचार और लेबलिंग के बारे में चिंतित है, लेकिन हमें इसे प्रतिबंधित करने के बजाय श्रेणी को विनियमित करके इस समस्या का हल तलाशना होगा।

दुनिया भर के कई देशों ने इन उपकरणों के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव पर शोध करने में अधिक निवेश करने का विकल्प चुना और इस पर पाबंदी लगाने के बजाय इसके सकारात्मक प्रभाव को इष्टतम करने के लिए उचित नियम भी बनाए हैं। संभव है कि यह एक कदम वापस लेने और दुनिया भर के 98 से अधिक देशों से कुछ सीखने का समय है, जिन्होंने इस श्रेणी को विनियमित किया है। यूएई, सेशेल्स और थाईलैंड जैसे देशों, जिन्होंने पहले इस श्रेणी पर प्रतिबंध लगा दिया था, अब ई-सिगरेट के कम नुकसान को देखते हुए इसके उपयोग के लिए नियम बना रहे हैं ताकि युवा स्मोकर्स को गुणवत्तापूर्ण नियंत्रित उत्पाद प्रदान किए जा सकें।

इस संबंध में नियम बनाते समय ई-सिगरेट व आम सिगरेट के जोखिमों पर विचार महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रमाण उपलब्ध हैं जो साबित करते हैं कि पारंपरिक सिगरेट के मुकाबले ई-सिगरेट कम नुकसानदेह है। ऐसे में सिगरेट पीने वालों के लिए विकल्प को नकार देना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत को धूम्रपान करने वाली अपनी आबादी को दोबारा यह आश्वासन देना होगा कि कम हानि वाले विकल्प भी उपलब्ध हैं। पूरे परिदृश्य को देखते हुए हमें समझना होगा कि समझदारी से भरे विकल्प महत्वपूर्ण हैं।

डीपीआइआइटी जल्द जारी करेगा राष्ट्रीय रिटेल नीति का मसौदा

नई दिल्ली, प्रेट्र : उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) जल्द ही राष्ट्रीय रिटेल नीति का मसौदा जारी करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस नीति का मकसद 6.5 करोड़ छोटे कारोबारियों का विकास करना है और मसौदे के जरिये विभिन्न पक्षों की राय जुटाई जाएगी। इस नीति में रिटेल सेक्टर के विकास को बढ़ावा देने, डिजिटल भुगतान बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधा दूर करने पर मुख्य ध्यान होगा। विभाग ने प्रस्तावित नीति पर विमर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। हम इसका मसौदा तैयार कर रहे हैं।

पहले भी विदेश में सॉवरेन बांड बेचने के मुद्दे पर विचार हुआ था, लेकिन इस पर आगे नहीं बढ़ा गया, क्योंकि इसमें फायदा से अधिक घाटा दिखा। आप विदेशी निवेशकों को यहीं पूंजी लाने दीजिए। इससे हमारे पूंजी बाजार का विकास होगा।

— मोंटेक सिंह अहलूवालिया, पूर्व उपाध्यक्ष, योजना आयोग

स्पष्टीकरण ▶ कई एजेंसियों से मिल जाती है विदेश भ्रमण या महंगी खरीदारी की सूचना

सोशल मीडिया पोस्ट्स नहीं खंगालता टैक्स विभाग : सीबीडीटी चेयरमैन

बड़े लेन-देन की जानकारी जुटाने के लिए विभाग के पास एक डाटा एनालिटिक्स प्रणाली भी है

नई दिल्ली, प्रेट्र : टैक्स विभाग ने इस धारणा को एक गलतफहमी बताया कि अघोषित आय का पता लगाने के लिए वह सोशल मीडिया पोस्ट्स से विदेश भ्रमण तथा महंगी खरीदारी से जुड़ी सूचना इकट्ठा करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पीसी मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा कि टैक्स विभाग को ऐसे कदम उठाने की जरूरत नहीं है। टैक्स विभाग को विभिन्न एजेंसियों से सूचना और आंकड़े हासिल करने की ताकत मिली हुई है। इसके साथ ही बड़े लेन-देन करने वालों के बारे में सूचना हासिल करने के लिए उसके पास एक मजबूत डाटा एनालिटिक्स प्रणाली भी है।

इनकम टैक्स विभाग की नीति बनाने वाली सीबीडीटी के प्रमुख से पूछा गया था कि लोगों की अघोषित आय और खर्च से जुड़े व्यवहार पर सूचना हासिल करने के लिए क्या इनकम टैक्स विभाग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम व अन्य सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट्स की जांच करता है। पिछले कुछ समय से मीडिया की चर्चा में इस तरह की बात कही जाती रही है कि टैक्स अधिकारी सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिये यह पता लगाते हैं कि किस व्यक्ति ने विदेश यात्रा पर बड़ा खर्च किया है या क्या कोई अपनी महंगी खरीदारी को लेकर सोशल मीडिया पर दिखावा करता है। चर्चा के मुताबिक इस तरह से विभाग यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि ऐसे लोग वाजिब टैक्स का भुगतान करें।

पीसी मोदी ने कहा कि यह एक गलतफहमी है। हमें सोशल मीडिया पर जाने की क्या जरूरत है? हमें ऑटोमैटिक तरीके से खुद ही किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा और अन्य वित्तीय लेन-देन की जानकारी मिलती रहती है। सीबीडीटी ने एक अत्याधुनिक डाटा एनालिटिक्स प्रणाली स्थापित की है, जो आंकड़ों का विश्लेषण कर बताता है कि किस जगह पर टैक्स लगाया जाना चाहिए और किन आंकड़ों के मामले में राहत दी जा सकती है। टैक्स विभाग ने इस नई प्रणाली का नाम प्रोजेक्ट इनसाइट रखा है।

मोदी ने कहा कि इस प्रणाली के सहयोग से विभाग अब एसएमएस पर आधारित एक सेवा शुरू करने पर काम कर रहा है। इसके तहत करदाता को उसके द्वारा किए गए 18 प्रकार के ऐसे लेन-देन के बारे में बताया जाएगा, जो एक निश्चित सीमा से ऊपर के होंगे। इसके तहत करदाताओं को सिर्फ सतर्क किया जाएगा कि टैक्स विभाग को इन सब की सूचना है। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय वे इन लेन-देन का भी उल्लेख सुनिश्चित करें और उन पर वाजिब टैक्स का भुगतान भी करें। विभाग ने कुछ निश्चित श्रेणी के करदाताओं के लिए पहले से भरे हुए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म की सुविधा भी शुरू की है। हम प्रक्रिया को जटिलता से मुक्त करना चाहते हैं। विभाग ये लेन-देन की सूचनाएं बैंक, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड कंपनी, सब-रजिस्ट्रार, आदि जैसी एजेंसियों से हासिल करता है।

टैक्स विभाग की प्रणाली बता देती है कि कहां टैक्स लगाना है और कहां नहीं। प्रतीकात्मक

पूर्व सीईओ ने लगाया हेलो टैक्सी के प्रमोटर्स पर घपला करने का आरोप

▶ कहा, प्रमोटर्स ने निवेशकों के 1,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल दूसरे कार्यों में किया

▶ मामले की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी की

नई दिल्ली, एएनआइ : कैब सेवा देने वाली कंपनी हेलो टैक्सी के एक पूर्व सीईओ ने कंपनी के प्रमोटर्स पर वित्तीय धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पूर्व सीईओ सरोज महापात्रा सहित कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि प्रमोटर्स ने निवेशकों के करीब 1,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल दूसरे कार्यों में किया है, जबकि ठगे गए निवेशकों के आक्रोश का शिकार वे हो रहे हैं। गौरतलब है कि एक महीने पहले एक व्यक्ति ने कंपनी, इसके अधिकारियों और प्रमोटर्स के खिलाफ प्राथमिकी (एफआइआर) भी दर्ज कराई थी। महापात्रा ने इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी की है। उन्होंने कहा है कि आरोपित देश से भागने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने घपले के सभी सबूत भी प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सौंपे हैं। महापात्रा ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए प्रमोटर्स को हिरासत में लिए जाने की मांग की है।

हेलो टैक्सी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) का योजना का संचालन करती है। इसमें वह निवेशकों को ऊंचा लाभ देती है। कंपनी के ऊपर बड़े और छोटे निवेशकों की भारी भरकम रकम बकाया है। पूर्व सीईओ महापात्रा ने कहा कि संदिग्ध कंपनियों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कॉरपोरेट स्तर पर हमें एकजुट होकर उनकी निंदा करने और सभी जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू करने की जरूरत है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों को भी ऐसी गतिविधियों पर निगाह रखनी चाहिए।

महापात्रा ने कहा कि मार्च के बाद से मुझे पूरा विश्वास था कि प्रमोटर्स द्वारा करीब 1,000 करोड़ रुपये का वित्तीय घपला किया गया है और मैंने सभी सबूत जुटाए। मुझे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को फंसाया गया है। हमें उनके द्वारा यह विश्वास दिलाया गया कि हम सिर्फ मासिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी हैं और कंपनी द्वारा जुटाई गई राशि से हमारा कोई वास्ता नहीं है। वित्तीय लेन-देन पर कभी हमारा हस्ताक्षर नहीं होता था। प्रासंगिक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ऐसा लगता है कि प्रमोटर्स ने 1,000 करोड़ रुपये का घपला किया है।

इस बारे में हेलो टैक्सी के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश का कोई जवाब नहीं मिला।

प्रमोटर ने किया घपला, निशाना बन रहे अधिकारी। प्रतीकात्मक

अगले दो साल तक आठ फीसद विकास दर के आसार नहीं

▶ वित्त वर्ष 2020-21 में विकास दर 7.3 फीसद व 2021-22 में 7.5 फीसद रहने का अनुमान

▶ वित्त मंत्रालय ने मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में जताई संभावना

इकोनॉमी को पांच लाख करोड़ डॉलर का बनाने का लक्ष्य। प्रतीकात्मक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार ने अगले पांच साल में अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर पांच लाख करोड़ डॉलर (करीब 343 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सालाना औसतन आठ फीसद विकास दर की दरकार होगी, लेकिन अगले दो साल तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के यह आंकड़ा छूने के आसार नहीं हैं। खुद वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि अगले दो वित्त वर्षों में देश की विकास दर सात से 7.5 फीसद तक रहेगी।

वित्त मंत्रालय ने ये अनुमान पांच जुलाई को संसद में पेश किए गए आम बजट 2019-20 के साथ 'मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण' दस्तावेज में व्यक्त किए हैं। इस दस्तावेज में कहा गया है कि प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी पिछले वर्ष के मुकाबले 11 फीसद बढ़कर चालू वित्त वर्ष में 2,11,00,607 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसी तरह प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में 11.6 फीसद और वित्त वर्ष 2021-22 में 11.9 फीसद रहने का अनुमान है। 'मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण' के अनुसार स्थिर मूल्यों पर विकास दर 2020-21 में 7.3 फीसद और 2021-22 में 7.5 फीसद रहने का अनुमान है।

हाल के वर्षों में विकास दर

वित्त वर्ष	फीसद
2015-16	8.0
2016-17	8.2
2017-18	7.2
2018-19	6.8
आगामी अनुमान	
2019-20	7.0
2020-21	7.3
2021-22	7.5

गौरतलब है कि 'आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19' में कहा गया है कि 2024-25 तक भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर (375 लाख करोड़ रुपये) की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सालाना 8 फीसद विकास दर की दरकार होगी। चालू वित्त वर्ष में देश की विकास दर 7 फीसद रहने का अनुमान है। ऐसी स्थिति अगर पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करना है तो आने वाले वर्षों में विकास दर कम से कम आठ फीसद बनाए रखनी होगी। हालांकि अर्थव्यवस्था अभी जिस दौर से गुजर रही है, उसमें यह लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। पिछले वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर महज 6.8 फीसद थी, जो विगत पांच वर्षों का निचला स्तर है।

इंडिगो में अधिक जोखिम लेने से बचते रहे गंगवाल : आइजीई

▶ भाटिया समूह ने इंडिगो को खड़ा करने के लिए 1,100 करोड़ रुपये का जोखिम लेने का दावा किया

▶ कहा, गंगवाल ने अपने वित्तीय जोखिम को 15 करोड़ रुपये से ऊपर नहीं जाने दिया

नई दिल्ली, आइएएनएस : विमानन कंपनी इंडिगो के प्रमोटर इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज (आइजीई) ने रविवार को कहा कि राकेश गंगवाल ने हमेशा विमानन कंपनी इंडिगो में अपने वित्तीय जोखिम को सीमित रखा। यही नहीं, उन्होंने कठिन समय में कारोबार को बेच देने की भी कोशिश की। राकेश गंगवाल द्वारा कंपनी पर कॉरपोरेट गवर्नेंस की बदहाली का लगाए गए आरोप के जवाब में आइजीई ने पिछले एक सप्ताह में तीन बयान जारी किए हैं। आइजीई राहुल भाटिया की कंपनी है।

आइजीई ने रविवार को जारी बयान में कहा कि राहुल भाटिया उद्योग के पेशेवर गंगवाल को लंबे समय से जानते थे। इसलिए उन्होंने गंगवाल को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया था। दोनों पक्षों में यह सहमति बनी थी कि आइजीई समूह और गंगवाल लगभग समान हिस्सेदारी रहेगी। गंगवाल अपने वित्तीय जोखिम को 15 करोड़ रुपये से अधिक नहीं रखना चाहते थे। आइजीई समूह और शेयर पूंजी का निवेश करता, लेकिन चूंकि गंगवाल और अधिक निवेश नहीं करना चाहते थे, इसलिए इंडिगो की चुकता शेयर पूंजी को 30 करोड़ रुपये रखा गया। यह न्यूनतम नियामकीय सीमा थी।

आइजीई ने कहा कि राकेश गंगवाल समूह (आरजी समूह) ने आइजीई से 1,49,950 शेयर खरीदे, जो मई 2016 में करीब आधी हिस्सेदारी थी। शेयरधारक समझौते में आरजी समूह को निवेशक का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2005 में जब विमान की खरीद के लिए एयरबस से बात चल रही थी, तब एयरबस ने आइजीई और गंगवाल दोनों से इंडिगो को सहयोग देने के लिए ज्वाइंट अंडरटेकिंग मांगी। इस पर आइजीई और गंगवाल ने इंडिगो में कम से कम पांच करोड़ डॉलर (उस समय के मुताबिक करीब 200 करोड़ रुपये) निवेश करने का वादा किया। इसके बाद दोनों ने आखिरी विमान की आपूर्ति तक इस निवेश को बनाए रखने का भी वादा किया। गंगवाल चूंकि और अधिक वित्तीय जोखिम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए आइजीई ने अकेले इंडिगो में 110 करोड़ रुपये का और निवेश करने की जिम्मेदारी ली, ताकि पहले के 99 करोड़ रुपये के निवेश को मिलाकर एयरबस की शर्त पूरी की जा सके।

आइजीई ने कहा कि कठिन समय में इंडिगो को बचाने की जिम्मेदारी आइजीई समूह पर छोड़ दी गई। गंगवाल ने कठिन समय में इंडिगो से बाहर निकलने या उसे बेच डालने की बात भी उठाई। बैंक गारंटी और निजी कर्ज के जरिये आइजीई, कपिल भाटिया और राहुल भाटिया का वित्तीय एक्सपोजर 1,100 करोड़ रुपये से अधिक था। उस वक्त गंगवाल 15 करोड़ रुपये से भी कम के सुरक्षित दायरे में थे। आइजीई समूह और गंगवाल को जोखिम अनुपात 80:एक का था। कपिल भाटिया और राहुल भाटिया की व्यक्तिगत गारंटी वित्त वर्ष 2011-12 के आखिर तक प्रभावी रही। उस समय तक इंडिगो का बैलेंस शीट मजबूत हो चुका था।

गंगवाल पर कठिन समय में इंडिगो को बेचने का भी आरोप। फाइल फोटो

सेबी ने जांच तेज की

नई दिल्ली : पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने विमानन कंपनी इंडिगो में कॉरपोरेट गवर्नेंस की खामी के आरोप पर गहराई से जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने कहा कि सेबी के नियमों के कई उल्लंघन के संकेत मिले हैं।

भाटिया कंपनी पर नियंत्रण छोड़ने के मूड में नहीं

नई दिल्ली : इंडिगो के प्रमोटर राहुल भाटिया कंपनी में अपनी नियंत्रक हिस्सेदार कम करने के मूड में नहीं हैं। नियंत्रक हिस्सेदारी के बल पर ही वह कंपनी का चेयरमैन, सीईओ और अन्य प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि भाटिया सरकार की ओर से कंपनी पर हर प्रकार की जांच के लिए भी तैयार हैं। आधिकारिक सूत्र ने कहा कि संबद्ध पक्ष लेन-देन और कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे के बहाने एक प्रमोटर गवर्नेंस की संरचना बदलना चाहता है, लेकिन राहुल भाटिया ऐसा होने देने के लिए तैयार नहीं हैं।

विदेश में सॉवरेन बांड न बेचने की सलाह

मुंबई, प्रेट्र : योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने सरकार को सलाह दी है कि वह विदेशी डेट बाजार से फंड न जुटाए। उन्होंने कहा कि पहले भी सॉवरेन बांड बेचने के मुद्दे पर विचार हुआ था, लेकिन नुकसान को देख इस पर आगे नहीं बढ़ा गया।

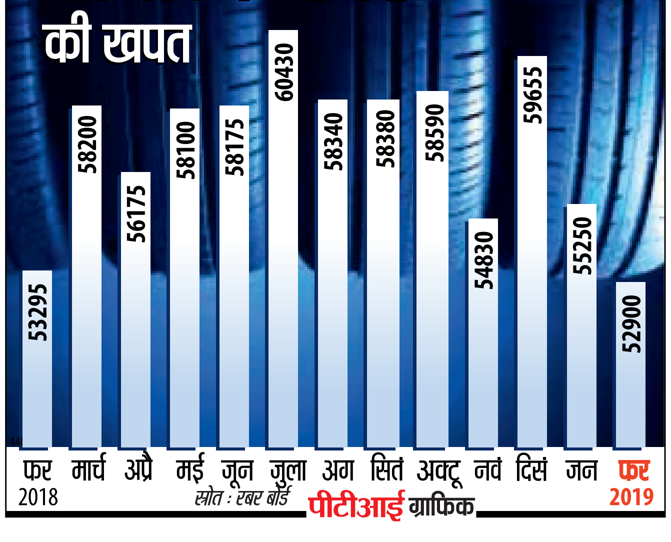

एक हजार करोड़ की सरसों खरीद में नैफेड व हरियाणा की हैफेड में ठनी

▶ ढाई लाख टन की खरीद में आढ़तियों को शामिल करने पर विवाद

▶ बैंक ऋण से किसानों को हो चुका है पहले ही भुगतान

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

सरसों खरीद के तौर तरीके को लेकर नैफेड और हैफेड के बीच जबर्दस्त ठन गई है। केंद्रीय नोडल एजेंसी नैफेड की आपत्तियों के चलते हरियाणा की सहकारी एजेंसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विवाद को निपटाने का दायित्व केंद्रीय रजिस्ट्रार को सौंप दिया गया है। एक हजार करोड़ रुपये की लागत से खरीदी गई सरसों पर लगातार बैंक का ब्याज बढ़ रहा है, जो सहकारी एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।

बीते रबी खरीद सीजन में हरियाणा की सहकारी खरीद एजेंसी हैफेड ने ढाई लाख टन सरसों की खरीद की है। सरसों की इस खरीद में पहली बार सहकारी एजेंसी ने आढ़तियों का सहयोग लिया है, जिन्हें हैंडलिंग एजेंट के तौर पर शामिल किया गया है। सामान्य तौर पर सहकारी एजेंसियां कृषि उपज की सीधी खरीद किसानों से करती हैं। इनमें आढ़तियों की कोई भूमिका नहीं होती रही है। इसी आधार पर नैफेड ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा किसी और तरह के कमीशन को मंजूरी देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। जबकि हैफेड ने 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आढ़तियों को हैंडलिंग चार्ज का भुगतान किया है।

हरियाणा के कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। हालांकि तोमर ने इस मामले को नियमानुसार फैसला लेने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार को सौंप दिया है। हैफेड के अफसरों का कहना है कि सहकारी एजेंसियों की खरीद में आढ़तियों को शामिल करने की परंपरा कभी नहीं रही है। हैफेड ने इस तरह नियमों की अवहेलना की है। इसलिए हैंडलिंग चार्ज के नाम पर दी जाने वाली 10 करोड़ रुपये की धनराशि को नैफेड के लिए मंजूरी देना आसान नहीं होगा।

बैंकों का बढ़ रहा है ब्याज। प्रतीकात्मक

अनुमान

इस सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो और एचडीएफसी बैंक जारी करेंगे तिमाही नतीजे, सोमवार को जारी होने वाले थोक महंगाई के आंकड़ों पर भी रहेगा निवेशकों का ध्यान

तिमाही नतीजों व आर्थिक आंकड़ों से शेयर बाजार को मिलेगी दिशा

नई दिल्ली, प्रेट्र : शेयर बाजारों की दिशा इस सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआइएल), विप्रो और एचडीएफसी बैंक जैसी दिग्गज कंपनियों के तिमाही नतीजों और आर्थिक आंकड़ों से तय होगी। विश्लेषकों के मुताबिक इस दौरान निवेशकों की नजर व्यापार से जुड़े घटनाक्रम, रुपये की चाल और तेल कीमत पर भी टिकी रहेगी।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि इस सप्ताह बाजार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए कंपनियों के नतीजों पर प्रतिक्रिया करेगा। हालांकि तिमाही नतीजों के उत्साहवर्धक रहने की उम्मीद नहीं है। सोमवार को इंफोसिस के शेयरों में कुछ गतिविधि दिख सकती है। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद तिमाही नतीजा जारी किया था।

एपिक रिसर्च के सीईओ मुस्तफा नदीम ने कहा कि थोक महंगाई जैसे महत्वपूर्ण आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी। विदेशी बाजारों के रुझान और भारत-अमेरिका व्यापार विवाद से जुड़े घटनाक्रम भी बाजार को प्रभावित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच उभरे व्यापारिक तनाव के दूर होने की प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं और इस दौरान बाजार पर भी इसका असर बना रहेगा।

शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जारी हुए खुदरा महंगाई और औद्योगिक विकास के आंकड़े पर भी बाजार में प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। औद्योगिक विकास दर मई में गिरकर 3.1 फीसद रह गई। इस गिरावट में मुख्य योगदान खनन और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की सुस्ती का रहा। खुदरा महंगाई दर जून में लगातार छठे महीने बढ़कर 3.18 फीसद पर पहुंच गई। अनाज, दलहन, मांस और मछली की कीमत में बढ़ोतरी ने खुदरा महंगाई बढ़ने में प्रमुख भूमिका निभाई।

कैपिटलएम के रिसर्च प्रमुख रोमेश तिवारी ने कहा कि सोमवार को थोक महंगाई के आंकड़े जारी होंगे। मंगलवार को अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल का अहम बयान आने वाला है। सैमको सिक्युरिटीज एंड स्टॉकनोट के संस्थापक और सीईओ जिमीत मोदी ने कहा कि इस सप्ताह एचडीएफसी एएमसी, फेडरल बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसी दिग्गज कंपनियों के तिमाही नतीजे आने वाले हैं। विप्रो और यस बैंक भी इस सप्ताह अपने नतीजे जारी करेंगे। पिछले सप्ताह के कारोबार में बीएसई के सेंसेक्स में कुल 777.16 अंकों की गिरावट दर्ज की गई।

व्यापार से जुड़े घटनाक्रम पर भी रहेगा ध्यान। फाइल फोटो

एफपीआइ ने 3,551 करोड़ रुपये लगाए

नई दिल्ली : बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार से विदेशी पूंजी के तेजी से बाहर निकलने के बाद भी जुलाई में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआइ) भारतीय पूंजी बाजार (शेयर और डेट बाजार) में खरीदार बने रहे। डिपॉजिटरी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक से 12 जुलाई तक एफपीआइ ने शेयर बाजार से कुल 4,953.77 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की। इस दौरान डेट बाजार में हालांकि उन्होंने कुल 8,504.78 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया। इस तरह से भारतीय पूंजी बाजार में जुलाई में अब तक एफपीआइ ने 3,551.01 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया।

नौ ब्लूचिप कंपनियों का एमकैप 88,609 करोड़ रुपये गिरा

नई दिल्ली : देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से नौ का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) गत सप्ताह कुल 88,609.87 करोड़ रुपये घट गया। शीर्ष 10 में सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआइएल) का एमकैप बढ़ा। आरआइएल का एमकैप 11,415.21 करोड़ रुपये बढ़ा। दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक का एमकैप सर्वाधिक 22,395.4 करोड़ रुपये घटा। टीसीएस का एमकैप 20,150.31 करोड़ रुपये, हिंदुस्तान यूनीलिवर (एचयूएल) का 16,907.1 करोड़ रुपये, कोटक महिंद्रा बैंक का 6,367.64 करोड़ रुपये, एसबीआइ का 6,291.85 करोड़ रुपये, आइसीआइसीआइ बैंक का 5,925.68 करोड़ रुपये, आइटीसी का 5,270.27 करोड़ रुपये, एचडीएफसी का 3,795.66 करोड़ रुपये और इंफोसिस का एमकैप 1,505.96 करोड़ रुपये घटा। एमकैप के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी कंपनी रही।

1200 सदस्यों की चुनाव समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा चलाया जाता है हांगकांग का शासन, लेकिन लोग चाहते हैं कि ये प्रतिनिधि जनता के जरिए चुने जाने चाहिए। 2007 में यह निर्णय लिया गया कि 2017 में होने वाले चुनावों में लोगों को मताधिकार का हक मिलेगा, लेकिन 2014 की शुरुआत में इसके कानूनों में जरूरी बदलाव शुरू हो गए।

न्यूज गैलरी

7.3 तीव्रता के भूकंप के झटकों से दहला इंडोनेशिया

जकार्ता : भूकंप के तेज झटके से रविवार को इंडोनेशिया दहल उठा। 7.3 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र पूर्वी इंडोनेशिया के मालुकु द्वीप में था। भूकंप से हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने सुनामी आने की भी चेतावनी नहीं दी है। पिछले साल 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद आई सुनामी से यहां भारी तबाही हुई थी। (एएफपी)

अफगानिस्तान में रेडिया पत्रकार की हत्या

काबुल : अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिया प्रांत में शनिवार देर रात रेडियो पत्रकार नादिर शाह की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, हत्या के पीछे की मंशा अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। हत्या में किसी आतंकी संगठन का भी हाथ हो सकता है। पक्तिया में तालिबान के समर्थन वाले आतंकी समूह हक्कानी नेटवर्क का दबदबा है। (एपी)

चीन में एक और कनाडाई हिरासत में

मॉन्ट्रियल : चीन में कनाडा के एक और नागरिक को हिरासत में लिया गया है। इस कदम से दोनों देशों में तनातनी बढ़ सकती है। इस साल की शुरुआत में अमेरिका के वारंट पर कनाडा में चीनी टेक फर्म हुआवे की सीएफओ मेंग वांगजु को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके जवाब में चीन ने भी दो कनाडाई नागरिकों को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए थे। (एएफपी)

हांगकांग के प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप से लगाई मदद की गुहार

लगातार दूसरे दिन चीन की सीमा से सटे शहर में किया बड़ा प्रदर्शन, कहा–कराएं आजाद और बचाएं संविधान

हांगकांग, रायटर : हांगकांग में प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने लगातार दूसरे दिन चीन की सीमा से सटे शहर शा टिन में बड़ी रैली निकाली। इसमें युवकों और बुजुर्गों समेत हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। रैली के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी लहराए गए। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर लहराकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हांगकांग को आजाद कराने और संविधान बचाने की गुहार भी लगाई।

वर्ष 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग इसी शर्त पर सौंपा था कि 'एक देश, दो प्रणाली' के तहत इस क्षेत्र की स्वायत्तता बरकरार रहेगी। प्रदर्शनकारी प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून को हांगकांग की स्वायत्तता पर खतरा मान रहे हैं। इस कानून में संदिग्धों और आरोपितों को मुकदमे के लिए चीन में प्रत्यर्पित करने का प्रावधान है। जून के मध्य में लाखों लोग इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। इसके दबाव में हांगकांग की नेता कैरी लाम ने संबंधित बिल निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद विरोध नहीं थमा। प्रदर्शनकारी बिल को वापस लेने और लाम के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। हाल में लाम ने कानून को निरस्त बता दिया था। लेकिन प्रदर्शनकारी लाम को झूठा बताते हुए कानून को आधिकारिक तौर पर वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

हांगकांग में लाखों लोग विवादास्पद प्रत्यर्पण कानून को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कवर कर रहे पत्रकारों से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया और कई फोटोग्राफरों के कैमरे भी छीन लिए गए। रविवार को पुलिस और गवर्नमेंट मुख्यालय के सामने मीडियाकर्मियों ने इसके विरोध में शांति मार्च निकाला। उनकी मांग है कि पुलिस, मीडियाकर्मियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दे और उनके कामकाज में किसी भी तरह का दखल नहीं दे। एपी

पत्रकारों ने भी किया विरोध प्रदर्शन : रविवार को एक हजार से ज्यादा पत्रकारों और उनके समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ शांतिपूर्ण रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने प्रत्यर्पण कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों पर पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाई रोकने की मांग की।

चीन के व्यापारियों खिलाफ रैली निकाल रहे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़े : **शनिवार को** हांगकांग में चीन के व्यापारियों के खिलाफ रैली निकाल रहे प्रदर्शनकारी चीन के साथ लगती एक कस्बे की सीमा पर पुलिस से भिड़ गए। बता दें कि हांगकांग में पिछले एक महीने से प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस के साथ लोगों की झड़पें भी हुई हैं।

यह प्रदर्शन एक कानून के कारण किया जा रहा है, जिसके जरिये लोगों को मुकदमे का सामना करने के लिए चीन भेजे जाने का प्रावधान है। हांगकांग के क्षेत्रीय शहर शेंग शुई में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन यह जल्द ही हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने जब छाते और अपनी टोपियां पुलिस की तरफ फेंकी तो सुरक्षा बलों ने लाठियां लहराईं और मिर्ची स्प्रे दागे। हालांकि बाद में पुलिस द्वारा जल्द इलाके को खाली करने की चेतावनी देने के बाद प्रदर्शनकारी चले गए। दरअसल, आलोचक इस बिल को हांगकांग के शासन के लिए खतरे के रूप में देखते हैं।

ताइवान, हांगकांग और मकाऊ को चीन ने अपनी वेबसाइट से हटाया

हांगकांग, आइएएनएस : चीन सरकार के 'सोशल क्रेडिट सिस्टम' वेबसाइट से हांगकांग, मकाऊ और ताइवान को हटा दिया गया है। मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। 2014 में घोषित की गई इस प्रणाली का उद्देश्य इस विचार को मजबूत करना है कि 'भरोसा रखना शानदार और विश्वास को तोड़ना घृणित है।'

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार देर रात अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक संदेश में, संवैधानिक और मुख्यभूमि मामलों के सचिव पैट्रिक निप तक-कुएन ने कहा कि हांगकांग, मकाऊ और ताइवान को राष्ट्रीय सार्वजनिक विश्वसनीयता सूचना द्वारा संचालित 'क्रेडिट चाइना' वेबसाइट से हटा दिया गया था। साइट व्यवस्थापक और शहर की सरकार के बीच बातचीत के बाद ऐसा किया गया है। नौ जुलाई को, ताइवान के कुछ समाचार पत्रों और हांगकांग के ऑनलाइन प्लेटफार्मों ने दावा किया कि ताइवान में सामाजिक क्रेडिट प्रणाली लागू की जाएगी। निप ने उसी दिन इस दावे का खंडन किया था। हांगकांग सरकार के एक सूत्र ने कहा, 'हांगकांग, मकाऊ और ताइवान केनाम को वेबसाइट से हटाने का मकसद इस भ्रांति को दूर करना है कि सोशल क्रेडिट सिस्टम को हांगकांग में लागू किया जाएगा।' सूत्रों ने कहा कि पूर्णता के लिए वेबसाइट में पहले चीन के मुख्य प्रांतों के साथ ही हांगकांग, मकाऊ और ताइवान के नाम को शामिल किया गया था, हालांकि कोई लिंक एम्बेडेड नहीं थे। संभावित कार्यान्वयन को अफवाहें शायद इसलिए पैदा हुईं क्योंकि वृहद खाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए 2018 से 2020 तक की तीन साल की कार्ययोजना में इस सिस्टम को शामिल किया गया था। इसके तहत चीन सरकार की हांगकांग, मकाऊ और गुआंग्डोंग प्रांत के नौ शहरों को एकीकृत आर्थिक क्षेत्र में बदलने की योजना है।

'सोशल क्रेडिट सिस्टम' का उद्देश्य सरकार और समुदायों के बीच भरोसे का विकास करना है

सरकार की योजना अगले वर्ष तक सभी नागरिकों को उनके 'सोशल क्रेडिट' के आधार पर रैंक करने की है। इस, सिस्टम का मकसद एक समाजवादी सर्वसत्तावादी नेतृत्व में पूरा भरोसा पैदा करने के अलावा बाजार के खिलाड़ियों और समुदायों के बीच नैतिकता और भरोसे का विकास करना भी है। इस सिस्टम में यह व्यवस्था है कि अगर कोई शख्स हॉर्न बजाता है, कर्ज या कर नहीं चुकाता, या फिर ड्राइविंग के तौर-तरीकों पर अमल नहीं करता, धोखाधड़ी करता है, तो उसे 'गैरभरोसेमंद' व्यवहार के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। दंड के रूप में उस पर सार्वजनिक परिवहन टिकट खरीदने या होटल में कमरा बुक करने पर पाबंदी लगाई जा सकती है।

नवंबर में भी रद रहेंगी अमेरिकन एयरलाइंस की 115 उड़ानें

वाशिंगटन, रायटर: बोइंग 737 मैक्स विमानों के परिचालन से बाहर होने का असर अमेरिकन एयरलाइंस पर भी दिखाई दे रहा है। विमानन कंपनी ने चौथी बार अपनी उड़ानों के निरस्तीकरण को विस्तार देते हुए रविवार को बताया कि नवंबर के शुरुआती महीने में 115 फ्लाइट प्रतिदिन रद रहेंगी। बता दें कि अमेरिकन एयरलाइंस दुनिया की सबसे बड़ी विमानन कंपनी और यह विश्व में मैक्स विमानों का प्रयोग करने वाली दूसरे सबसे बड़ी कंपनी है।

दरअसल, दो भीषण दुर्घटनाओं के बाद भी मैक्स विमानों को उड़ान के लिए ठीक बताने वाले अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन ने पिछले महीने बोइंग की एक नई कमी को उजागर किया था। विमान निर्माता कंपनी ने इस कमी को सितंबर तक ठीक करने की बात कही थी। माना जा रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने यह फैसला किया है। रविवार को कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक अमेरिकन एयरलाइंस को भरोसा है कि बोइंग 737 मैक्स विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही विमानों को उड़ान के लिए दोबारा सर्टिफिकेट लेने का काम इस साल पूरा हो जाएगा।

नेपाल में बाढ़ का कहर जारी, अब तक 50 लोगों की मौत, 33 लापता

भारी बारिश के कारण नेपाल के कई इलाकों में पानी भर गया है। रायटर

काठमांडू, एएनआइ : नेपाल में मूसलधार बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल पुलिस के अनुसार, 33 लोग लापता हैं जिनकी खोज जारी है। दो हजार लोगों को बचाया गया है।

गुरुवार से जारी बारिश के कारण पूर्वी और दक्षिणी नेपाल के कई इलाके भूस्खलन और बाढ़ के खतरे का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अभी दो-तीन दिनों तक बारिश जारी रहने की आशंका जताई है। बाढ़ के कारण कई मुख्य राज्यमार्गों पर यातायात ठप है। देश के ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं। ढाई हजार से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। करीब 1,500 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। र विस्थापित भी हुए हैं। बचावकार्यों के लिए प्रभावित इलाकों में 27 हजार से ज्यादा पुलिस और सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं।

अमेरिका और रूस ने तालिबान से किया संघर्ष विराम का आग्रह

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से तालिबान से तुरंत संघर्ष विराम के लिए राजी होने का आग्रह किया है। चारों देशों ने 18 वर्षों से देश में जारी हिंसा को खत्म करने के लिए तालिबान से अफगानिस्तान सरकार के साथ सीधा समझौता शुरू करने के लिए कहा है।

बीजिंग में 10-11 जुलाई को अफगान शांति प्रक्रिया पर बैठक समाप्त होने के बाद शुक्रवार को संयुक्त बयान जारी किया गया। सभी देशों ने दोहराया है कि समझौता अफगान-नेतृत्व में और अफगान-स्वामित्व में हो। इसके साथ ही यथाशीघ्र शांति प्रारूप पेश करने को कहा है। बयान में कहा गया है, 'इस प्रारूप में सुरक्षा स्थिति का तर्कसंगत और जवाबदेह हस्तांतरण की गारंटी होनी चाहिए। सभी अफगानों को स्वीकार योग्य भावी समग्र राजनीतिक व्यवस्था पर एक समझौते का ब्योरा होना चाहिए।' अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान ने संबंधित पक्षों से शांति का अवसर हाथ में लेने और तुरंत ही तालिबान, अफगानिस्तान सरकार और अन्य अफगानों के बीच इंट्रा-अफगान समझौता करने को कहा है।

बांग्लादेश के पूर्व सैन्य तानाशाह हुसैन मुहम्मद इरशाद का निधन

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश के पूर्व सैन्य तानाशाह हुसैन मुहम्मद इरशाद का रविवार सुबह यहां निधन हो गया। 91 वर्षीय इरशाद लंबे समय से फेफड़े और किडनी संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। 22 जून को उनकी हालात बिगड़ गई थी जिसके बाद उन्हें यहां सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जातीय पार्टी के प्रमुख और संसद में विपक्ष के नेता इरशाद के निधन पर राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना और संसद की अध्यक्ष डॉ शिरीन शर्मिन ने शोक व्यक्त किया है।

इरशाद का जन्म 1930 में भारत के मौजूदा बंगाल प्रांत के कूचबिहार जिले में हुआ था। भारत विभाजन के एक साल बाद 1948 में उनका परिवार तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बांग्लादेश) चला गया था। इरशाद 1952 में पाकिस्तान की सेना में भर्ती हुए थे। नेता के साथ ही वह बतौर कवि भी खासे मशहूर थे। 1982 में रक्तहीन तख्तापलट के जरिये देश की सत्ता पर काबिज होने वाले इरशाद आठ साल तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क घोषित करने का विवादित निर्णय लिया था। 1990 में हुए लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के बाद उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। इसके बाद भ्रष्टाचार संबंधी कई आरोपों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कई साल जेल में रहने के बाद भी वह बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा नाम थे। वह पांच बार सांसद चुने गए। उन्होंने एक बार जेल में रहते हुए भी चुनाव जीता था। उनकी जातीय पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और कई बार गठबंधन सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभा चुकी है।

बांग्लादेश के पूर्व सैन्य तानाशाह हुसैन मुहम्मद इरशाद की फाइल फोटो। एपी

मुसलमानों पर हमले की ब्रिटिश सांसद ने की आलोचना

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन की शैडो कैबिनेट के एक मंत्री ने मुसलमानों पर हो रहे कथित हिंसक हमलों के लिए भारत की आलोचना करते हुए कहा है कि ब्रिटिश सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और 'बेहद चिंताजनक स्थिति' के विषय में कार्रवाई करनी चाहिए। लेसिस्टर साऊथ से लेबर पार्टी के सांसद जॉनाथन ऐशवर्थ ने पिछले सप्ताह विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री पद के दावेदार जेरेमी हंट को लिखे पत्र में कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में रहने वाले कई लोगों ने चिंता जताई कि भारत सरकार इस मुद्दे पर पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है।

ऐशवर्थ ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में मुसलमानों ने भारत में मुस्लिम समुदाय के साथ हो रही हिंसा के विषय पर मुझसे संपर्क किया है। हंट से इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेने और इस पर कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए शैडो कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री ऐशवर्थ ने कहा कि भारत में हालात काफी चिंताजनक हैं, वहां से धार्मिक रूप से प्रेरित हत्याओं, मारपीट, दंगे, भेदभाव, तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं और वहां धर्म का पालन करने के अधिकार से वंचित करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

चीन में होगा दलाई लामा के उत्तराधिकारी का फैसला

बीजिंग, प्रेट्र : दलाई लामा के उत्तराधिकारी का फैसला चीन में होगा। इस मामले में भारत का किसी तरह का हस्तक्षेप दोनों देशों के रिश्तों पर असर डालने वाला होगा। बौद्ध धर्मगुरु को लेकर यह बात चीन के शीर्ष अधिकारियों ने कही है।

दोनों देशों के बीच के इस संवेदनशील मसले पर चीन के किसी बड़े अधिकारी ने पहली बार अपनी जुबान खोली है। तिब्बत के उप मंत्री स्तर के अधिकारी वांग नेंग शेंग ने कहा है कि दलाई लामा के अवतार को चीन की सरकार स्वीकृति आवश्यक होगी। अवतार का चुनाव भी चीन के भीतर से ही होगा। यह 200 साल पुरानी ऐतिहासिक परंपरा है। दलाई लामा का पुनर्जन्म एक ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक मसला है। वर्तमान दलाई लामा भी चीन की स्वीकृति से बने थे और उनके उत्तराधिकारी के लिए भी चीन की मान्यता आवश्यक होगी। वांग ने ल्हासा की यात्रा पर गए भारतीय पत्रकारों से यह बात कही है। वांग तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के चीन द्वारा नियुक्त महानिदेशक हैं।

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 1959 से निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे 14 वें दलाई लामा अब 84 साल के हो गए हैं। हाल के वर्षों में उनके स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आई है। इसके चलते उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का उत्तराधिकारी हमेशा उनके गुणों के आधार पर चुना जाता है। धर्मगुरु के खास गुण किसी खास बच्चे में मिलने पर धार्मिक विद्वानों की समिति नए दलाई लामा के बारे में निर्णय लेती है। वांग ने कहा, दलाई लामा के पुनर्जन्म के विषय में फैसला कोई एक व्यक्ति या विदेश में रहने वाला कुछ लोगों का समूह नहीं कर सकता। यह कार्य प्रक्रिया के तहत और परंपरा के अनुसार पूरा किया जाएगा। वांग के सुर में सुर मिलाते हुए बीजिंग स्थित तिब्बत मामलों के शोध संस्थान के निदेशक झा लुओ ने कहा है कि स्थापित प्रक्रिया में बदलाव की कोई भी भारतीय कोशिश दोनों देशों के संबंधों पर असर डालेगी।

बौद्ध धर्मगुरु के सवाल पर चीन ने दिखाई हठधर्मिता, भारत ने डाली बाधा तो द्विपक्षीय रिश्तों पर होगा असर

दलाई लामा। फाइल

महिला भी हो सकती है दलाई लामा

बीते दिनों दलाई लामा में मुम्बई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भविष्य में कोई महिला भी दलाई लामा हो सकती है। बौद्ध धर्म बहुत उदार है और महिला व पुरुष दोनों के लिए इसमें समान अधिकार हैं, ऐसे में हो सकता है कि महिला दलाई लामा भविष्य में हो। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म ने दोनों लिंगों को समान अधिकार दिए हैं और तिब्बत तथा भारत में महिलाएं भी पंथ प्रमुख रह चुकी हैं। दलाई लामा के इस बयान के बाद एक बार फिर उनके अगले अवतार को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। कुछ साल पहले चीन ने खुद अगला दलाई लामा तय करने का दावा किया था, इसके बाद दलाई लामा ने कहा था कि उनका अगला अवतार होगा या नहीं इस बारे वह 90 साल की आयु में तय करेंगे।

मौत से पहले देते हैं खास संकेत

हर दलाईलामा अपनी मौत से पहले कुछ संकेत वरिष्ठ लामाओं को देकर जाते हैं, जिससे उनके अगले अवतार की पहचान आसानी से की जा सके। मौजूदा समय में यह परंपरा 14वें दलाई लामा तक पहुंची है। मौजूदा दलाई लामा ने इस बारे पहले भी स्पष्ट किया है कि तिब्बती बौद्ध परंपराओं के उच्च लामाओं, तिब्बती समेत तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करने वाले संबंधित लोगों से विचार विमर्श के बाद ही वह निर्णय लेंगे कि दलाई लामा की परंपरा को जारी रखना चाहिए या नहीं। दलाई लामा ने कुछ साल यह भी कहा था कि इस विषय में वह स्पष्ट लिखित निर्देश छोड़कर जाएंगे।

रोचक है 14वें दलाई लामा की पहचान

मौजूदा दलाईलामा का असली नाम तेजिंन ग्यात्सो है। तेजिंन ग्यात्सो बनने से पूर्व यह नाम था, ल्हामो थोंडुंप। इसका तिब्बती भाषा में अर्थ हुआ मनोकामना करने वाला। 6 जुलाई 1935 को उत्तरी तिब्बत में आमदो के एक छोटे से गांव तकछेर में एक किसान परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उस समय उस बच्चे के व्यवहार को देखते हुए उन माता पिता ने उस बच्चे को ल्हामो थोंडुंप का नाम दिया। दो वर्ष की आयु में ल्हामो थोंडुंप की पहचान तिब्बत के वरिष्ठ लामाओं ने तेरहवें दलाई लामा थुबतेन ग्यात्सो के अवतार के रूप में की। थुबतेन ग्यात्सो ने जो संकेत अपनी मौत से पहले दिए थे। उन संकेतों से ही 14वें दलाईलामा की पहचान हुई थी।

अंधेरे में डूबा न्यूयॉर्क

न्यूयॉर्क में शनिवार रात को अचानक बिजली गुल हो जाने से पूरा शहर अंधेरे के आगोश में चला गया। मिडटाउन मैनहट्टन और अपर वेस्ट साइड के करीब 50,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड्स, मेट्रो सबस्टेशन, आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी अंधेरा छा गया था। बिजली की आपूर्ति करने वाली कॉन एडिशन नामक कंपनी के अनुसार बिजली गुल होने से दक्षिण की 40 वीं स्ट्रीट से लेकर उत्तर में 72 वीं स्ट्रीट तक और फिफ्थ एवेन्यू के हडसन नदी तक फैले क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने टाइम्स स्क्वायर होटल की लॉबी में रात गुजारी। (इनसेट एएफपी) रायटर

शाहबाज शरीफ पर करोड़ों रुपये के गबन का आरोप

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान में विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएलएन) के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ ने ब्रिटेन से मिले अनुदान में से करोड़ों रुपये गबन किए हैं। यह दावा ब्रिटिश अखबार द मेल ने किया है। शाहबाज पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। पीएमएलएन ने इस खबर को आधारहीन बताया है। कहा है- यह प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से उपलब्ध कराया गया झूठ का एक और पुलिंदा है।

अखबार के अनुसार शाहबाज ने यह धनराशि 2005 से 2012 के बीच गबन की। यह धनराशि ब्रिटेन के विश्व विकास विभाग की ओर से पाक को कई विकास कार्यों के लिए दी गई थी। पीएमएलएन की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने अखबार में छपी खबर को झूठों से भरा हुआ बताया है। कहा है कि यह आधारहीन खबर इमरान खान के दिमाग की उपज है, जिसके लिए उन्होंने झूठी जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। इस तरह से चरित्र हनन के लिए पार्टी अखबार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।

ब्लैकमेल कर न्यायपालिका पर दबाव डालता है पाक माफिया : इमरान

इस्लामाबाद, आइएएनएस : पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश के मनी लांड्रिंग संदिग्धों की तुलना सिसिलियन माफिया से करते हुए कहा कि वे भी विदेश में जमा अपनी गैरकानूनी दौलत को बचाने के लिए सरकारी संस्थाओं और न्यायपालिका पर दबाव डालते हैं। इसके लिए वे रिश्वत, धमकी और ब्लैकमेल जैसी तरकीबों का इस्तेमाल करते हैं।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिये उपरोक्त टिप्पणी की। इसके साथ ही उन्होंने चार साल पुराने एक लेख को टैग भी किया जो पूर्व इतालवी राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो की 1990 की बमबारी से संबंधित मुकदमे में गवाही से संबंधित है। बताते हैं कि नेपोलिटानो ने अपनी गवाही में कहा था कि यह बमबारी पूरी व्यवस्था को अस्थिर करने के उद्देश्य से की गई थी।

इस बमबारी का कथित रूप से सीधा संबंध वरिष्ठ इतालवी मंत्रियों से था जो सिसिलियन माफिया के साथ जेल की कम सजा और जेल में बेहतर सुविधाओं बदले उनसे हिंसा खत्म करने के लिए वार्ता कर रहे थे। इमरान खान ने अपने देश के मनी लांड्रिंग संदिग्धों की तुलना इसी सिसिलियन माफिया से की है। हालांकि इमरान ने अपने ट्वीट में किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब एक ही दिन पहले जवाबदेही न्यायाधीश अरशद मलिक ने हलफनामे के जरिये दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पुत्र हुसैन नवाज ने उन्हें नकद 50 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का प्रस्ताव दिया था।

पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। फाइल

भारत–पाक के मतभेद दूर करने की पहल

इस्लामाबाद, प्रेट्र : सामाजिक गतिविधियों से जुड़े भारत और पाकिस्तान के लोग दोनों देशों के मतभेद दूर करने के लिए आगे आए हैं। ट्रैक-2 वार्ता के तहत इन लोगों ने इस्लामाबाद में दो दिन तक द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों में पैदा तनाव को कम करने का यह पहला प्रयास है।

राजनीति और विवाद से अलग नई शुरुआत, शीर्षक वाली पहल इस्लामाबाद की संस्था रीजनल पीस इंस्टीट्यूट (आरपीआइ) ने की है। आरपीआइ के मुख्य कार्यकारी रऊफ हसन ने ट्वीट कर बताया कि बैठक में कोई औपचारिक वार्ता नहीं हुई। किसी खास मसले पर चर्चा नहीं हुई। दोनों देशों के लोग हर हालत में शांति बनाए रखने को संकल्पबद्ध थे। शांति को कैसे बनाए रखें, इसके लिए हम रास्ते तलाशेंगे। इस वार्ता में भारत की ओर से छह लोगों ने भाग लिया। शुक्रवार और शनिवार को हुई बैठकों में जनता की सुरक्षा, व्यापार और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों बढ़ाने के तरीकों पर वार्ता हुई। इसमें युवाओं को अग्रणी भूमिका देने पर सहमति बनी।

इन बैठकों में भविष्य की रूपरेखा तैयार करने, दोनों देशों की समान बातों को उभारने और विकास को मुद्दा बनाने पर चर्चा हुई। पुलवामा हमले के बाद युद्ध के कगार पर पहुंचे दोनों देशों के बीच विश्वास कायम करने को लेकर पहली बार यह कोशिश हुई है। गैर सरकारी लोगों की यह चर्चा करतारपुर कॉरीडोर परियोजना पर दोनों देशों के अधिकारियों की रविवार को अटारी-वाघा सीमा पर होने वाली बैठक से पहले हुई है।

पुलवामा हमले के बाद पहली बार शांति स्थापना को बैठे दोनों देशों के लोग

इस्लामाबाद में दो दिन तक द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत

पाक में रखी गई गुरु नानक विश्वविद्यालय की आधारशिला

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के ननकाना साहिब में शनिवार को बाबा गुरु नानक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रख दी गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित ननकाना साहिब सिख धर्म के पहले गुरु नानकदेव का जन्मस्थान है। स्थापना की घोषणा के करीब दस साल बाद विश्वविद्यालय निर्माण के लिए पहला पत्थर रखा गया है। विवि की आधारशिला पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार ने रखी। दस एकड़ जमीन पर 258 करोड़ रुपये की लागत से यह विश्वविद्यालय तैयार होगा। सरकार ने विश्वविद्यालय के बनने की समयसीमा अभी घोषित नहीं की है। पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी होते ही विवि का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि औपचारिकताएं जल्द पूरी हो जाएंगी, क्योंकि यह गृह मंत्री एजाज शाह खुद इस परियोजना में रुचि ले रहे हैं।

बगैर पासपोर्ट के मिली पाकिस्तान मूल की महिला को भेजा जेल

संवाद सूत्र, चम्पावत : बगैर पासपोर्ट और वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में आ रही पाकिस्तान मूल की अमेरिकी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वह काठमांडू से दिल्ली जा रही थी। भारत नेपाल मैत्री बस के इमीग्रेशन चेक पोस्ट बनबसा के पास पहुंची। यहां इमीग्रेशन अधिकारियों ने बस में थर्ड कंट्री नागरिक की पहचान के लिए यात्रियों के दस्तावेजों की जांच शुरू की तो एक पाकिस्तान मूल की महिला बगैर पासपोर्ट के भारत जा रही थी। पूछताछ में पहले वह खुद को नेपाली नागरिक बता रही थी।

संदिग्ध लगने पर उसे पूछताछ के लिए बस से उतार लिया गया। चेकिंग के दौरान उसके पास पासपोर्ट और वीजा नहीं मिला। पासपोर्ट की केवल फोटो कॉपी थी। महिला ने अपना नाम फरीदा मलिक (50) पुत्री सुल्तान अख्तर मलिक बताते हुए अमेरिकी नागरिक होना बताया। महिला का कहना था कि वह अपना पासपोर्ट काठमांडू में भूल आई है।

ये भी जानिए
जेसन रॉय ने अब तक विश्व कप में पिछली पांच पारियों में पहले विकेट के लिए 100 रनों से अधिक की साझेदारी की है। फाइनल में अकेला मौका था जब रॉय (28) बेयरस्टो के साथ 100 रनों की साझेदारी नहीं कर पाए।

खिताबी मुकाबले से पहले कलाकारों का यह अंदाज भी नजर आया। जागरण

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल से पहले ड्रम बजाकर माहौल बनाते प्रशंसक। जागरण

मैच देखते बीसीसीआइ कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना, अभिनेता अनुपम खेर व अन्य। जागरण

लॉर्ड्स में फाइनल देखने पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता बोमन ईरानी। जागरण

शानदार ▸ रोमांचक सुपर ओवर टाई होने के बाद बाउंड्री के अंतर से न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता इंग्लैंड

क्रिकेट का जन्मदाता बना विश्व विजेता

विश्व कप में दैनिक जागरण
अभिषेक त्रिपाठी ● लंदन

इंग्लैंड और भारत के प्रशंसकों से भरे लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान की हरी पिच पर न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सुबह हुई बारिश के कारण मैच आधे घंटे देरी से शुरू हुआ और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। विलियमसन ने पहले बल्लेबाजी के फैसले को लेकर कहा था कि इस पिच पर यह फैसला 50-50 का है और ऐसा ही साबित हुआ क्योंकि पिछले मैचों की तरह खिताबी मुकाबले में भी उसका पहला विकेट सातवें ओवर में ही गिर गया और इस कारण उसकी लय बिगड़ गई। हेनरी निकोल्स (55) और विकेटकीपर टॉम लाथम (47) की बदौलत टीम किसी तरह 50 ओवर में आठ विकेट पर 241 रन बनाने में कामयाब रही। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में 239 रन ही बनाए थे। लेकिन इंग्लैंड के लिए यह मैच जीतना इतना आसान नहीं रहा। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इंग्लैंड का शीर्ष क्रम धराशायी कर दिया। बाद में जोस बटलर (59) और बेन स्टोक्स (84 नाबाद) ने मेजबान टीम की मैच में वापसी कराई। हालांकि अंत में लॉकी फर्ग्यूसन ने 10 ओवर में 50 रन देकर तीन विकेट लिए और न्यूजीलैंड की मैच में वापसी कराई। हालांकि स्टोक्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 50 ओवर में 241 रन तक पहुंचा दिया और मैच टाई हो गया। विश्व कप इतिहास के फाइनल का यह पहला टाई मुकाबला रहा। इसके बाद सुपर ओवर में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 16 रनों का लक्ष्य दिया। न्यूजीलैंड भी 15 रन ही बना सका और स्कोर फिर टाई हो गया। पारी में अधिक बाउंड्री लगाने की वजह से इंग्लैंड खिताब जीत गया।

कीवियों की खराब बल्लेबाजी : इस मैच के लिए दोनों टीम ने कोई परिवर्तन नहीं किया। विलियमसन ने लगातार फेल होने के बावजूद मार्टिन गुप्टिल (19) को एक और मौका दिया। गुप्टिल 2015 विश्व कप के सबसे सफल बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 237 रनों की पारी खेली थी, लेकिन इस विश्व कप में 10 मैचों में वह 20.66 के औसत से सिर्फ 186 रन बना पाए। 2007 विश्व कप के शुरुआती दौर में ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट के साथ भी ऐसा हुआ था लेकिन फाइनल में उन्होंने धमाकेदार पारी खेलकर अपनी टीम को मुकाबला जिता दिया था। न्यूजीलैंड के प्रशंसक गुप्टिल से भी ऐसी ही उम्मीद कर रहे थे लेकिन वह दो चौके और एक छक्का लगाने के बाद वोक्स का शिकार हो गए। पगबाधा आउट होने के बाद उन्होंने साथी ओपनर निकोल्स से बातचीत की और रिव्यू लिया, लेकिन इस बार बार भाग्य ने न्यूजीलैंड का साथ नहीं दिया। वोक्स की लेंथ बॉल पर गुप्टिल मिड ऑफ पर ड्राइव मारना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले और गेंद के बीच से निकलकर पैड में गई। रिव्यू में भी वह साफ आउट थे।

ओपनर विलियमसन : न्यूजीलैंड ने इस विश्व कप में पहले मैच में पहले विकेट के लिए 137 रनों की साझेदारी की थी और उसके बाद उनकी तरफ से पहले विकेट के लिए 35, 29, 12, 5, 2, 1, 0, 0, 1 और 29 रनों की साझेदारी हुई। न्यूजीलैंड के नकारा ओपनरों के कारण ही कप्तान विलियमसन को इस विश्व कप में एक तरह से ओपनर का ही काम करना पड़ा है। वह पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ 16.2, दूसरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 5.2, तीसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 0.2, चौथे मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2.2, वेस्टइंडीज के खिलाफ 0.2, पाकिस्तान के खिलाफ 1.2, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9.3, इंग्लैंड के खिलाफ 0.6, भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में 3.4वें ओवर और इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 6.3वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे। पहला विकेट जल्दी गिरने के कारण उन्होंने काफी धीमी बल्लेबाजी की। उन्होंने शुरुआत 20 गेंद पर सिर्फ पांच रन बनाए और बाद की 22 गेंद पर 25 रन बनाए।

मिडिल ओवर मास्टर प्लंकेट : जब लग रहा था कि वह और निकोल्स टीम को उबारेंगे तभी लियाम प्लंकेट ने उन्हें विकेटकीपर बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। अंपायर ने विलियमसन को आउट नहीं दिया था लेकिन मेजबानों ने रिव्यू लिया और फैसला उनके पक्ष में गया। 15 रन के अंदर प्लंकेट ने निकोल्स को बोल्ड कर दिया। न्यूजीलैंड ने 118 के कुल योग पर तीन विकेट गंवा दिए। अप्रैल 2015 से अब तक प्लंकेट 11-40 ओवरों के बीच सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने इस दौरान 56 मैचों में बीच के ओवरों में लगभग 35 के औसत से 56 विकेट लिए हैं। उन्होंने इसके बाद जिम्मी नीशाम (19) को भी आउट किया।

शानदार तेज गेंदबाजी : इस मैच की हरी पिच पर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने विविधता दिखाई। जहां प्लंकेट ने क्रॉस सीम गेंदों पर जोर दिया तो स्टोक्स ने अतिरिक्त उछाल हासिल करने की कोशिश की। वुड ने तेज गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन उनको उछाल कम मिल रही थी। वहीं जोफ्रा आर्चर ने बाउंसर का काफी प्रयोग किया। 34वें ओवर की पहली गेंद रॉस टेलर (15) के पैड पर लगी और गेंदबाज वुड ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। नीशाम के आउट होने के बाद 39 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 175/3 हो गया था और इसके बाद कीवियों से बड़े स्कोर की आशा भी कम हो गई थी। वोक्स और प्लंकेट ने तीन-तीन विकेट लिए।

इंग्लैंड-न्यूजीलैंड फाइनल में भी खराब अंपायरिंग : विश्व कप के खिताबी मुकाबले में इस तरह की खराब अंपायरिंग देखने को मिलेगी इसकी उम्मीद नहीं थी। न्यूजीलैंड जब बल्लेबाजी करने उतरी तो तीसरे ओवर में ही क्रिस वोक्स की गेंद निकोल्स के पैड में लगी और तुरंत ही अंपायर कुमार धर्मसेना ने बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू करार दे दिया। निकोल्स ने साथी ओपनर मार्टिन गुप्टिल से चर्चा करने के बाद रिव्यू लिया। रीप्ले में साफ दिख रहा था कि गेंद स्टंप के ऊपर से जा रही थी। रिव्यू के कारण वह बच गए। 34वें ओवर की पहली गेंद पर दूसरे मैदान अंपायर मराइस इरासमस ने गलत निर्णय दिया जिसका खामियाजा न्यूजीलैंड को भुगतना पड़ा। मार्क वुड की गेंद टेलर के पैड में लगी और इरासमस ने कुछ देर सोचने के बाद अंगुली उठा दी।

विश्व कप में न्यूजीलैंड

विश्व कप	सफर
1975	सेमीफाइनल
1979	सेमीफाइनल
1983	लीग दौर
1987	लीग दौर
1992	सेमीफाइनल
1996	लीग दौर
1999	सेमीफाइनल
2003	लीग दौर
2007	सेमीफाइनल
2011	सेमीफाइनल
2015	फाइनल
2019	फाइनल

विश्व कप में इंग्लैंड

विश्व कप	सफर
1975	सेमीफाइनल
1979	फाइनल
1983	सेमीफाइनल
1987	फाइनल
1992	फाइनल
1996	लीग दौर
1999	लीग दौर
2003	लीग दौर
2007	लीग दौर
2011	लीग दौर
2015	लीग दौर
2019	फाइनल

सुपर ओवर का रोमांच

सुपर ओवर में इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। न्यूजीलैंड की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने ओवर किया। इंग्लैंड ने पहली गेंद पर तीन रन, दूसरी गेंद पर एक रन, तीसरी गेंद पर चार रन, चौथी गेंद पर एक रन, पांचवीं गेंद पर दो रन और छठीं गेंद पर चार रन बनाए। इसी के साथ न्यूजीलैंड को 16 रनों का लक्ष्य मिला। इसके बाद न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने आई। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद वाइड रही। इसके बाद पहली गेंद पर दो रन, दूसरी पर नीशाम ने छक्का लगाया। तीसरी पर दो, चौथी गेंद पर भी दो रन आए। पांचवीं गेंद पर एक ही रन आया। अब आखिरी गेंद पर दो रनों की दरकार थी। गुप्टिल दो रन पूरा करने के लिए दौड़े, लेकिन बटलर ने उन्हें दूसरे रन पर रन आउट कर दिया। इंग्लैंड की मैच में बाउंड्री 26 थी जबकि न्यूजीलैंड की 17।

मैच टाई कराने के बाद वापस लौटते इंग्लैंड के बल्लेबाज मार्क वुड और बेन स्टोक्स। एपी

स्कोर बोर्ड

टॉस : न्यूजीलैंड (बल्लेबाजी) मैन ऑफ द मैच : बेन स्टोक्स मैन ऑफ द टूर्नामेंट : केन विलियमसन

न्यूजीलैंड 241/8 (50 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
मार्टिन गुप्टिल एलबीडब्ल्यू बो. वोक्स	19	18	02	01
हेनरी निकोल्स बो. प्लंकेट	55	77	04	00
विलियमसन का. बटलर बो. प्लंकेट	30	53	02	00
रॉस टेलर एलबीडब्ल्यू बो. वुड	15	31	00	00
टॉम लाथम का. सब (विंस) बो. वोक्स	47	56	02	01
जेम्स नीशाम का. रूट बो. प्लंकेट	19	25	03	00
डि ग्रैंडहोम का. सब (विंस) बो. वोक्स	16	28	00	00
मिशेल सेंटनर नाबाद	05	09	00	00
मैट हेनरी बो. आर्चर	04	02	01	00
ट्रेंट बोल्ट नाबाद	01	02	00	00

अतिरिक्त : (लेबा-12, नोबॉ-1, वा-17) 30
कुल : 50 ओवर में आठ विकेट पर 241 रन

विकेट पतन : 1-29 (गुप्टिल, 6.2), 2-103 (विलियमसन, 22.4), 3-118 (निकोल्स, 26.5), 4-141 (टेलर, 33.1), 5-173 (नीशाम, 38.6), 6-219 (ग्रैंडहोम, 46.5), 7-232 (लाथम, 48.3), 8-240 (हेनरी, 49.3)

गेंदबाजी :
क्रिस वोक्स 9-0-37-3
जोफ्रा आर्चर 10-0-42-1
लियाम प्लंकेट 10-0-42-3
मार्क वुड 10-1-49-1
आदिल राशिद 8-0-39-0
बेन स्टोक्स 3-0-20-0

इंग्लैंड 241 (50 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
जेसन रॉय का. लाथम बो. हेनरी	17	20	03	00
जॉनी बेयरस्टो बो. फर्ग्यूसन	36	55	07	00
जो रूट का. लाथम बो. ग्रैंडहोम	07	30	00	00
इयोन मोर्गन का. फर्ग्यूसन बो. नीशाम	09	22	00	00
बेन स्टोक्स नाबाद	84	98	05	02
बटलर का. सब (साउथी) बो. फर्ग्यूसन	59	60	06	00
क्रिस वोक्स का. लाथम बो. फर्ग्यूसन	02	04	00	00
लियाम प्लंकेट का. बोल्ट बो. नीशाम	10	10	01	00
जोफ्रा आर्चर बो. नीशाम	00	01	00	00
आदिल राशिद रन आउट	00	00	00	00
मार्क वुड रन आउट	00	00	00	00

अतिरिक्त : (बा-2, लेबा-3, वा-12) 17
कुल : 50 ओवर में 241 रन पर सभी आउट

विकेट पतन : 1-28 (रॉय, 5.4), 2-59 (रूट, 16.3), 3-71 (बेयरस्टो, 19.3), 4-86 (मोर्गन, 23.1), 5-196 (बटलर, 44.5), 6-203 (वोक्स, 46.1), 7-220 (प्लंकेट, 48.3), 8-227 (आर्चर, 48.6), 9-240 (राशिद, 49.5)

गेंदबाजी :
ट्रेंट बोल्ट 10-0-67-0
मैट हेनरी 10-2-40-1
कोलिन डि ग्रैंडहोम 10-2-25-1
लॉकी फर्ग्यूसन 10-0-50-3
जेम्स नीशाम 7-0-43-3
मिशेल सेंटनर 3-0-11-0

परिणाम : मैच व सुपर ओवर टाई होने के बाद ज्यादा बाउंड्री से जीता इंग्लैंड

154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गेंद मार्क वुड ने इस मैच में डाली। यह इस विश्व कप की संयुक्त रूप से सबसे तेज गेंद रही। उनके अलावा जोफ्रा आर्चर और मिशेल स्टार्क ही इस विश्व कप में ऐसा कर चुके हैं

एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान बने केन

विशेष संवाददाता, लंदन

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने क्रिकेट विश्व कप के इतिहास का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह विश्व कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए विश्व कप 2019 के फाइनल में विलियमसन ने 30 रनों की पारी खेली। उन्होंने फाइनल मुकाबले में एक रन बनाते ही यह बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया।

इस विश्व कप में विलियमसन ने कुल 578 रन बनाए। इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने के नाम था। जयवर्धने ने 2007 विश्व कप में श्रीलंकाई टीम के लिए बतौर कप्तान 548 रन बनाए थे, लेकिन विलियमसन ने अब इस विश्व रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है।

एक विश्व कप में कप्तान के सर्वाधिक रन

कप्तान	देश	रन	विश्व कप
केन विलियमसन	न्यूजीलैंड	578	2019
महेला जयवर्धने	श्रीलंका	548	2007
रिकी पोंटिंग	ऑस्ट्रेलिया	538	2007
आरोन फिंच	ऑस्ट्रेलिया	507	2019

इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में शॉट खेलते न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। एपी

भारतीयों से टिकट मांगते रहे अंग्रेज और कीवी

टिकट हासिल करने के लिए तख्ती लगाकर घूम रहे थे दोनों देशों के प्रशंसक

अभिषेक त्रिपाठी, लंदन

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और भारत की कंपनियों का ही क्रिकेट में दखल नहीं है, बल्कि टीम इंडिया के प्रशंसकों का भी इस क्षेत्र में जलवा है। इंग्लैंड में खत्म हुए विश्व कप में अधिकतर मैदानों पर खासकर भारत के मैचों में सिर्फ भारतीय दर्शक ही नीली टीशर्ट में नजर आते थे। यही नहीं, बर्मिंघम में इंग्लैंड की टीम मेजबान के तौर पर खेल रही थी, लेकिन पूरा एजबेस्टन स्टेडियम भारतीय प्रशंसकों से भरा हुआ था। विराट सेना के प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय प्रशंसकों ने फाइनल मुकाबले के अधिकतर टिकट भी खरीद लिए थे, लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम खिताबी मुकाबले में पहुंच गईं।

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल में पहुंचने के कारण दोनों देशों के प्रशंसकों की इस मैच में रुचि बढ़ गई, लेकिन सारे टिकट पहले से ही बिक जाने के कारण उनको टिकट नहीं मिल रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जिम्मी नीशाम ने एक दिन पहले भारतीय प्रशंसकों से प्रार्थना की थी कि वे अपने टिकट आइसीसी के रीसेल प्लेटफॉर्म पर बेच दें, जिससे उनके प्रशंसक उनकी टीम का मुकाबला देख सकें। सुबह जब सब लोग लॉर्ड्स की तरफ जा रहे थे तो दोनों देशों के प्रशंसक तख्ती लगाकर टिकट देने का निवेदन कर रहे थे। न्यूजीलैंड के प्रशंसक एंडी मैकमिलन सेंट जॉन वुड्स ट्यूब स्टेशन के पास तख्ती लेकर खड़े थे। उस पर लिखा था कि मैं वास्तविक प्रशंसक हूं। मैं उस दाम तक टिकट खरीद सकता हूं जिसमें मुझे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़े। वहीं इंग्लैंड के प्रशंसक रॉबर्ट बॉथम सुबह से यहां पहुंच गए थे और करीब दो घंटे हाथ में तख्ती लेकर घूमते रहे, उसके बाद उन्हें 800 पाउंड का एक टिकट मिला। उन्होंने कहा कि मैं मैच शुरू होने के तीन घंटे पहले ही यहां पहुंच गया था। मैंने तख्ती में लिख रखा था कि मैं पहली बार इंग्लैंड को विश्व कप जीतते हुए देखना चाहता हूं। कृपया करके इस टीम के वास्तविक प्रशंसक को अपने घर में मैच देखने के लिए टिकट बेच दें। उन्होंने कहा कि एक भारतीय ने मुझे टिकट बेच दी और उससे मैंने मैच देखा। इस टिकट की वास्तविक कीमत 295 पाउंड थी।

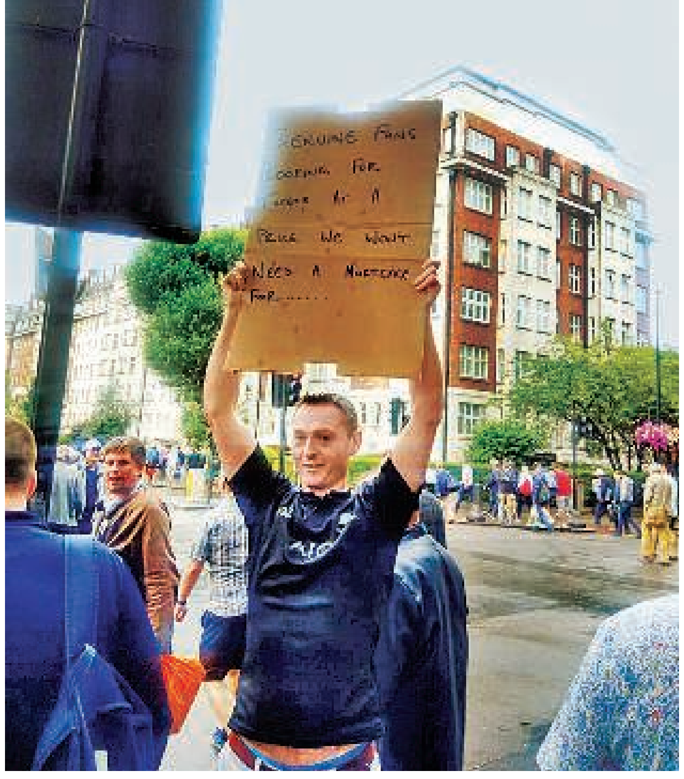
तख्ती लगाकर टिकट देने का निवेदन करता एक कीवी प्रशंसक। जागरण

केन विलियमसन ने विश्व कप में दबाव अच्छा झेला

कुमार संगकारा
बिहाइंड द स्टंप

न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ अपने प्रदर्शन से खुद पर गर्व महसूस कर सकती है, जिन्होंने शानदार तेज गेंदबाजी से बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने एक बेहतर रणनीति से और नियंत्रित क्रिकेट खेला जिसने मैकुलम के दिनों की याद दिलाई।

2015 विश्व कप में देखें तो न्यूजीलैंड की टीम वहां शीर्ष पर थी, उन्होंने ब्रेंडन मैकुलम के नेतृत्व में आक्रामक क्रिकेट खेला था और उनके फाइनल खेलने की संभावना थी। वहीं इस विश्व कप में वह इतने आक्रामक नहीं थे, लेकिन उन्होंने तब भी शानदार प्रदर्शन किया। इसका श्रेय केन विलियमसन के शांत नेतृत्व को जाता है।

उन्होंने न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ रन स्कोरर और कप्तान का दबाव अच्छे से संभाला। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला शानदार था। ऑस्ट्रेलिया चोट से जूझने के बाद भी मिशेल स्टार्क की फॉर्म को देखते हुए दूसरा सेमीफाइनल जीतने के लिए सुसज्जित टीम दिख रही थी। इंग्लैंड ने दबाव में अच्छा खेल खेला।

जेसन रॉय की वापसी और उनकी खतरनाक फॉर्म विरोधी टीमों के लिए चुनौतीपूर्ण बन गई थी। वह जॉनी बेयरस्टो को आजादी और आत्मविश्वास से खेलने की इजाजत देते हैं। मैं इस बात से आश्चर्यचकित हुआ कि ऑस्ट्रेलिया बायें हाथ के बल्लेबाज मैथ्यू वेड की जगह पीटर हैंड्सकोंब के साथ खेला। वेड ने ऑस्ट्रेलिया-ए के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। वह आत्मविश्वास से भरे बल्लेबाज हैं जो तकनीक से ज्यादा रन बनाने में विश्वास रखते हैं। हैंड्सकोंब को मानसिक और तकनीकी दोनों रूप से बहुत काम करना था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर अच्छा किया, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शुरुआत में रणनीति के साथ दमदार गेंदबाजी की। जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के लिए एक रहस्योद्घाटन की तरह हैं। वह बहुत जल्दी सीखते हैं और इस टूर्नामेंट में बहुत तेजी से विकसित हुए हैं। उनकी क्षमता और गति पर कभी भी संदेह नहीं था, लेकिन उनका स्वभाव और परिपक्वता शानदार है। उनकी सटीकतका, विविधता को देखना शानदार है।

THE ULTIMATE INVERTER BATTERY
EXIDE INVATUBULAR

माल्या के साथ फोटो खिंचाकर ट्रोल हुए गेल

नई दिल्ली, एएनआइ : वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल भारत के भगौड़े कारोबारी विजय माल्या के साथ दिखाई देने से ट्रोल हो गए। विस्फोटक बल्लेबाज ने ट्विटर पर विजय माल्या को बिग बॉस बताते हुए फोटो शेयर किया है। इस ट्वीट के बाद गेल ट्रोल हो गए। गेल और माल्या शनिवार को फॉर्मूला-1 ब्रिटिश ग्रां प्रि के वेन्यू पर मिले थे। गेल ने लिखा कि बिग बॉस विजय माल्या से मिलकर बहुत अच्छा लगा।

जिस दिन मैंने समानता के लिए लड़ना छोड़ दिया, उस दिन आप मुझे मेरी कब्र में पाएंगे।
–सेरेना विलियम्स, अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी

शानदार ▸ अमेरिकी पेशेवर सर्किट में पदार्पण करते हुए स्नाइडर को हराया

विजेंदर ने जीती लगातार 11वीं बाउट

भारतीय मुक्केबाज को नॉकआउट के जरिये मिली आठवीं जीत

नेवार्क (अमेरिका), प्रेट्र : भारतीय स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने यहां अमेरिकी पेशेवर सर्किट में पदार्पण करते हुए अपने से कहीं ज्यादा अनुभवी माइक स्नाइडर पर तकनीकी नॉकआउट के जरिये जीत हासिल की। आठ राउंड की सुपर मिडिलवेट बाउट में हरियाणा के 33 साल के मुक्केबाज ने चार राउंड में दबदबा बनाकर सर्किट में लगातार 11वीं जीत हासिल की। विजेंदर ने बाउट के बाद कहा, 'लंबे समय बाद रिंग में वापसी करना शानदार है। यहां अमेरिका में आना और जीत हासिल करना शानदार है। यह सचमुच काफी रोमांचक था। मैं अमेरिका में पदार्पण में जीत दर्ज कर काफी खुश हूं।' यह जीत उन्हें चौथे दौर के दूसरे मिनट में मिली जब विजेंदर ने स्नाइडर को लगातार सीधे पंच से पस्त कर दिया, जिससे रेफरी को बाउट इस भारतीय मुक्केबाज के पक्ष में करने के लिए बाध्य होना पड़ा। विजेंदर ने कहा, 'मुझे दबदबा बनाने में चार राउंड लगे। मैंने दो या तीन राउंड की उम्मीद की थी, लेकिन मुझे इसमें चार राउंड लग गए।'

यह विजेंदर की आठवीं नॉकआउट जीत है। पूरी बाउट के दौरान 38 वर्ष के स्नाइडर के पंच में ज्यादा दम नहीं दिखा, जबकि एक साल से ज्यादा समय बाद वापसी कर रहे विजेंदर के पंच काफी सटीक और दमदार थे। स्थानीय प्रबल दावेदार के खिलाफ विजेंदर का कहीं भी खतरा नहीं दिखा और उन्होंने स्नाइडर के कमजोर आक्रमण को आसानी से रोक दिया। स्नाइडर का जीत का रिकॉर्ड 13-5-3 है। पूर्व डब्ल्यूबीओ एशिया पेसिफिक चैंपियन विजेंदर हाल में दक्षिण दिल्ली की सीट से आम चुनाव में कांग्रेस की तरफ से लड़े थे, लेकिन उसमें उन्हें हार मिली थी। 'हॉल ऑफ फेम' बाब अरूम के टॉम रैंक प्रोमोशंस से करार करने के बाद विजेंदर इस साल दो और फाइट में भाग लेना चाहते हैं।

अमेरिका में स्नाइडर को हराने के बाद जश्न मनाते भारतीय पेशेवर मुक्केबाज विजेंदर सिंह। एपी

ब्राजीली स्ट्राइकर नेमार ने पीएसजी के साथ वाक युद्ध को दी हवा

पेरिस, एएफपी : ब्राजीली स्ट्राइकर नेमार ने यह कहते हुए पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) के साथ अपने वाक युद्ध को हवा दी है कि उनकी सबसे खास यादगार जीत पीएसजी पर 2017 में बार्सिलोना की वापसी वाली जीत है।

एक ऑनलाइन खेल चैनल द्वारा जब दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर नेमार से पूछा गया कि चेंजिंग रूम से जुड़ी उनकी सबसे अच्छी याद क्या है तो उन्होंने पीएसजी पर मिली बार्सिलोना की उस जीत का जिक्र किया। नेमार ने कहा कि उस जीत के बाद हम सभी पागल हो गए थे। मुझे लगता है कि वह हम सभी के लिए सबसे अच्छा अनुभव था। नेमार ने साओ पाउलो में सोमवार को पीएसजी से जुड़ने से पहले यह बात कही।

नेमार का हालिया बयान उनके मौजूदा क्लब के साथ रिश्ते पर असर डाल सकता है। खबरों के मुताबिक नेमार पीएसजी को छोड़कर बार्सिलोना लौटना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक भारी-भरकम करार की जरूरत होगी। 2017 में नेमार ने बार्सिलोना को छोड़कर पीएसजी से 222 मिलियन यूरो (करीब 17 अरब रुपये) में करार किया था। हाल ही में बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड के स्टार स्ट्राइकर एंटोनी ग्रीजमैन को 120 मिलियन यूरो (करीब नौ अरब 27 करोड़ रुपये) में अपने साथ जोड़ा है जिसके बाद अब नेमार के बार्सिलोना के साथ जुड़ने को लेकर जटिलताएं खड़ी हो गई हैं। पिछले सोमवार को ही नेमार को पीएसजी के प्री सीजन से जुड़ना था, लेकिन ब्राजीली स्टार समय पर नहीं पहुंच पाए जिसके बाद पीएसजी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी थी। उधर हाल ही में पीएसजी के खेल निदेशक लियोनार्डो ने कहा था कि अगर क्लब को करार के लिए सही प्रस्ताव मिलता है तो नेमार क्लब को छोड़ सकते हैं।

नेमार ने शनिवार को बाद में इंस्टाग्राम पर एक 10 सेकेंड का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह बार्सिलोना की जर्सी पहने हुए हैं और उन्होंने बाइबल के हवाले से लिखा है कि कोई भी हथियार आपकी समृद्धि के खिलाफ नहीं जा सकता है। मालूम हो कि 2017 के चैंपियंस लीग के अंतिम-16 में बार्सिलोना ने पहले दौर में 0-4 से हारने के बावजूद पीएसजी को दूसरे दौर में हराया था जहां नेमार ने दो गोल दागे थे।

नेमार का कहना है कि वह करीब-करीब 100 फीसदी फिट हो चुके हैं।

एंटोनी ग्रीजमैन बोले, अभ्यास में मेसी की पसंद जानने को लेकर उत्साहित हूं

बार्सिलोना, एएनआइ : स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना से हाल ही में जुड़े फ्रेंच स्ट्राइकर एंटोनी ग्रीजमैन ने कहा है कि वह देखना चाहते हैं कि अभ्यास सत्र के दौरान अर्जेंटीनी स्टार लियोन मेसी को क्या पसंद है। ग्रीजमैन ने कहा कि मैं यह जानने के लिए उत्साहित हूं कि हर दिन मेसी को अभ्यास में क्या पसंद है। मैं वास्तव में अपने नए साथी खिलाड़ियों और बॉस के साथ काम करने और कैंप नाउ में खेलने और बहुत कुछ जीतने को लेकर उत्साहित हूं।

फुटबॉल डायरी

- ब्राजील स्टार ने 2017 में पीएसजी पर मिली बार्सा की जीत को बताया यादगार
- बार्सिलोना में नेमार के जाने की चल रही हैं खबरें

पीएसजी के स्ट्राइकर नेमार। फाइल फोटो, एपी

विनेश ने जीता स्वर्ण पदक

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

▸ दीपक पूनिया को रजत, जबकि सुमित ने जीता कांस्य पदक

भारतीय स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट ने तुर्की के इस्तांबुल में यासर दोगू अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में रूस की कैटरीना पोलेस्चुक पर शानदार जीत से 53 किग्रा में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। विनेश ने पिछले सप्ताह स्पेन ग्रां प्रि में पोडियम स्थान हासिल किया था। उन्होंने यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट के फाइनल में रूस की प्रतिद्वंद्वी को 9-5 से शिकस्त देकर स्वर्ण जीता था।

विनेश का पदक महिला स्पर्धा में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण था। स्वर्ण पदक के सफर तक विनेश ने अपनी तीन में से दो बाउट तकनीकी श्रेष्ठता के बूते जीतीं। इससे पहले सीमा ने 50 किग्रा और मंजू ने 59 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता था। पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में दीपक पूनिया ने 86 किग्रा में रजत जीता, उन्हें फाइनल में अजरबैजान के एलेक्सांद्र गोस्तियेव से 2-7 से पराजय झेलनी पड़ी। सुमित ने 125 किग्रा में कांस्य जीतकर भारत की पदक संख्या में इजाफा किया। बजरंग पूनिया की अनुपस्थिति में स्नोबा तनाजी गोंगाने 65 किग्रा में भाग ले रहे थे लेकिन वह कांस्य पदक के मुकाबले में तुर्की के सेंगीजान इरोडगन से तकनीकी श्रेष्ठता में हार गए। रजनीश (70 किग्रा) और विक्की (92 किग्रा) भी कांस्य पदक मैच हार गए जबकि अमित (74 किग्रा) और सत्यव्रत (97 किग्रा) क्वालीफिकेशन दौर से आगे नहीं बढ़ सके।

अनस विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई

▸ पुरुषों के गोला फेंक में तेजिंदर ने कांस्य जीतने के लिए 20.36 मीटर का थ्रो फेंका

नई दिल्ली, प्रेट्र : मुहम्मद अनस ने चेक गणराज्य में चल रही क्लादनो एथलेटिक्स टूर्नामेंट की पुरुष 400 मीटर स्पर्धा में अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए स्वर्ण पदक जीता और विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया। 24 वर्षीय अनस ने 45.21 सेकेंड के समय से पहला स्थान प्राप्त किया वह पोलैंड के रजत पदक विजेता ओमेलको रफाल (46.19) से एक सेकेंड आगे रहे। अनस ने पिछले साल 45.24 सेकेंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, उन्होंने इसे तोड़ते हुए 27 सितंबर से छह अक्टूबर के बीच दोहा में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया। पुरुषों की 400 मीटर रेस के लिए विश्व चैंपियनशिप क्वालीफाइंग समय 45.30 सेकेंड का था।

भारत के विपिन कसाना, अभिषेक सिंह और देविंदर सिंह कंग ने पुरुष भाला फेंक फाइनल में क्रमशः 82.51 मीटर, 77.32 मीटर और 76.58 मीटर की दूरी से शीर्ष तीन स्थान हासिल किए। पुरुषों की गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी तेजिंदर पाल सिंह तूर ने कांस्य जीतने के लिए 20.36 मीटर का थ्रो फेंका। उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 20.75 मीटर का है। महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में वी के विस्मया ने 52.54 सेकेंड के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से रेस जीत ली। सरिताबेन गायकवाड़ 53.37 सेकेंड के समय से तीसरे स्थान पर रहीं। इस बीच, किर्गिस्तान के बिश्केक में अंतरराष्ट्रीय स्मृति टूर्नामेंट में भारतीयों ने छह स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य भी जीता। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी एम श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धा में 7.97 मीटर की कूद से जीत दर्ज की।

अर्चना 100 मीटर (11.74 सेकेंड) में, हर्ष कुमार 400 मीटर (46.76 सेकेंड) में, लिली दास 1500 मीटर (4:19.05) में, भाला फेंक में साहिल सिलवाल (78.50 मीटर) और महिलाओं की 4×100 रिले टीम (45.81 सेकेंड) स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। राहुल (1500 मीटर, 3:50.69), जिस्ना मैथ्यू (400 मीटर, 53.76) और गजानंद मिस्त्री (400 मीटर, 47.23) ने रजत पदक जीते, जबकि रोहित यादव ने भाला फेंक (73.33 मीटर) में कांस्य पदक जीता।

केकेआर से अलग हुए कैलिस और कैटिच

कोलकाता, प्रेट्र : दो बार की इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) विजेता कोलकाता नाइटराइडर्स अगले सत्र से नए कोचिंग स्टाफ के साथ नजर आएगी। टीम प्रबंधन मौजूदा कोच जैक कैलिस और सहायक कोच साइमन कैटिच से अलग हो गया है। कैलिस अक्टूबर 2015 में कोलकाता टीम के मुख्य कोच बने थे। उन्हें ट्रेवर बेलिस के स्थान पर नया कोच चुना गया था। बेलिस इस समय इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच हैं। कैलिस के कोच बनने के बाद से कोलकाता ने लगातार तीन बार प्लेऑफ में जगह बनाई थी, लेकिन इस वर्ष वह प्लेऑफ में जगह बनाने में विफल रही। कैलिस और कैटिच के मार्गदर्शन में कोलकाता ने 32 मैच जीते हैं।

बुजुर्ग महिला प्रशंसक की यॉर्कर देख चौंकन्ने रह गए बुमराह : नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय क्रिकेट टीम के यॉर्कर विशेषज्ञ

क्रिकेट डायरी

जसप्रीत बुमराह पिछले दो-तीन वर्षों में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में एक शानदार गेंदबाज बनकर उभरें हैं। खेल के किसी भी समय विकेट लेने की अपनी क्षमता के चलते वह मौजूदा समय में रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। ट्विटर पर एक यूजर्स ने शनिवार को एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला बुमराह के गेंदबाजी एक्शन की नकल करती हुई दिखाई दे रही हैं। यह वीडियो शांता सक्कूबाई नाम की एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला बुमराह के गेंदबाजी एक्शन की नकल करते हुए नजर आ रही है। 21 वर्षीय बुमराह ने भी इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इससे मेरा दिन बन गया।

विविध

'जो इस खेल से मिला है, बस वही लौटा रहा हूं'

जागरण विशेष ▸ अपनी नर्सरी में हॉकी खिलाड़ियों को तराश रहे पूर्व ओलंपियन सैयद अली

राजीव बाजपेयी, लखनऊ

लखनऊ के चंद्रभानु गुप्त मैदान में पूर्व ओलंपियन सैयद अली अपनी नर्सरी में खिलाड़ियों को इस मकसद से तराशते और निखारते हैं कि वे किसी दिन देश के लिए खेल सके और हॉकी के फिर से सुनहरे दिन ला सकें। सैयद अली की नर्सरी से कई खिलाड़ी देश के लिए खेल भी चुके हैं। 33 साल से अनवरत जारी उनका प्रयास देश की निस्वार्थ सेवा का अप्रतिम उदाहरण है। महान हॉकी खिलाड़ी केडी सिंह बाबू की धरती पर उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे सैयद अली की नजर में वह कुछ खास नहीं कर रहे। वह बस इतना ही कहते हैं, 'जो इस खेल से मिला है, बस वही लौटा रहा हूं।'

नैनीताल से आए लखनऊ : भारत के लिए कई अंतराराष्ट्रीय हॉकी मैच खेल चुके सैयद अली के लखनऊ आने की कहानी भी बड़ी रोचक है। नैनीताल में उनकी कपड़े की सिलाई की दुकान थी। वहीं पर केडी सिंह बाबू ने उन्हें स्थानीय प्रतियोगिता में खेलते देखा तो लखनऊ ले आए।

बता दें कि केडी सिंह ओलंपिक में 1948 (लंदन) और 1952 (हेलसिंकी) में हॉकी में गोल्ड जीतने वाली टीम में सदस्य थे। 1952 में तो वह टीम के उपकप्तान भी थे। यह केडी सिंह की प्रतिभा परखने की नजर ही थी, जिसने प्रशिक्षण देकर सैयद अली को 1976 की मॉन्ट्रियल ओलंपिक टीम तक पहुंचाया। सैयद अली ने देश को कई यादगार क्षण दिए। आज भले ही वह खेल से रिटायर हो गए हैं, लेकिन वह पहले भी ज्यादा सक्रिय हैं। स्टेट बैंक में नौकरी कर रहे सैयद छुट्टी मिलते ही सीधे चंद्रभानु गुप्त मैदान पर पहुंच जाते हैं और हॉकी की प्रतिभाओं को तराशते हैं।

दाखिले के लिए शुल्क नहीं जुनून की दरकार : बिना सरकारी मदद के चलने वाली सैयद अली की नर्सरी में दाखिले के लिए शुल्क नहीं, हॉकी के लिए केवल जुनून की जरूरत होती है। इसी के सहारे इस नर्सरी से ललित उपाध्याय, आमिर, हरिकृपाल, राहुल शिल्पकार, सौरभ, विजय थापा, विवेकधर, अमित प्रभाकर, सिद्धार्थ शंकर, दीपक सिंह, शारदानंद तिवारी, कुमारी कमला रावत, कविता मौर्या और कमलेश जैसे खिलाड़ी इंडिया कैंप तक पहुंचे। कमल थापा, वीरबहादुर, अविनाश, मो. रफीक, कुमारी फरहा, अभिमन्यु, कवि यादव, विजय कुमार, प्रशांत कबीर, शुभम वर्मा, राहुल वर्मा, अंकित कुमार, आकाश यादव, सौरभ यादव, गौरव यादव राष्ट्रीय टीम के लिए खेल चुके हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

नेशनल कॉलेज ग्राउंड पर बच्चों को हॉकी का प्रशिक्षण देते पूर्व ओलंपियन सैयद अली। जागरण

सुजीत कुमार करते हैं गरीब बच्चों की मदद

करीब 33 साल पहले पद्मश्री जमन लाल शर्मा के साथ सैयद अली ने बच्चों को हॉकी सिखाना शुरू किया। अधिकतर बच्चे गरीब घरों के थे। उनके पास हॉकी और जूते तक खरीदने की क्षमता नहीं थी। खेल के प्रति अपने जुनून के चलते सैयद ने बच्चों की जरुरतें पूरी करने लगे। सैयद के संघर्ष को देखकर कुछ साथियों ने हाथ बढ़ाया। इनमें से एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सुजीत कुमार आज तक गरीब बच्चों का भविष्य संवारने में मदद कर रहे हैं। सैयद अली सुजीत कुमार के सहयोग का जिक्र करने के साथ इसके लिए उनका आभार जताने से नहीं चूकते।

15 से बंद नहीं होगा अक्षयवट, श्रद्धालुओं को हो सकेंगे दर्शन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगाने के लिए देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को किले के भीतर अक्षयवट के दर्शन का भी मौका मिलता रहेगा। कहा जा रहा था कि 15 जुलाई के बाद अक्षयवट के दर्शन बंद हो जाएंगे, लेकिन प्रशासन से स्पष्ट किया है कि बाढ़ का पानी किले के पास पहुंचने पर ही अक्षयवट बंद होगा। उसी अवधि में सेना अक्षयवट स्थल पर मरम्मत का काम कराएगी।

किले के भीतर सदियों से बंद अक्षयवट को कुंभ से पहले श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। कुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसके बाद 15 जुलाई के बाद अक्षयवट दर्शन बंद होने की बात कही गई थी, क्योंकि गंगा-यमुना में बाढ़ आने पर किले से लेकर लेटे हनुमान मंदिर तक पानी आ जाता है। इससे श्रद्धालु वहां नहीं पहुंच सकेंगे। इसी अवधि में वहां मरम्मत आदि के कार्य कराए जाएंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के एडीएम द्वितीय दिलीप त्रिगुनायत का कहना है कि फिलहाल अक्षयवट श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। यह निर्णय 31 मार्च को जिला प्रशासन, मेला प्राधिकरण और सेना के साथ बैठक तथा इसके बाद की बैठक में हो चुका है। मरम्मत के लिए एक माह तक अक्षयवट बंद करने की योजना है, लेकिन यह समय सेना तय करेगी।

अबू धाबी से आए इंदौर के दंपती ने कराया बेटी का उपनयन संस्कार

नई परंपरा की शुरुआत

- दो वर्ष शास्त्रों का अध्ययन कर तलाशे बालिकाओं के यज्ञोपवीत के प्रमाण
- बेटियों को ज्ञान से जुड़े संस्कार से दूर करने पर जताई असहमति, भेदभाव पर आपत्ति

योगेश कुलकर्णी ने दुबई से इंदौर आकर बेटी और बेटे का उपनयन संस्कार करा कर एक भ्रांति को तोड़ा है। नईदुनिया

रामकृष्ण मुले, इंदौर

आमतौर पर पठन-पाठन शुरू करने से पहले बेटे का उपनयन संस्कार कराना सामान्य बात है, लेकिन बेटी के उपनयन के उदाहरण मुश्किल से मिलते हैं। अबू धाबी (दुबई) में रहने वाले इंदौर के एक दंपती योगेश कुलकर्णी और माणिक कुलकर्णी ने आठ साल की बेटी शमिका का उपनयन संस्कार उसके जुड़वां भाई शनय के साथ कराया। इसके लिए उन्होंने दो साल तक शास्त्रों का अध्ययन कर इसके उदाहरण भी तलाशे। उनका मानना है कि यह संस्कार विद्या से जुड़ा है, जिसमें गायत्री माता का पूजन होता है। इसमें बेटे-बेटी के बीच भेदभाव उचित नहीं है।

अबू धाबी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर योगेश का कहना है कि चार साल पहले पुणे में एक आयोजन के दौरान उन्हें लड़कियों का उपनयन संस्कार होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने विद्वानों से चर्चा शुरू की। फिर ज्ञान प्रबोधनी और पुरातन पुस्तकों का अध्ययन किया। इसमें ऋषि पुत्री गार्गी और लोपमुद्रा का उल्लेख आता है, जिनका उपनयन संस्कार हुआ था। इसके बाद उन्होंने इंदौर आकर अपने गुरु से चर्चा की और सबकी सहमति से 11 जुलाई को उपनयन संस्कार कराया।

आर्य समाज देता है अनुमति : आर्य समाज मंदिर के मंत्री मनोज सोनी बताते हैं कि सभी सोलह संस्कार लड़के और लड़कियों के लिए हैं। बालिकाओं के उपनयन संस्कार की अनुमति आर्य समाज देता है, लेकिन अब कई जगह बालिकाओं को जनेऊ पहनने से दूर कर दिया गया है। जनेऊ के तीन धागे माता-पिता, राष्ट्र और धर्म पालन के प्रतीक हैं, जिस पर दोनों का समान अधिकार है।

यह है उपनयन संस्कार : हिंदू धर्म में सोलह संस्कारों में से उपनयन संस्कार का स्थान दसवां है। माना जाता है कि इस संस्कार से बालक के भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस संस्कार में बटुकों को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। शिक्षा की शुरुआत के समय यह संस्कार कराने की परंपरा है।

परंपरागत चिमनियों–दीपों से रोशन होगा भोपाल में बन रहा इस्कॉन मंदिर

बृजेंद्र वर्मा, भोपाल

भोपाल के पटेल नगर में देश का पहला ऐसा इस्कॉन मंदिर बन रहा है, जिसमें रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रात के अंधेरे में परंपरागत चिमनियों व दीपों से मंदिर रोशन होगा। मंदिर के गर्भगृह, अतिथि कक्ष, रसोई घर, संत निवास से लेकर अन्य कमरों में बिजली की फिटिंग भी नहीं की जा रही है। इन दीपों और चिमनियों में अरंडी के तेल का उपयोग किया जाएगा।

अंतराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कॉन) भोपाल के मीडिया प्रभारी श्याम सुंदर प्रभु ने बताया कि पुराने समय में बिजली नहीं हुआ करती थी। लोग रात में घरों में रोशनी के लिए चिमनियों व दीपों को ही जलाते थे। उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इससे यहां आने वाले भक्त भगवान श्रीकृष्ण का भजन व गीता का ज्ञान एक परंपरागत स्थान व माहौल में प्राप्त करेंगे।

इस्कॉन मंदिर के सेवक देवाशीष ने बताया कि दक्षिण भारत के सेलम में इस्कॉन मंदिर है। वह मंदिर भी पूरी तरह दीपों से रोशन नहीं होता। बिजली का इस्तेमाल किया गया है। भोपाल में बन रहा इस्कॉन मंदिर देश का पहला ऐसा मंदिर होगा जो पीतल के बड़े-बड़े दीपों से जगमग होगा। मोबाइल व लेपटॉप आदि चार्ज हो सकें, इसके लिए सिर्फ एक हॉल के लिए बिजली का अस्थाई कनेक्शन लिया गया है। इसके अतिरिक्त मंदिर में कहीं भी बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

भीषण गर्मी में रहेगी ठंडक : मंदिर में ईंट, सीमेंट व रेत की दीवारें खड़ी कर ऐसी चुनाई की गई है जिससे गर्मी में दीवारें ज्यादा गर्म न हों। सीमेंट का प्लास्टर नहीं किया गया है। मिट्टी व गोबर का लेप दीवारों पर किया गया है। इसके साथ ही मंदिर के गर्भगृह सहित अन्य कमरों की छत आरसीसी की नहीं है। इसमें लकड़ियों का प्रयोग किया गया है। लकड़ियों के ऊपर मिट्टी के खप्परों से छत बनाई गई है। इससे भीषण गर्मी पड़ने पर भी मंदिर के अंदर के परिसर में ठंडक रहेगी। इतना ही नहीं, मंदिर के पांच संत कमरों व रसोई घर की फर्श पक्की नहीं की गई है। फर्श पर मिट्टी व गोबर का ही लेप किया गया है। मिट्टी की टाइल्स भी लगाई गई है।

रसोई में गैस से नहीं, लकड़ियों से पकेगा खाना : मंदिर के एक बड़े हॉल में रसोई बनाई गई है। खाना पकाने में एलपीजी गैस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लकड़ियों से ही खाना पकाया जाएगा। रसोईघर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि खाना पकाने के दौरान धुंआ मंदिर परिसर में न फैले, सीधे छत के रास्ते निकल जाए। रसोई घर बनकर तैयार है। जगन्नाथ यात्रा में आने वाले भक्तों के लिए परंपरानुसार लकड़ियों से ही खाना बनने लगा है।

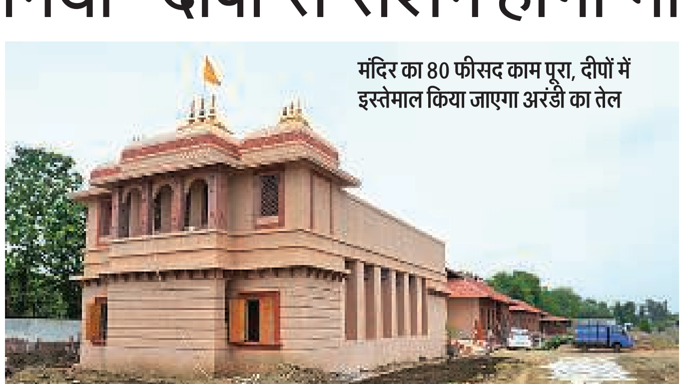
मंदिर का 80 फीसद काम पूरा, दीपों में इस्तेमाल किया जाएगा अरंडी का तेल
रायसेन रोड पर बना रहा यह इस्कॉन मंदिर, कई मायनों में अन्य देवालयों से अलग है। नईदुनिया

एक नजर में इस्कॉन मंदिर

- 03 एकड़ जमीन पटेल नगर एनआरआइ कॉलेज के पास में उद्योगपति राकेश शर्मा ने इस्कॉन मंदिर के लिए मई 2013 में दान में दी
- 10 हजार वर्गफीट क्षेत्र में मंदिर का निर्माण हो रहा है। बाकी जगह पार्किंग, सड़क व पौधे लगाने के लिए छोड़ी गई है
- 1.5 करोड़ रुपये है इस इस्कॉन मंदिर की लागत
- अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था इस मंदिर के निर्माण का काम

मौसम विशेष

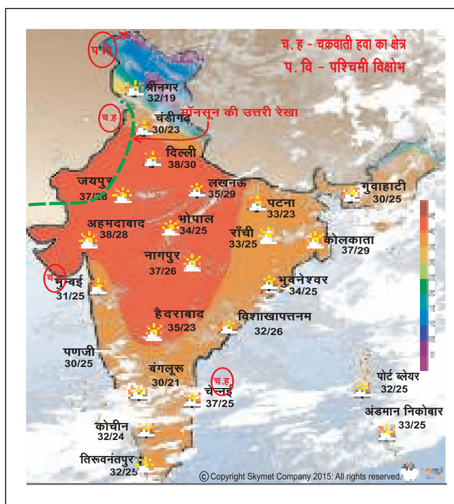

उत्तरी हरियाणा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा संभव है। दिल्ली सहित मैदानी भागों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ धूलभरी आंधी व हल्की वर्षा संभव है। जम्मू-कश्मीर में मौसम गर्म व हिमाचल प्रदेश में आरामदायक रहेगा। इन राज्यों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/25/व	अहमदाबाद	38/28/व
कोलकाता	34/28/आंबा	बड़ौदा	36/26/आंबा
चेन्नई	37/26/आंबा	नागपुर	38/26/व
हैदराबाद	36/23/व	इन्दौर	35/24/व
बंगलूरु	29/20/व	रांची	35/26/व
त्रिवेन्द्रम	31/26/व	पटना	35/28/व
गुवाहाटी	32/25/आंबा	जमशेदपुर	36/26/व
गंगटोक	20/11/व	पुणे	24/22/व

हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग की स्थापना हुई

1916 में आज ही विलियम बोइंग ने हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग की अमेरिका के शिकागो में स्थापना की। उस समय इसका नाम पैसिफिक एयरो प्रोडक्ट्स था। इसे अप्रैल 1917 को बोइंग नाम दिया गया।

माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल साइट ट्विटर की शुरुआत हुई

2006 में आज ही ट्विटर की शुरुआत हुई थी। इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का निर्माण मार्च 2006 को जैक डोर्सी, नूह ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स ने मिलकर किया था। 32 करोड़ सक्रिय यूजर्स हैं। 3800 कर्मचारियों वाली इस वेबसाइट को अलेक्सा रैंकिंग में 11वां पायदान हासिल है।

शहीद ब्रिगेडियर उस्मान से खौफ खाता था पाकिस्तान

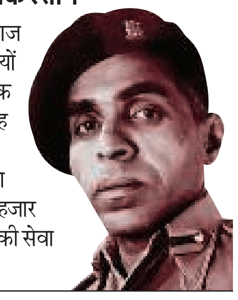

शहीद ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान का जन्म 1912 में आज ही यूपी के आजमगढ़ में हुआ था। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने 25 दिसंबर 1947 को जम्मू-कश्मीर के झंगड़ नामक इलाके को कब्जे में ले लिया था। लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से मार्च 1948 को नौशेरा और झंगड़ फिर भारत के कब्जे में आ गए। अपनी नेतृत्व क्षमता की वजह से ही उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। इस घटना के बाद पाकिस्तानी सरकार ने उन पर पचास हजार का इनाम रखा था। 3 जुलाई 1948 को झंगड़ में ही मोर्चे पर देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए।

इधर-उधर की

घर खाली छोड़ने पर लगा करोड़ों का जुर्माना

ओटावा, एजेंसी : कनाडा में एक अजीब वाकया सामने आया है। वैंकूवर प्रशासन ने चीनी अरबपति की पत्नी पर घर खरीदने के बाद उसमें न रहने के चलते 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। उसने यह घर 143 करोड़ रुपये में खरीदा था। दरअसल, वैंकूवर प्रशासन ने 2018 में एम्प्टी होम टैक्स लागू किया था। इसके मुताबिक खाली रखे गए घरों पर कुल कीमत का एक फीसद जुर्माने के तौर पर देना होगा। 2015 में हे यिजु ने बेलमोंट एवेन्यू इलाके में ओशन व्यू वाला घर खरीदा था। उनके पति जेन झियांग चीन की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस में नेता हैं। फोर्ब्स के मुताबिक दंपती की कुल नेटवर्थ 6475 करोड़ रुपये है। यिजु ने नोटिस के खिलाफ ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके बताया है कि घर भले ही खाली रहा हो, पर उसके पुनर्निर्माण का काम चलता रहा है।

छात्रों के लिए हानिकारक है स्कूल का कठोर अनुशासन

- अमेरिका की बॉलिंग ग्रीन स्टेट और ईस्टर्न केंटुकी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन
- मस्तिष्क में पड़ता है नकारात्मक प्रभाव, किशोरावस्था छात्र में ही पकड़ लेते हैं गलत राह

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : अक्सर देखा जाता है कि स्कूल से निलंबित हुए छात्र किशोरावस्था में गलत राह पकड़ लेते हैं और जो उनके भविष्य को गर्त में धकेल देती है। अब अमेरिकी शोधकर्ताओं ने भी एक अध्ययन में चिंता जताते हुए कहा है कि स्कूलों में छात्रों के लिए कठोर अनुशासन हानिकार सिद्ध हो सकता है। कई बार स्थिति ऐसी भी बन जाती है कि अनुशासन का पालन न करने वाले छात्रों को स्कूल से निलंबित तक कर दिया जाता है।

शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसा करने पर छात्र और ज्यादा गलत कामों को करना शुरू कर देते हैं। शिक्षकों का यह रुख किशोरावस्था में ही बच्चों के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हो जाता है। इससे छात्रों में तमाम तरह की नकारात्मकताएं घर कर जाती हैं और वह अपराध की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। इसी का परिणाम है कि आपके आस-पड़ोस में हमले, चोरी और ड्रग्स बेचने जैसे अपराध अधिक होना शुरू हो जाते हैं।

यह अध्ययन बॉलिंग ग्रीन स्टेट और ईस्टर्न केंटुकी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है, जो 'जस्टिस क्वार्टरली' में प्रकाशित हुआ है। इसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि स्कूल से निलंबित होने के बाद छात्रों में अपराध की प्रवृत्ति कम होने की बजाए बढ़ जाती है।

बॉलिंग ग्रीन स्टेट में समाजशास्त्र के

'जस्टिस क्वार्टरली' में प्रकाशित हुआ है शोध।

एसिस्टेंट प्रोफेसर थॉमस जेम्स मोवेन ने कहा कि स्कूलों में अनुशासनात्मक रणनीति को तेज करने से ज्यादा नुकसान हो सकता है। कुछ लोग इसे 'स्कूल अनुशासन के लिए अपराधीकरण' भी कहते हैं। इससे आपके आस-पड़ोस, स्कूल और समुदायों में आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग बढ़ सकते हैं।

मोवेन ने कहा कि उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ अध्ययन कर यह पता लगाया कि मिडिल और हाई स्कूल से निलंबित किए जाने पर छात्रों के व्यवहार और जीवन में क्या बदलाव आते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी पता लगाया कि क्या स्कूल से निष्कासित होना युवावस्था में लोगों के दुर्व्यवहार का कारण बन जाता है?

अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि स्कूलों में अनुशासनात्मक रणनीति को तेज करने से छात्र ज्यादा हिंसक और आपराधिक प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं और उम्र बढ़ने के साथ-साथ उनकी प्रवृत्ति और ज्यादा हिंसक हो जाती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि इससे बचने का एक उपाय यह भी हो सकता है कि छात्रों की काउंसिलिंग कराई जाए और उनकी मनःस्थिति को समझने के बाद ही उन्हें दिशा-निर्देश दिए जाएं। शोधकर्ताओं ने कहा कि इस काम में शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

रूस ने अंतरिक्ष में स्थापित किया 'स्पेक्टर-आरजी'

रूसी अंतरिक्ष यान कजाकिस्तान के बाइकोनुर कोस्मोड्रोम से लांच किया गया। रायटर

मास्को, आइएएनएस : रूसी वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन-एम प्रक्षेपण यान के जरिये अंतरिक्ष वेधशाला 'स्पेक्टर-आरजी' को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। रूसी सरकारी अंतरिक्ष संघ रॉसकॉसमॉस ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी शिंहुआ ने बयान के हवाले से कहा कि अंतरिक्ष यान कजाकिस्तान में बाइकोनुर कोस्मोड्रोम से लांच किया गया। यह इस प्रकार के लांच व्हीकल का वर्ष 2019 में दूसरा लांच है। बयान में कहा गया है कि, दो विशेष एक्स-रे मिरर दूरबीनों से लैस कक्षीय वेधशाला ने एक्स-रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए अपनी 100 दिवसीय उड़ान शुरू कर दी है।

स्पेक्ट्रम

- आकाशगंगा और ब्लैक होल्स का पता लगाकर वेधशाला बनाएगी नक्शा

रॉसकॉसमॉस के अनुसार, स्पेक्टर-आरजी एक रूसी परियोजना है, जिसमें जर्मनी ने सहयोग किया है। इसका मुख्य लक्ष्य आकाशगंगाओं के लगभग एक लाख बड़े समूहों और 30 लाख विशालकाय 'ब्लैक होल्स' का पता लगाकर पूरे आकाश का नक्शा बनाना है।

नासा के वैज्ञानिकों ने मार्स रोवर में इंस्टाल किए पहिये और पैर

लॉस एंजलिस, आइएएनएस : नासा के इंजीनियरों ने वर्ष 2020 में शुरू होने वाले अपने मंगल मिशन के लिए तैयार किए जा रहे रोवर में पहिये और पैरों को इंस्टाल कर दिया है, जो रोवर को मंगल ग्रह पर घूमने में मदद करेंगे। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (जेपीएल) ने यह जानकारी दी है।

शिंहुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, जेपीएल में स्पेसक्राफ्ट एसेंबली फैसिलिटी के क्लीन रूम में एक दर्जन से ज्यादा इंजीनियरों ने रोवर में पहियों और पैरों को इंस्टॉल किया। इसके लिए इंजीनियरों की टीम ने 'रॉकर-बोगी' सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो रोवर को संतुलित रखने में मदद करेगा। छह पहियों की मदद से रोवर मंगल ग्रह पर आसानी चल फिर सकेगा। जेपीएल ने कहा कि 52.5 सेंटीमीटर व्यास वाले ये पहिये इंजीनियरिंग मॉडल के

अगले वर्ष उड़ान भरेगा नासा का यान। फाइल

अद्भुत नमूने हैं। यह मॉडल फ्लाइट मॉडल के पहियों की जगह लेंगे। इसके हर पहिये में एक मोटर लगी हुई है। आगे और पीछे के पहियों में अलग-अलग स्टीयरिंग मोटर भी लगाई गई हैं, जो रोवर को 360 डिग्री मुड़ने में सक्षम बनाती हैं। रोवर को जुलाई 2020 तक प्रक्षेपित किया जाएगा। 1,000 किलोग्राम से अधिक वजन वाला रोवर मंगल ग्रह पर किसी दौर में मौजूद रहे सूक्ष्मजीवों के चिह्नों की तलाश कर करेगा और वहां की जलवायु एवं भू-तत्वों की विशेषता का पता लगाएगा।

हकीकत से अभी दूर हैं क्वांटम कंप्यूटर

करना होगा इंतजार ▶ अगले 10 वर्षों तक इनके बाजार में आने के आसार नहीं

पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं भविष्य के कंप्यूटर, जारी हैं वैज्ञानिकों के अध्ययन

लिंडाउ (जर्मनी) : प्रेट्र : कंप्यूटर की दुनिया का भविष्य माने जाने वाले सुपरफास्ट 'क्वांटम कंप्यूटर' का इंतजार सभी को है। क्योंकि 'क्वांटम मैकेनिक्स' से लैस ये कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटरों के मुकाबले कई गुना तेजी से समस्याओं को सुलझा सकते हैं, लेकिन जर्मनी के नोबेल पुरस्कार विजेता क्लाउस वॉन क्लिटिंग सहित कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 10 वर्षों तक भी बाजार में 'क्वांटम कंप्यूटर' उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। हालांकि, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन कंप्यूटरों का विकास होने से विज्ञान के क्षेत्र में शोधकर्ताओं को अभूतपूर्व सफलता हाथ लग सकती है। इनकी मदद से जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण के साथ-साथ बीमारियों का भी तेजी से निदान किया जाएगा।

'इंटिजर क्वांटम हॉल इफेक्ट' की खोज के लिए 1985 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले 76 वर्षीय क्लिटिंग ने कहा कि क्वांटम कंप्यूटर जब भी बाजारों में उपलब्ध होंगे, वे अनुसंधान और उद्योगों में ज्यादातर प्रयुक्त होने वाले पारंपरिक प्रणालियों (कंप्यूटरों) को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे। 69वें 'लिंडाउ नोबेल लैक्चरेट मीटिंग' में उन्होंने कहा 'मुझे नहीं लगता कि अगले दस वर्षों तक भी क्वांटम कंप्यूटर लांच हो पाएंगे। यदि ये लांच हो भी गए तो आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।'

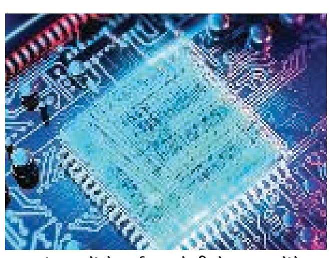

आम कंप्यूटरों से कई गुना तेजी से काम करेंगे क्वांटम कंप्यूटर। प्रतीकात्मक

अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्डस एंड टेक्नोलॉजी (एनआइएसटी) की एलिना जॉर्डन ने कहा कि वह क्लिटिंग से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर क्वांटम कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटरों से कई बेहतर काम करेंगे, लेकिन निकट भविष्य में ये कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तक इन्हें पूरी तरह तैयार नहीं किया जा सका है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, बोल्डर की शोधकर्ता जॉर्डन ने कहा कि कुछ छोटे क्वांटम कंप्यूटरों की कार्यप्रणाली को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनकी क्या क्षमता हो सकती है, लेकिन ज्यादातर शोधकर्ता अभी भी इसके सिग्नल गेट और 'स्पीड' (गति) पर काम कर रहे हैं ताकि ये और बेहतर तरीके से काम कर सकें। उन्होंने कहा कि अभी सभी प्रोग्रामों से लैस सुपरफास्ट क्वांटम कंप्यूटरों का सपना साकार होना दूर की कौड़ी है। जॉर्डन ने उम्मीद जताई है कि अध्ययनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले 'कंप्यूटर सिमुलेशन' के क्षेत्र में क्वांटम कंप्यूटर अभूतपूर्व बदलाव लाएंगे, क्योंकि आम कंप्यूटरों में सिमुलेशन के जरिये अध्ययन के परिणाम निकालने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

क्या होंगे फायदे : ऑस्ट्रिया के इंस्टीट्यूट फॉर क्वांटम ऑप्टिक्स एंड क्वांटम इन्फॉर्मेशन के मनोज के जोशी ने कहा कि 'क्वांटम कंप्यूटर' नए विचारों और सिद्धांतों से लैस होंगे। नए सिद्धांतों के आधार पर नई सामग्री, दवाओं या उपकरणों का निर्माण किया जा सकता है। यह तकनीकी प्रगति और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे और साधारण क्वांटम कंप्यूटर प्रयोगशालों से बाहर आने को तैयार हैं पर पूरी तरह स्वचालित और मशीनरी से लैस कंप्यूटरों के लिए अभी आपको कुछ इंतजार करना होगा। आइएमबी क्यू, डीवेव, गूगल एएआइ जैसी कई कंपनियां इन्हें बनाने के लिए प्रयासरत हैं।

आम कंप्यूटर से है अलग : कंप्यूटर में कैलकुलेशन के लिए बिट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डेटा को जीरो और एक की फॉर्म में रखा जाता है। इसका प्रयोग मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए तैयार किया जाता है तो उसे मशीनी भाषा में कंवर्ट किया जाता है और प्रोसेसर जब किसी सॉफ्टवेयर को कैच करता है तो इसी मशीनी भाषा का इस्तेमाल करके सभी प्रोसेस पूरे किए जाते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में परमाणु (एटम) से कैलकुलेशन की जा सकती है।

ऐसे करता है काम : परमाणु प्राकृतिक रूप से घूमता रहता है। यह या तो ऊपर की घूमेगा या नीचे की ओर। अगर डिजिटल तकनीक के हिसाब से देखें तो प्रत्येक चीज को शून्य (जीरो) और एक की फॉर्म में रखा जाता है। यानी परमाणु का ऊपर जाने वाला चक्रण एक हो सकता है और नीचे आने वाला चक्रण शून्य (जीरो) हो सकता है, लेकिन अगर इस चक्रण का मापन किया जाए तो यह एक ही समय में ऊपर या नीचे दोनों तरफ हो सकता है। इसी वजह से यह पारंपरिक कंप्यूटर के बिट के बराबर नहीं होता। इसीलिए इसे क्यूबिट्स कहा जाता है, जिसे क्वांटम बिट्स भी कहा जाता है। क्यूबिट्स बिट्स के मुकाबले काफी अलग होता है। बिट्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है वह या तो शून्य में हो सकती है या एक की फॉर्म में हो सकती है लेकिन क्यूबिट्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है वह एक ही बार में शन्यू और एक दोनों ही फॉर्म में हो सकती है, जिसे कंप्यूटेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है।

शोध अनुसंधान

प्रदूषण से बढ़ जाता है फेफड़े की बीमारी का खतरा

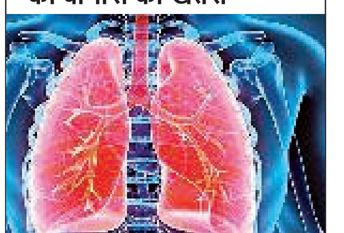

वायु प्रदूषण दुनियाभर में एक गंभीर संकट की तरह सामने आया है। एक अध्ययन में पाया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण फेफड़े की क्षमता प्रभावित होती है और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इससे क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज (सीओपीडी) का खतरा बढ़ने की बात सामने आई है। लंबे समय तक फेफड़े की क्षमता प्रभावित रहने से व्यक्ति सीओपीडी का शिकार हो जाता है। इसमें व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है। अगले 10 साल में इससे जान गंवाने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उम्र बढ़ने से धीरे-धीरे फेफड़े की क्षमता कम होती जाती है। प्रदूषण इस प्रक्रिया को तेज कर देता और व्यक्ति के फेफड़े समय से पहले ही काम करने में अक्षम होने लगते हैं। - एएनआइ

सहानुभूति से भी मिलती है एड्स के इलाज में मदद

हालिया अध्ययन में सामने आया है कि अगर एड्स के मरीजों को सहानुभूति और बिना शर्त देखभाल मिले तो इलाज का असर बढ़ जाता है। विज्ञान पत्रिका 'जोएना ब्रिग्स इंस्टीट्यूट डाटाबेस ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यूज' में प्रकाशित शोध में कहा गया है कि मरीजों को अपनी बीमारी को समझने के लिए सहयोग की जरूरत पड़ती है। अध्ययनकर्ता एंड्रिया नोरबर्ग ने कहा, 'एचआइवी गंभीर बीमारी है लेकिन इसका इलाज संभव है। बहुत से मरीजों को लगता है कि एड्स का मतलब मौत। इस डर के साथ जो मरीज बेहतर इलाज नहीं ले रहे हैं, उनके पास पहुंचना बड़ी चुनौती है।' इस अध्ययन को अंजाम देने के लिए 1997 से 2017 के बीच प्रकाशित हुए 41 अध्ययनों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि अगर मरीज और उसकी देखभाल करने वाले के बीच संवाद सही ना हो, तो नुकसान हो सकता है। - एएनआइ

जर्मनी में क्वीन डे पर हुई परेड

जर्मनी के विट्जनहाउजेन शहर में 'क्वीन दिवस' पर आयोजित परेड में महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनकर शामिल होती हैं। रानी के सम्मान में इस दिन देशभर में समारोह का आयोजन किया जाता है। महिलाएं रानी जैसी पोशाक पहनती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। पारंपरिक ड्रेस में नौकायन भी समारोह का प्रमुख आकर्षण है। एपी

गीत का मनाया जाता है उत्सव

ब्रिटेन की कैट बुश दुनिया की इकलौती गायिका व संगीतकार हैं, जिनके सुप्रसिद्ध गीत 'वुथरिंग हाइट्स' पर प्रतिवर्ष कई देशों में बाकायदा उत्सव मनाया जाता है। बर्लिन में हजारों संगीत प्रेमी मोस्ट वुथरिंग हाइट्स डे एवर पर जश्न मनाते हैं। महिला व पुरुष कैट बुश की पोशाक पहनकर उनके गीत पर डांस करते हैं। कैट ने 1978 में महज 19 वर्ष की उम्र में 'वुथरिंग हाइट्स' यह गाना रिकार्ड किया। उनके पहले ही गीत को यूके सिंगल्स चार्ट में शीर्ष स्थान मिल गया। इस तरह वह यूके नंबर हासिल करने वाली पहली महिला आर्टिस्ट बन गईं। इसके बाद से प्रतिवर्ष समारोह होता है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

स्क्रिप्ट लिखने से पहले फिल्म का नामकरण जरूरी : सुजॉय घोष

सात सवाल

'अलादीन', 'कहानी', 'कहानी 2' 'दुर्गा रानी सिंह' व 'बदला' फिल्मों के निर्देशक सुजॉय घोष ने अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का रुख किया है। नेटफ्लिक्स पर 19 जुलाई से शुरू होने वाली वेब सीरीज 'टाइपराइटर' का निर्देशन उन्होंने किया है। सुजॉय से बातचीत :

वेब सीरीज बनाने की योजना कब से थी?

- मैं वेब सीरीज नहीं, फिल्म बनाने की तैयारी में था। कहानी ऐसी थी कि बच्चे उसके हीरो होंगे। वे दुनिया की रक्षा करेंगे। मैंने नेटफ्लिक्स से फिल्म बनाने के लिए संपर्क किया। उन्होंने कहा कि इसकी सीरीज बेहतर बन सकती है। मुझे लगा कि शायद उनकी बात में दम है।

लेखन में किस प्रकार का बदलाव करना पड़ा?

- मुझे एपिसोड लिखने थे। मैंने एक एपिसोड लिखकर नेटफ्लिक्स को यह जानने के लिए भेजा कि मैं सही राह पर हूं या नहीं। वेब शो लिखने के लिए फिल्म लेखन को भूलना पड़ा। उन्हें पसंद आया तो मेरी इसके लेखन में दिलचस्पी जागी। टीवी में लेखन को लेकर कई मानक होते हैं। डिजिटल के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं है। यह भी लेखन में मददगार रहा।

शो का नाम शुरुआत से ही 'टाइपराइटर' था?

- बिल्कुल। मैं कोई भी स्क्रिट लिखने से पहले उसका नाम रखता हूं। वरना मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। अगर किसी का नाम न हो तो उसकी पहचान क्या होगी? 'बदला' भी मैं तभी लिख पाया, जब मुझे उसका नाम मिला।

थ्रिलर व हॉरर को टीवी, फिल्म और वेब सभी जगह एक्सप्लोर किया जा रहा है। क्या इस जॉनर में ज्यादा पोटेंशियल है?

- पोटेंशियल सिर्फ कहानी में होता है। अगर कहानी दमदार हो तो हर जॉनर में पसंद की जाएगी। उसमें एक लक्ष्य होना चाहिए कि दर्शक कुर्सी से चिपके रहें। दर्शक किसी फिल्म के लिए अपने दो घंटे दे रहे हैं तो कहानी ऐसी हो कि इंसान टस से मस न हो।

'टाइपराइटर' की कहानी गोवा में सेट है। आपकी ज्यादातर फिल्में कोलकाता में सेट रही हैं। ऐसे में गोवा को कितना एक्सप्लोर कर पाए?

- गोवा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। थोड़ा-बहुत पहले गोवा को पर्यटक के तौर पर देखा था। वहां की जीवनशैली से ज्यादा परिचित नहीं था। लिखने के दौरान लगा कि कहानी गोवा के माकूल ही है। लिहाजा गोवा की जीवनशैली और वहां की लोकेशन की रेकी की। शो की कहानी में सब लोग कुछ अंधेरे में तलाश रहे हैं। उसके मुताबिक चीजें तलाशते गए। सब हो गया।

जीशु सेनगुप्ता के साथ पहली बार काम कर रहे हैं?

- कहानी लिखते समय मुझे एहसास था कि अमित राय के किरदार में जीशु सेनगुप्ता ही फिट होंगे। वह उसे जीवंत बनाने का माद्दा रखते हैं। शो की शूटिंग से एक दिन पहले ही उन्हें हमने बताया और उन्होंने स्वीकृति दे दी।

पूरब कोहली को पुलिस अधिकारी के किरदार में कास्ट करने के बारे में कैसे सोचा?

- असल जिंदगी में भी पूरब पिता है। शो में वह सिंगल फादर के रोल में हैं। जब बेटी बड़ी हो रही होती है तो पिता चिंतित होता है। शो में पिता-पुत्री के बीच दोस्ती का रिश्ता है। वह उसमें दिखा भी है।

स्मिता श्रीवास्तव

अध्ययन

ग्लोबल वॉर्मिंग से पुरातात्विक स्थलों को खतरा

ग्रीनलैंड की बर्फ में मौजूद हैं 2500 ईसा पूर्व के कई जैविक अवशेष, गर्मी बढ़ने के कारण लगातार हो रहे हैं विघटित

- आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद हैं 1,80,000 से ज्यादा पुरातात्विक स्थल
- विज्ञान पत्रिका 'नेचर' में प्रकाशित हुआ है अध्ययन

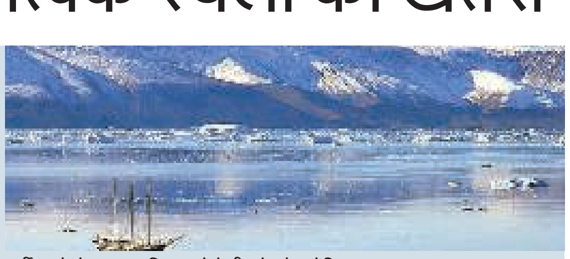

गर्मी बढ़ने से लगातार पिघल रहे हैं ग्रीनलैंड के ग्लेशियर। फाइल

कोपेहेगन, एएफपी : जलवायु परिवर्तन से न केवल ग्रीनलैंड का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है, बल्कि इससे वहां के पुरातात्विक स्थलों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हाल में ही प्रकाशित हुए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है। बता दें कि पूरे आर्कटिक क्षेत्र में 1,80,000 से ज्यादा पुरातात्विक स्थल मौजूद हैं, जो हजार वर्षों से यहां की मिट्टी में मौजूद विशेष गुणों के कारण संरक्षित हैं।

विज्ञान पत्रिका 'नेचर' में प्रकाशित हुए अध्ययन में बताया गया है कि इन क्षेत्रों के घटने का सीधा संबंध मिट्टी के ताप, नमी की मात्रा, हवा के बढ़ते तापमान और बारिश के मौसम में बदलाव से है, जिससे पुरातात्विक लकड़ी, हड्डी और प्राचीन डीएनए जैसे कार्बनिक तत्वों को नुकसान हो सकता है। शोधकर्ताओं की टीम का नेतृत्व करने वाले जॉर्गेन होलेसेन ने इस अध्ययन के लिए वर्ष 2016 से आर्कटिक क्षेत्र की सात अलग-अलग साइटों की गहन पड़ताल की है। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां कार्बनिक तत्व, जैसे- बाल, पंख, शंख-सीप और मांस के टुकड़ों के अलावा कुछ साइटों में वाइकिंग बस्तियों के खंडहर भी मौजूद हैं।

अगले 80 वर्षों में गायब हो जाएंगे पुरातात्विक तत्व : होलेसेन ने कहा कि अध्ययन में किए गए अनुमान गर्मी के विभिन्न परिदृश्यों पर आधारित हैं। जो यह बताते हैं कि इन इलाकों में औसत तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे मिट्टी का तापमान बढ़ेगा और कार्बनिक परतों के भीतर सूक्ष्मजीवों के पनपने से गतिविधियां भी बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि अध्ययन से पता चलता है कि आगामी 80 वर्षों के भीतर जैविक कार्बन (ओसी) के पुरातात्विक अंश 30 से 70 फीसद तक गायब हो सकते हैं। होलेसेन ने कहा कि इसका मतलब है कि ये कार्बनिक अवशेष खतरे में हैं। इनमें कई अवशेष ऐसे भी हैं जो लगभग 2,500 ईसा पूर्व के लोगों से संबंधित हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि जब उन्होंने इन साइटों के निष्कर्ष की तुलना पिछले सर्वेक्षणों के साथ की तो पाया कि ये इलाके लगातार कम होते जा रहे हैं।

बारिश से कम हो जाता है विघटन : होलेसेन ने कहा कि कुछ साइटों पर हमें एक भी पुरातात्विक जैविक तत्व नहीं मिला। इसका मतलब है कि पिछले दशकों में वे विघटित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सूक्ष्मजीव इन अवशेषों को विघटित कर देते हैं, लेकिन यदि वर्षा बढ़ जाती है, तो उनकी गतिविधि धीमी हो जाती है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि यदि समय-समय पर बारिश हो और जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव कम हो तो ग्रीनलैंड के पुरातात्विक जैविक तत्वों को क्षीण होने में ज्यादा समय लगेगा।

'द गर्ल ऑन द ट्रेन' में दिखेगा परिणीति का अलग रूप

परिणीति चोपड़ा फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' के लिए कमर कस चुकी हैं। अपने किरदार के लिए उन्हें मेकओवर की जरूरत पड़ेगी और बालों का रंग बदलना होगा। परिणीति ने इंस्टाग्राम पर एक हेयर सैलून की तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वह मेकओवर कराती नजर आ रही हैं। परिणीति ने लिखा, 'बालों का रंग बदला जा रहा है। 'गर्ल ऑन द ट्रेन' का समय आ गया है।' उन्होंने यह भी बताया कि इन दिनों वह बहुत व्यस्त हैं और उन्हें घर भी बदलना है। उन्होंने लिखा, '3 हफ्ते बचे हैं 'जबरिया जोड़ी' को रिलीज होने में और 'गर्ल ऑन द ट्रेन' की शूटिंग शुरू होने में। 'साइना नेहवाल' के लिए प्रशिक्षण भी चल रहा है, क्योंकि 'गर्ल ऑन द ट्रेन' के बाद उसकी शूटिंग करनी है। इस हफ्ते घर भी बदलूंगी। 'जबरिया जोड़ी' का प्रोमोशन, 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' की तैयारी, घर शिफ्ट, सब कामों के लिए 3 हफ्ते।' 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' पाउला हॉकिंस की किताब पर आधारित है, जिस पर हॉलीवुड में फिल्म बनचुकी है, जिसमें एमिली ब्लंट द्वारा निभाया गया मुख्य किरदार परिणीति कर रही हैं।

वेब सीरीज में नीना गुप्ता के साथ नजर आएंगी उनकी बेटी मसाबा

बॉलीवुड की वरिष्ठ अभिनेत्री नीना गुप्ता बॉलीवुड में फिर से सक्रिय हो चुकी हैं और एक के बाद एक फिल्मों में नजर आ रही हैं। अब उन्होंने अपना रुख वेब सीरीज की ओर भी कर लिया है और जल्द ही वह एक अनूठी कहानी वाली वेब सीरीज में नजर आने वाली हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि नीना के साथ उनकी बेटी मसाबा भी इस वेब सीरीज में नजर आएंगी। पिछले दस वर्षों से फैशन की दुनिया में सक्रिय मसाबा लोकप्रिय फैशन डिजाइनर हैं। इसके साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रहती है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज में उनका किरदार भी डिजाइनर के जीवन से प्रेरित है। इस प्रोजेक्ट की निर्देशक सोनम नायर हैं, जबकि इसके प्रोड्यूसर अश्विनी यार्डी है। सूत्रों के अनुसार, 'मसाबा और अश्विनी को कई अवसरों पर साथ देखा जा चुका है। अब खबर आई है कि दोनों ने एक शो को फाइनल किया है। इस वेब सीरीज की कहानी मसाबा के जीवन से मिलती-जुलती होगी।' नीना इस शो में भी मसाबा की मां की भूमिका में नजर आएंगी। दोनों को शो का कॉन्सेप्ट भी पसंद आया है।